चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित

08 जुलाई–14 जुलाई 2013

दंगे होने वाले हैं

सभी फोटो : प्रभात पाण्डे

देश में जिस तरह का राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है, उससे साफ़ लगता है कि दंगे होने वाले हैं. देश का मीडिया, राजनीतिक दल और राजनेता इस देश में दंगे कराने पर आमादा हैं. दंगे कराने वालों में सांप्रदायिक ताकतों के साथ- साथ वे कथित सेकुलर ताकतें भी हैं, जिनकी निगाह उस 19 फ़ीसद वोटों पर है, जिन्हें वे बड़ी बेशर्मी से मुस्लिम वोटबैंक कहती हैं. कोई चेहरा दिखाकर मुसलमानों को डरा रहा है, तो कोई हमदर्द होने का दिखावा करके. हैरानी इस बात की है कि मुसलमानों के वोटों के लिए तो सब लड़ रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए लड़ने वाला कोई भी नहीं है. मुसलमानों की समस्याएं ख़त्म करने के लिए न तो किसी के पास ठोस नीति है और न ही इरादा. सभी राजनीतिक दलों की एकमात्र रणनीति है, मुसलमानों के साथ फरेब करना. राजनीति के ऐसे फरेबी माहौल में मुसलमानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे क्या करें और कहां जाएं?

भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी एवं जनता दल यूनाइटेड बिहार और उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने वाली राजनीति पर आमादा हैं. इन सभी पार्टियों के नेताओं को लगता है कि 2014 में उनके प्रधानमंत्री बनने का सुनहरा अवसर है. इन पार्टियों को यह भी लगता है कि जितना ज़्यादा ध्रुवीकरण होगा, उन्हें उतना ही फ़ायदा मिलेगा. इसलिए यह कहा जा सकता है कि चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ये पार्टियां किसी भी हद तक जा सकती हैं.

मनीष कुमार

सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं. भाजपा ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान कमेटी का मुखिया बना दिया. इससे साफ़-साफ़ एक संकेत मिलता है कि वह लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ेगी. आडवाणी ने मोदी का विरोध किया, लेकिन भाजपा टस से मस नहीं हुई. उन्होंने पार्टी के सभी दायित्वों से इस्तीफ़ा भी दे दिया, पर उसका भी असर नहीं हुआ. भाजपा के दर्जनों नेता मोदी के ख़िलाफ़ हो गए, फिर भी आरएसएस ने अपना फ़ैसला नहीं बदला. मोदी के लिए भाजपा बिहार सरकार से बाहर हो गई और मंत्रियों को कुर्सी से हाथ धोना पड़ा, लेकिन फिर भी मोदी बने रहे. भाजपा को अपने सबसे भरोसेमंद साथी जदयू से रिश्ता तोड़ना पड़ गया, बावजूद इसके फ़ैसले पर कोई असर नहीं हुआ. अब जबकि नरेंद्र मोदी पर पार्टी इतना बड़ा दांव खेल रही है, तो इसका मतलब साफ़ है कि संघ परिवार किसी रणनीति पर काम कर रहा है और उस रणनीति के विरोध में जो भी खड़ा होगा, उसे दरकिनार कर दिया जाएगा. अब समझते हैं कि मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के मायने क्या हैं.

नरेंद्र मोदी चाहे विकास की बात करें या फिर भविष्य के भारत का कोई हसीन सपना दिखाएं, लेकिन उनके सामने आते ही चुनाव का ध्रुवीकरण होना निश्चित है. यह बात भाजपा और संघ परिवार के रणनीतिकारों को अच्छी तरह मालूम है. इसके बावजूद, भाजपा ने अपने सबसे बड़े नेता के रूप में मोदी को सामने रखकर यह साफ़ कर दिया कि वह 2014 में हिंदू-मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण चाहती है. दरअसल, भाजपा को यही लगता है कि जितना ज़्यादा ध्रुवीकरण होगा, उसे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा. इसलिए इस रणनीति के तहत ही मोदी के हाथों चुनाव की कमान सौंप दी गई है. ऐसी रणनीति पर चुनाव लड़ने का मतलब यही है कि देश में भाईचारा ख़त्म हो जाए, दंगे हो जाएं या फिर लोगों की जानें चली जाएं, पर चुनाव जीतने के लिए ध्रुवीकरण करना ही एकमात्र रास्ता है. मोदी अब तक विकास की बातें करते आए हैं और इस रणनीति की पुष्टि उन्होंने पठानकोट में कर ही दी. मोदी ने चुनावी अभियान की शुरुआत पठानकोट से की. यहां उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू एवं धारा 370 ख़त्म करने की बात करके यह स्पष्ट कर दिया कि सद्भावना मिशन सिर्फ़ मुसलमानों को बहलाने के लिए है, जबकि उनका असली एजेंडा कुछ और ही है.

दूसरी तरफ़, अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का जमावड़ा शुरू हो गया. बीते 12 जून को विश्व हिंदू परिषद की कोर कमेटी, यानी केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की यहां बैठक हुई. विश्व हिंदू परिषद ने यह ऐलान किया कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए वह 25 अगस्त से यात्रा शुरू करेगी, जो 19 दिनों की होगी और यह अयोध्या से सटे बस्ती से शुरू होकर 13 सितंबर को अयोध्या में ही ख़त्म होगी. यात्रा के दौरान यूपीए सरकार से यह मांग की जाएगी कि वह संसद में क़ानून बनाकर विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण कराए. और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, तो 18 अक्टूबर को विश्व हिंदू परिषद अयोध्या में साधु-संतों का एक महाकुंभ आयोजित करेगी. ग़ौर करने वाली बात यह है कि यह मामला अदालत में है और ऐसे में सरकार से इस तरह की मांग करने का मतलब साफ़ है कि सरकार क़ानून पास नहीं कर सकती है. दूसरा ख़तरनाक पहलू यह है कि यह यात्रा बस्ती से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में जाएगी, जो न सिर्फ़ संवेदनशील हैं, बल्कि जहां मुसलमानों की संख्या काफी ज़्यादा है. आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग ख़तरे से खेलना चाहते हैं, क्योंकि यहां की एक चिंगारी पूरे देश में आग लगा सकती है. इतने सालों तक सोए रहने के बाद, चुनाव से ठीक पहले इस तरह का कार्यक्रम तय करने का मतलब साफ़ है कि भाजपा ने विश्व हिंदू परिषद के कंधे पर बंदूक रखकर माहौल को सांप्रदायिक बनाने की पूरी तैयारी कर ली है. भाजपा इस चुनाव के दौरान राम जन्मभूमि, धारा 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुद्दा बनाने वाली है. दरअसल, ये ऐसे मुद्दे हैं, जो न सिर्फ़ मुस्लिम विरोधी हैं, बल्कि एक तरह से यह देश की एकता एवं अखंडता ख़तरे में डालने वाला डायनामाइट है. सच तो यह है कि ऐसे मुद्दों से न केवल भावनाएं भड़क सकती हैं, बल्कि दंगे भी हो सकते हैं.

चुनाव का ध्रुवीकरण करने और भावनाओं को भड़काने में कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है. फ़र्क़ सिर्फ़ इतना है कि भाजपा मोदी को आगे करके ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है और कांग्रेस एवं तमाम दूसरी सेकुलर पार्टियां संघ परिवार का खौफ दिखाकर. कांग्रेस के प्रवक्ता एवं नेता और कांग्रेस द्वारा नियंत्रित मीडिया मोदी के नाम का इतना बड़ा हौव्वा बना रही है कि जैसे देश में मोदी के अलावा, कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है. कांग्रेस ने 2014 का चुनाव एक साल पहले से ही मोदी केंद्रित कर दिया है. कांग्रेस ने मोदी के हर बयान का जवाब देना अपना परम कर्तव्य समझ लिया है. मोदी जो करते हैं उसके बारे में या तो टिप्पणी आती है या फिर उसी काम में पूरी कांग्रेस लग जाती है. प्राकृतिक आपदा के बाद मोदी उत्तराखंड गए. पहले तो उन्हें रोककर कांग्रेस

(शेष पृष्ठ 2 पर)

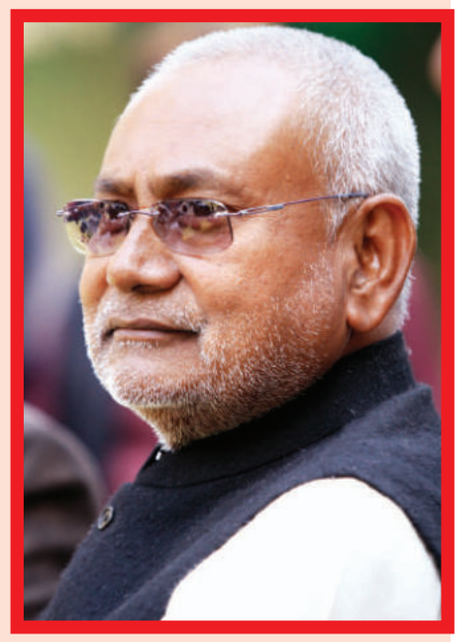

नीतीश कुमार ने भाजपा से अब रिश्ता तोड़ लिया है. ऊपर से देखने में यह फ़ैसला धर्मनिरपेक्ष राजनीति का एक उदाहरण ज़रूर लगता है, लेकिन इससे जो भविष्य की रेखा खिंचती है, वह बिहार में सांप्रदायिकता को मजबूत करने वाली है. जैसे कि पहले मोदी बिहार में चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाते थे, अब वह आराम से बिहार का दौरा कर सकेंगे.

ए एम यू कोर्ट में महिलाएं नज़रअंदाज़ क्यों

03

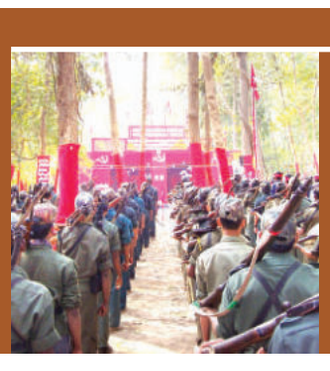

समस्या की जड़ में भी राजनीतिक तंत्र ही है

04

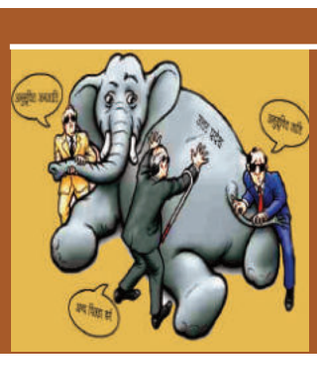

पिछड़े हैं, तो क्या ग़म है!

07

साई की महिमा

12

दंगे होने वाले हैं

पृष्ठ एक का शेष

ने बेवजह विवाद खड़ा किया और फिर अपने तीन-तीन मंत्रियों को उत्तराखंड भेज दिया. मोदी दो दिन उत्तराखंड में रहे, तो राहुल गांधी भी दो दिन उत्तराखंड में लोगों से मिलते रहे. मोदी के बारे में कोई ख़बर छप जाती है, तो कांग्रेस के मंत्री फौरन उसका जवाब देने के लिए मीडिया में पहुंच जाते हैं. कहने का मतलब यह कि जितना मोदी स्वयं अपना प्रचार करते हैं, उससे ज़्यादा उनका प्रचार कांग्रेस कर रही है. ऐसा इसलिए, क्योंकि कांग्रेस के रणनीतिकारों को लगता है कि मोदी के आगे आने से उन्हें फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मुसलमानों के पास कांग्रेस के सिवाय कोई और दूसरा विकल्प नहीं है.

सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ़ मोदी का विरोध करने मात्र से कांग्रेस का दायित्व ख़त्म हो जाता है? क्या देश में सेकुलरिज्म के मायने सिर्फ़ मोदी विरोध तक ही सीमित है? भाजपा मुसलमानों को लुभाने के लिए उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास का एक रोडमैप लेकर सामने आ गई, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? क्या मुसलमानों को फिर से आरक्षण का लालीपॉप दिखाकर धोखा दिया जाएगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ था? विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस ने हद ही कर दी. पहले उर्दू अख़बारों और अन्य मीडिया के जरिए अल्पसंख्यक आरक्षण को मुस्लिम आरक्षण बताकर मुसलमानों को ठगने की कोशिश की गई. जब यह चोरी पकड़ी गई, तो सलमान खुर्शीद ने मुसलमानों को 9 फ़ीसद आरक्षण देने का वादा कर दिया, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी का चुनाव घोषणापत्र सामने आया, तो मुसलमानों के संदर्भ में लिखी गई बातें उर्दू और अंग्रेजी में अलग-अलग थीं. यह किस तरह की राजनीति है? क्या कांग्रेस को लगता है कि हर बार की तरह इस बार भी झूठे वादे करके वह मुसलमानों को ठगने में कामयाब हो जाएगी? जैसा कि अब तक का इतिहास रहा है, उससे तो यही लगता है कि कांग्रेस फिर मुसलमानों के लिए आरक्षण एवं किसी पैकेज का झूठा ऐलान करके उनके वोट लेने की तैयारी में लगी हुई है. ऐसी राजनीति का नतीजा यह होता है कि मुसलमानों के हाथ लगता कुछ भी नहीं है, उल्टे मुस्लिम तुष्टिकरण के विरोध में ध्रुवीकरण ज़रूर हो जाता है. शायद कांग्रेस भी यही चाहती है. लगता है, कांग्रेस झूठे वादे करके, अफवाहें फैलाकर, डरा-धमका कर और मोदी का खौफ दिखाकर ध्रुवीकरण की रणनीति को अंजाम देने में लगी हुई है, ताकि मुसलमानों के 19 फ़ीसद वोट उसे बैठे-बिठाए मिल जाएं. कांग्रेस भी इस इंतज़ार में बैठी है कि माहौल में सांप्रदायिकता का ज़हर घुले, ताकि वह इसका चुनावी फ़ायदा उठा सके.

लालू प्रसाद यादव

लेकिन कांग्रेस की रणनीति में एक बहुत बड़ी त्रुटि है. मुसलमान या मोदी विरोधियों का वोट उसी उम्मीदवार को मिलेगा, जो भाजपा के उम्मीदवार को हराने में सबसे ज़्यादा सक्षम होगा. चूंकि यह चुनाव मोदी के समर्थन और विरोध के बीच एक लड़ाई है, इसलिए मोदी विरोधी कोई जोखिम नहीं उठाएंगे. इस बार स्ट्रैटजिक वोटिंग के साथ इंटेलिजेंट वोटिंग भी होगी. यही सोच मुलायम सिंह यादव की है. उन्हें लगता है कि मोदी के आगे आने से लोकसभा चुनाव के सारे मुद्दे ख़त्म हो जाएंगे और अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता को मुद्दा बनाएंगे तथा भाजपा को हराने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ आ जाएंगे. कहने का मतलब यह है कि जितना ज़्यादा ध्रुवीकरण होगा, समाजवादी पार्टी को उतना ही फ़ायदा होगा. उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार मोदी के वहां आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, क्योंकि मोदी ही उसकी जीत की कुंजी हैं. आने वाले समय में समाजवादी पार्टी मोदी एवं विश्व हिंदू परिषद को कोहराम मचाने के लिए न केवल छूट देगी, बल्कि जमकर विरोध भी करेगी. मतलब यह कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता का ज़हर घोलेगी, तो कांग्रेस एवं समाजवादी पार्टी आग में घी डालने का काम करेंगी.

मायावती

सभी फोटो : प्रभात पाण्डे

ऐसी ही रणनीति का उदाहरण नीतीश कुमार हैं. नीतीश कुमार की राजनीति को मुसलमानों ने फिर से 30 साल पीछे धकेल दिया है और भाजपा को सांप्रदायिक राजनीति करने की पूरी छूट दे दी. बिहार में नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन था, सरकार चल रही थी. दोनों ने मिलजुल कर कई चुनाव भी लड़े. बिहार में पहली बार मुसलमानों ने खुलकर भाजपा को वोट दिया. भाजपा के टिकट से मुस्लिम उम्मीदवार भी चुनाव जीतकर आए. नीतीश कुमार एवं सुशील मोदी ने अपनी सूझबूझ से सांप्रदायिकता को राज्य से दूर ही रखा. उनकी गठबंधन सरकार के दौरान भागलपुर के दंगों के दोषियों को सजा भी मिली. चुनाव में भाजपा ने विवादित मुद्दे कभी नहीं उठाए और न ही नरेंद्र मोदी को बिहार में पैर जमाने का कोई मौक़ा दिया. जब-जब चुनाव हुए, नरेंद्र मोदी को बिहार आने से रोका गया. इसमें जितना रोल नीतीश कुमार का था, उतना ही सुशील मोदी का भी था. मुसलमान विकास एवं सुशासन के नाम पर बिना खौफ वोट करते रहे.

रामविलास पासवान

नीतीश कुमार ने भाजपा से अब रिश्ता तोड़ लिया है. ऊपर से देखने में यह फ़ैसला धर्मनिरपेक्ष राजनीति का एक उदाहरण ज़रूर लगता है, लेकिन इससे जो भविष्य की रेखा खिंचती है, वह बिहार में सांप्रदायिकता को मजबूत करने वाली है. जैसे कि पहले मोदी बिहार में चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाते थे, अब वह आराम से बिहार का दौरा कर सकेंगे. पहले भाजपा विवादित मुद्दे उठाने से बचती थी, अब वह ऐसे सारे मुद्दे उठा सकेगी, जो विवादित और समाज को बांटने वाले हैं. नीतीश कुमार के फ़ैसले के पीछे भी चुनावी राजनीति का समीकरण है. बिहार में 15 सालों तक लालू यादव का वर्चस्व रहा. वह चुनाव नहीं हारते थे, क्योंकि उनकी जीत का फॉर्मूला यादवों एवं मुसलमानों के वोटों का गठजोड़ था. लेकिन जबसे मुसलमानों ने लालू यादव को वोट देना बंद कर दिया, तबसे वह बिहार की सत्ता से बाहर हो गए. मुसलमानों ने लालू यादव को इसलिए वोट देना बंद किया, क्योंकि 15 सालों में उनकी सरकार ने मुसलमानों के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया. मुसलमानों को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, इसलिए उन्होंने जदयू-भाजपा गठबंधन का साथ दिया. नीतीश का भाजपा से अलग होने का फ़ैसला वैचारिक मतभेद से ज़्यादा चुनावी समीकरण का नतीजा है. नीतीश जानते हैं कि बिहार में लालू यादव को कमजोर करके ही सत्ता में कायम रहा जा सकता है. जिस दिन मुसलमान वापस लालू के साथ हो गए, उसी दिन उनकी सत्ता की नींव कमजोर हो जाएगी. इसलिए हर चुनाव से पहले वह मोदी का विरोध करके मुसलमानों का दिल जीतने में कामयाब रहे. इसलिए जैसे ही भाजपा ने मोदी के नाम की घोषणा की, वैसे ही उन्होंने उससे रिश्ता तोड़ लिया. इससे नीतीश को चुनाव में कितना फ़ायदा होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन उनका फ़ैसला उसी रणनीति का नतीजा है, जिस पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी काम कर रही है.

दरअसल, भारतीय राजनीति विचारशून्य हो गई है. सेकुलरिज्म का मतलब सिर्फ़ अल्पसंख्यकों के वोट धोखे से हासिल कर लेना भर रह गया है. केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, बिहार में नीतीश और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की. ये सब दिन-रात सेकुलरिज्म की दुहाई देते हैं, लेकिन इनमें से किसकी सरकार ने ग़रीब अल्पसंख्यकों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए कोई समग्र योजना तैयार की है? किसने उन्हें निरक्षरता के अंधेरे से बाहर निकालने की कोशिश की? हर किसी ने मुसलमानों के साथ धोखा किया. सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने मुसलमानों के पिछड़ेपन की हकीकत बता दी. रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट ने कई सारे सुझाव दिए. तीन-चार साल से यह रिपोर्ट सरकार की आलमारी में सड़ रही है और किसी सेकुलर पार्टी को इसकी सुध लेने की फुर्सत भी नहीं है. बाकी जिन समस्याओं से देश गुजर रहा है, उनका तो मुसलमानों पर असर पड़ ही रहा है, लेकिन जिस तरह की आर्थिक नीति देश में लागू की जा रही है, उससे मुसलमान अलग से परेशान हो रहे हैं. किसी सेकुलर पार्टी ने अब तक इस बात पर क्यों ध्यान नहीं दिया कि उदारवाद की आर्थिक नीति की वजह से सबसे ज़्यादा मुसलमान पिसे हैं, सबसे ज़्यादा मुसलमान बेरोजगार हुए हैं. बाज़ार में चीनी सामान आने से सबसे ज़्यादा मुसलमान कारीगर परेशान हैं, एफडीआई की वजह से सबसे ज़्यादा मुसलमानों का व्यवसाय चौपट होगा. कहने का मतलब यह है कि देश के राजनीतिक दलों ने सेकुलरिज्म का मतलब केवल मुसलमानों से वोट लेना समझ लिया है. झूठे वादे करके मुसलमानों को धोखा देना ही सेकुलरिज्म का सही अर्थ लगा लिया गया है. चुनाव आते ही राजनीतिक दलों को मुसलमानों का आरक्षण याद आता है. बोलियां लगने लगती हैं. कोई 5 फ़ीसद, तो कोई 9 फ़ीसद, तो कोई 19 फ़ीसद आरक्षण की बात करता है और जब चुनाव हो जाते हैं, तो सब कुछ जीरो हो जाता है.

भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी एवं जनता दल यूनाइटेड बिहार और उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने वाली राजनीति पर आमादा हैं. इन सभी पार्टियों के नेताओं को लगता है कि 2014 में उनके प्रधानमंत्री बनने का सुनहरा अवसर है. इन पार्टियों को यह भी लगता है कि जितना ज़्यादा ध्रुवीकरण होगा, उन्हें उतना ही फ़ायदा मिलेगा. इसलिए यह कहा जा सकता है कि चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ये पार्टियां किसी भी हद तक जा सकती हैं. कोई डरा-धमका कर, विवादित भाषण देकर, तो कई मीठा जहर घोलकर वोटरों को बांटने की कोशिश करेगा. इनके अलावा, और भी कई पार्टियां हैं, जो इस दौड़ में थोड़ी पीछे ज़रूर नज़र आ रही हैं, लेकिन वे चुनाव के दौरान कैटेलिस्ट का काम करेंगी, जैसे लालू यादव का राष्ट्रीय जनता दल, रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी. ये पार्टियां भी सेकुलर राजनीति की दुहाई देकर वोटरों को बांटने की कोशिश करेंगी. जब इतनी सारी पार्टियां एक साथ एक मकसद पर काम करेंगी, तो नतीजा क्या निकलेगा, यह बिल्कुल साफ़ है. इसलिए हमें यह मानकर चलना चाहिए कि दंगे होने वाले हैं. ■

manish@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 05 अंक 18
दिल्ली, 08 जुलाई-14 जुलाई 2013
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
प्रथम तल, विराट कॉम्प्लेक्स के पीछे, सरदार पटेल पथ, कृष्णा अपार्टमेंट के नज़दीक, बोरिंग रोड, पटना-800013
फोन : 0612 2570092, 9431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे-3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ-226001
फोन : 0522-2204678, 9415005111

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999
6450888
6452888
011-23418962
विज्ञापन व प्रसार +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

सीबीआई और आईबी में सुलह

सीबीआई ने आख़िरकार आईबी के विशेष निदेशक राजिंदर कुमार से इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले पर पूछताछ को लेकर दोनों एजेंसियों के बीच पैदा हुआ गतिरोध ख़त्म करने में सफलता हासिल कर ली. इससे पहले कभी इन दोनों एजेंसियों में ऐसी तल्खी देखने को नहीं मिली थी. सूत्रों का कहना है कि जब सीबीआई ने इशरत मामले को लेना चाहा, तो आईबी ने उसे रोकने का प्रयास किया. आईबी ऐसा करके दरअसल, अपने वरिष्ठ अधिकारी को बचाना चाहती थी. सूत्रों का कहना है कि जनता तक यह बात पहुंचने के डर से इस मामले को सुलझाने के लिए सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा और आईबी प्रमुख आसिफ इब्राहिम गृह सचिव से मिले. इस बैठक में भूतपूर्व सीबीआई निदेशक ए पी सिंह ने भी भाग लिया. दो प्रमुख एजेंसियों के प्रमुखों के बीच सब कुछ पहले जैसा करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन को भी हस्तक्षेप करना पड़ा. इसके बाद यह तय हुआ कि उक्त आईबी अधिकारी से सिर्फ़ पूछताछ की जाएगी, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. ग़ौरतलब है कि सीबीआई ने पहले उन्हें गिरफ्तार करने की बात कही थी. ■

नौकरशाहों पर नकेल

सरकार सार्वजनिक तौर पर यह दावा करती रहती है कि वह अधिकारियों से अपने कर्तव्यों का पालन स्वतंत्रता एवं निर्भीकता के साथ करने के लिए कहती है. गंभीर चिंता का विषय यह है कि इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिनमें अधिकारी अपनी शिकायतें किसी खास चैनल के माध्यम से अपने वरिष्ठों के पास नहीं पहुंचाते. यह बेहद शर्मनाक है. ताजा मामला हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका का है. अशोक खेमका और उनके समकक्ष अन्य अधिकारी अपनी शिकायतों को लेकर अक्सर मंत्रियों, यहां तक कि प्रधानमंत्री को सीधे पत्र लिखते थे. इस पर संज्ञान लेते हुए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 60 वर्ष पुराना सर्कुलर फिर से जारी किया है, ताकि इस तरह की आदतों पर भविष्य में रोक लग सके. कार्मिक विभाग के सचिव पी के मिश्रा ने इन बाबुओं को चेतावनी दी है कि वे अपने वरिष्ठ अधिकारियों या कार्यालय प्रमुखों को पत्र लिखें और अनुशासन का परिचय दें. अब देखने की बात यह है कि कितने बाबू इस आदेश का पालन करते हैं. ■

मोइली का सख्त आदेश

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री एम वीरप्पा मोइली का कहना है कि उनका विभाग अपने काम पर नज़र बनाए हुए है. ग़ौरतलब है कि पिछले दिनों उनके यह कहने पर कि मंत्रालय को तेल आयात लॉबी से धमकियां मिल रही हैं, राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई थी. अब मोइली ने उन अधिकारियों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई का मन बना लिया है, जिनकी वजह से मंत्रालय के निर्णयों में देरी हुई. ग़ौरतलब है कि अधिकारियों द्वारा विलंब से निर्णय लेने के कारण सही समय पर न तो तेल की खोज हो पाई और न ही उत्पादन हो पाया, जिसके चलते कई बिलियन डॉलर का नुक़सान हुआ. सूत्रों का कहना है कि इनमें से कुछ निर्णयों का 2011 से ही इंतज़ार है. मोइली ने अपने सचिव विवेक रे को निर्देश दिया है कि सारे मामलों को एक महीने में निपटाया जाए. उन्होंने कहा कि जो अधिकारी इसमें असफल होगा, उसके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. कुछ अधिकारी मंत्रालय में ज़्यादा दिनों से नहीं हैं, फिर भी उनका तबादला किया जा रहा है. इनमें से बहुत सारे मामले ऐसे भी हैं, जो मुंबई कॉरपोरेट जगत से संबंधित हैं और विवादों के मुख्य केंद्र भी. ■

dilipcherian@gmail.com

साउथ ब्लॉक

सुजाता होंगी नई विदेश सचिव

चौथी दुनिया ब्यूरो

1976 बैच की आईएएस अधिकारी सुजाता सिंह अगली विदेश सचिव होंगी. सुजाता इस समय जर्मनी में भारत की राजदूत हैं. वह भारतीय विदेश सेवा में सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं. वह राजन मथाई का स्थान लेंगी.

मोहिंदर संयुक्त सचिव बने

1988 बैच के आईडीएस अधिकारी मोहिंदर सिंह को सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम की ज़िम्मेदारी दी गई है. वह यहां संयुक्त सचिव या फिर उसके समकक्ष पद संभालेंगे.

विमल, आलोक, प्रदीप और श्यामल सचिव बनेंगे

1979 बैच एवं मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी विमल जुल्का को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया जाएगा. वह 1976 बैच एवं मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी उदय कुमार का स्थान लेंगे. जुल्का वर्तमान में विदेश मंत्रालय में विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, दोनों पदों की ज़िम्मेदारी संभाल रहे हैं. इसी तरह 1979 बैच एवं पश्चिम बंगाल कैडर के आईएएस अधिकारी आलोक रावत को जल संसाधन मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया जाएगा. वह 1979 बैच एवं पश्चिम बंगाल कैडर के अधिकारी श्यामल कुमार सरकार का स्थान लेंगे. रावत इस समय केंद्रीय सचिवालय में बतौर सचिव (पीजी एंड को-ऑर्डिनेशन) कार्यरत हैं. इसी प्रकार 1977 बैच एवं उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार सिन्हा को ऊर्जा मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया जाएगा. वह 1976 बैच एवं उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी पी उमाशंकर का स्थान लेंगे. प्रदीप इस समय जहाजरानी मंत्रालय में बतौर सचिव कार्यरत हैं. वहीं 1979 बैच एवं पश्चिम बंगाल कैडर के आईएएस अधिकारी श्यामल कुमार सरकार को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में सचिव नियुक्त किया जाएगा. वह 1976 बैच एवं उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार मिश्रा का स्थान लेंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

एएमयू गर्ल्स हाई स्कूल

“इस सच्चाई को भला कैसे झुठलाया जा सकता है कि 1920 में जब इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, तो इसकी प्रथम कुलपति भोपाल की नवाब सुल्तान जहां बेगम बनीं. सर सैयद द्वारा स्थापित ए एम ओ कॉलेज में 21 सालों बाद ही मुस्लिम एजुकेशनल कांफ्रेंस में लड़कियों की शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का एक सेक्शन बनाया गया और न्यायाधीश करामत हुसैन इसके सचिव बने और नवाब मोहसिन उलमलिक, साहबज़ादा आफताब अहमद ख़ां, सुल्तान अहमद और हाजी इस्माइल ख़ां ने इसका खुलकर सहयोग किया.”

स्ट्रेची हॉल

ए एम यू कोर्ट में महिलाएं नज़रअंदाज़ क्यों

1920 में विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने पर जिस शिक्षण संस्थान की पहली कुलपति एक महिला रही हो, उसके डिसीज़न मेकिंग बॉडी ए एम यू कोर्ट में लगभग 200 सदस्यों में एक भी महिला निर्वाचित सदस्य का न होना आश्चर्य का विषय है. हद तो तब हो गई, जब हाल ही में इस संस्था में 42 नये सदस्यों की घोषणा हुई, लेकिन उनमें भी महिलाएं नदारद हैं. ए एम यू कोर्ट में महिलाओं को नज़रअंदाज़ किए जाने पर भारतीय महिलाओं में कड़ी नाराज़गी लाजिमी है.

ए यू आसिफ़

यह कैसी विडंबना है कि जिस शिक्षण संस्थान में कभी महिला कल्याण के मसीहा ठाकुर दास (शेख़ अब्दुल्ला उर्फ पापा मियां) जैसे महान व्यक्ति रहे हों, जो आज भी कैंपस में स्थित अब्दुल्ला कॉलेज और अब्दुल्ला छात्रावास का अटूट हिस्सा बना हुआ हो, यहां तक कि 1920 में विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने पर जिसकी पहली कुलपति एक महिला रही हो, उसके डिसीज़न मेकिंग बॉडी ए एम यू कोर्ट में लगभग 200 सदस्यों में एक भी महिला निर्वाचित सदस्य नहीं है? गौरतलब है कि हाल ही में बड़ी ही धूमधाम से इस संस्था में 42 नये सदस्यों की घोषणा हुई, उनमें भी महिलाएं नदारद हैं. ए एम यू कोर्ट में महिलाओं को नज़रअंदाज़ किए जाने पर भारतीय महिलाओं में कड़ी नाराज़गी है, जिसका अनुमान कुछ प्रतिष्ठित महिलाओं की प्रतिक्रिया से लगाया जा सकता है.

1857 में सर सैयद अहमद ख़ां के द्वारा अलीगढ़ में मदरसतुल उलूम मुसलमनाने हिन्द के नाम से स्थापित किया गया शिक्षण संस्थान, जो कि बाद में मोहम्डन एंगलो ओरिएंटल कॉलेज (ए एम ओ कॉलेज) बन गया और 1920 में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने के बाद यह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहलाया. वर्तमान में इसके अलीगढ़ में असल कैंपस के अलावा मलापुरम (केरल) और मुर्शिदाबाद (पश्चिमी बंगाल) में चल रहे दो ऑफ कैंपस सेंटर्स क़ायम हैं और किशनगंज (बिहार) और औरंगाबाद (महाराष्ट्र) में दो और सेंटर्स बनाने की तैयारी चल रही है. इसमें कोई शक नहीं कि यह भारतीय मुसलमानों का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान है. यह देश में मुसलमानों की शिक्षा का प्रतीक भी समझा जाता है. यहां से पिछले 138 सालों में कई लाख छात्र–छात्राएं शिक्षा प्राप्त करने के बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. आरंभ में बच्चों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन कश्मीर के रहने वाले मेहता गुरमुख सिंह के बेटे ठाकुर दास, जो 1891 में मुस्लिम बन जाने के बाद शेख़ अब्दुल्ला उर्फ पापा मियां (1874–1965) बन गए और स्वयं 1920 से लेकर 1965 तक ए एम यू कोर्ट के सदस्य रहे. इनकी सर सैयद से निकटता और लड़कियों की शिक्षा में गहरी रुचि के कारण इस संस्थान से छात्राएं ख़ूब लाभान्वित हुईं और इनका सशक्तिकरण हुआ.

इस सच्चाई को भला कैसे झुठलाया जा सकता है कि 1920 में जब इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, तो इसकी प्रथम कुलपति भोपाल की नवाब सुल्तान जहां बेगम बनीं. सर सैयद द्वारा स्थापित ए एम ओ कॉलेज में 21 सालों बाद ही मुस्लिम एजुकेशनल कांफ्रेंस में लड़कियों की शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का एक सेक्शन बनाया गया और न्यायाधीश करामत हुसैन इसके सचिव बने और नवाब मोहसिन उलमलिक, साहबज़ादा आफताब अहमद ख़ां, सुल्तान अहमद और हाजी इस्माइल ख़ां ने इसका खुलकर सहयोग किया. इसके बाद उम्मीद अली, गुलाम सकलैन और हाजी इस्माइल ख़ां व अन्य लोगों ने इस ज़माने में लड़कियों की शिक्षा पर उठाए गए सवालों का इस समय के अख़बार अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजेट में लेख और पत्र लिखकर करारा जवाब दिया. इसके बाद कहीं जाकर 1899 में कलकत्ता में मुस्लिम एजुकेशनल कांफ्रेंस के वार्षिक सम्मेलन में देश के विभिन्न स्थानों पर लड़कियों के लिए स्कूल खोलने का क्रांतिकारी निर्णय लिया गया और साथ ही यह भी तय किया गया कि लड़कियों के प्रस्तावित स्कूलों के कोर्स की तैयारी में उलेमा से मशविरा किया जाए और इसी के साथ–साथ कोर्स में साइंस और सोशल साइंस जैसे आधुनिक विषय भी शामिल किए जाएंगे. फिर दिसंबर 1902 के दिल्ली सम्मेलन में सर आग़ा ख़ां की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन के दौरान पापा मियां को महिलाओं की शिक्षा के प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए सचिव बनाया गया.

इसी ज़माने में नवंबर 1903 में अलीगढ़ मंथली विशेष अंक महिलाओं की शिक्षा पर प्रकाशित हुआ, जिसमें सैयद गुलाम नीरंग, सैयद सज्जाद हैदर यलदरम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलवी मोहम्मद अख़्तर जैसी हस्तियों के लेख इसमें प्रकाशित हुए. इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पापा मियां ने अलीगढ़ से ख़ातून से एक पत्रिका प्रकाशित की और इसके बाद फैमियल एजुकेशन एसोसिएशन स्थापित की गई, जो आज भी सक्रिय है. यह पत्रिका 1914 तक महिलाओं की शिक्षा की अगुवाई करती रही.

हालांकि पापा मियां यूनाईटेड प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गर्वनर के पास एक प्रतिनिधि मंडल को लेकर गए और अलीगढ़ में गर्ल्स स्कूल खोलने की अनुमति मांगी. इसी दौरान उन्होंने भोपाल की नवाब बेगम सुल्तान जहां के पास भी एक प्रस्ताव भेजा. तब जाकर इसके लिए बेगम की ओर से 100 रुपये मासिक आर्थिक सहयोग की स्वीकृति मिली. इस प्रकार 19 अक्टूबर, 1906 को दो रुपये महीना किराये के एक मकान में 5 लड़कियों और एक शिक्षिका से गर्ल्स स्कूल खुला. इस काम में पापा मियां को इनकी पत्नी वहीद जहां उर्फ आला बी से बहुत सहयोग मिला. बाद में यह स्कूल लोकप्रिय होने पर अलीगढ़ शहर के इसराईलियान में स्थानांतरित हो गया. 1929 में यह स्कूल इंटरमीडियट कॉलेज और 1930 में शेख़ इलजामिया सर रास मसूद के दौर में वुमेन कॉलेज बनकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़कर इसका हिस्सा बन गया. पापा मियां की दो बेटियां इसकी प्रिंसिपल रहीं और इनका परिवार इसका महत्वपूर्ण हिस्सा रहा.

एएमयू के इस ऐतिहासिक स्कूल और वुमेन कॉलेज ने अनगिनत योग्य महिलाएं देश को दीं, जिनमें पापा मियां की चार बेटियां, ख़ातून जहां, मुमताज़ जहां हैदर, ख़ुर्शीद जहां और बरजेस जहां के अलावा प्रसिद्ध कहानीकार असमत चुग़ताई और सलमा सिद्दिकी, प्रसिद्ध कलाकार ज़रीना हशमी, पाकिस्तानी अदाकारा नीर सुलताना, हिन्दी व संस्कृत स्कॉलर कुसुम अंसल, पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की पत्नी बेगम आबिदा अहमद, वर्तमान उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी की पत्नी सलमा अंसारी और इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज़ बंगलौर की फेलो डाक्टर कुदसिया तहसीन के नाम उल्लेखनीय हैं.

अब सवाल यह है कि भारतीय मुस्लिमों के केन्द्रीय शिक्षण संस्थान से महिलाओं को जिस मेहनत, परेशानियां और कुरबानियां देकर हमारे बुजुर्गों ने जोड़ा, आज किस षडयंत्र के तहत इस निर्णायक संस्था से इन्हें अलग रखा जा रहा है? ज्ञात रहे कि लगभग 200 सदस्यों में केवल 6 पदेन महिलाएं हैं, जो ए एम यू की स्टाफ़ हैं. इन 6 महिलाओं में ए एम यू गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल आमिना मलिक, वुमेन कॉलेज की प्रिंसिपल बिल्क़ीस नसीम वारिस, पैथोलोजी विभाग की अध्यक्ष वीना महेश्वरी, बॉयो टेक्नोलॉजी विभाग की अध्यक्ष कोसर जहां ख़्वाजा और साइंस विभाग की डीन अरोणिमा लाला हैं. इन 6 पदेन महिलाओं के अलावा, एएमयू कोर्ट में फिलहाल एक भी महिला सदस्य नहीं है.

लिहाज़ा, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विजिट्र भी हैं, की जिम्मेदारी बनती है कि यूनिवर्सिटी की निर्णायक संस्थान ए एम यू कोर्ट में चयनित महिला सदस्यों की संख्या को निश्चित करने के लिए आवश्यक क़दम उठाएं. ऐसे समय में जब संसद में 33 प्रतिशत महिला कोटे की चर्चा की जा रही है, तो ए एम यू कोर्ट में महिलाओं का आनुपातिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य है.

ममदूहा माजिद

अब सवाल यह है कि भारतीय मुस्लिमों के केन्द्रीय शिक्षण संस्थान से महिलाओं को जिस मेहनत, परेशानियां और कुरबानियां देकर हमारे बुजुर्गों ने जोड़ा, आज किस षडयंत्र के तहत इस निर्णायक संस्था से इन्हें अलग रखा जा रहा है? ज्ञात रहे कि लगभग 200 सदस्यों में केवल 6 पदेन महिलाएं हैं, जो ए एम यू की स्टाफ़ हैं.

डॉक्टर हसीना हाशिया

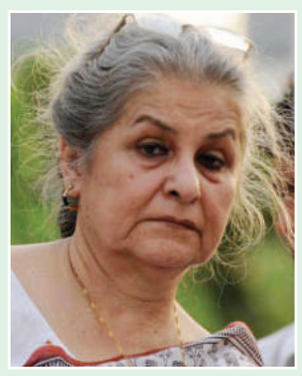
सैयदा सयदैन हमीद

महिलाओं की नाराज़गी

पापा मियां के आन्दोलन के तहत स्थापित हुई फेमियल एजुकेशन एसोसिएशन की वर्तमान सचिव प्रोफेसर ए. ज़किया सिद्दीक़ी, जो कि अब्दुल्ला कॉलेज की प्रिंसिपल और एएमयू कोर्ट की पदेन सदस्य हैं, फिलहाल मानव संसाधन मंत्रालय के तहत बनी गर्ल्स एजुकेशन कमेटी की अध्यक्ष हैं. ए एम यू कोर्ट में फिलहाल चयनित महिला सदस्यों के न होने को दुखद बताती हैं और इसलिए पुरुषवादी मानसिकता को जिम्मेदार मानती हैं. उनका मानना है कि ऐसा नहीं है कि योग्य महिलाओं की कमी है. वह कहती हैं कि जब ओल्ड ब्वॉयज़ का एएमयू कोर्ट में प्रतिनिधित्व है, तो आख़िर महिलाएं चयनित सदस्यों में मौजूद क्यों नहीं हैं? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से दस साल पहले रिटायर हुईं ज़किया सिद्दीक़ी ए एम यू कोर्ट में कम से कम 10 प्रतिशत महिलाओं के प्रतिनिधित्व की मांग कर रही हैं.

योजना आयोग की सदस्य सैयदा सयदैन हमीद अपनी नाराज़गी जताते हुए कहती हैं कि जब कोर्ट के नए 42 सदस्यों की सूची देखी, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ. उनका कहना है कि प्रथम चांसलर के रूप में शुरुआत तो एक महिला ने कर दी, लेकिन इसके बाद एक भी महिला कभी कुलपति या उप कुलपति नहीं बन पाई. उनके अनुसार, यह मामला पक्षपाती मानसिकता का है और इसीलिए अब इसे बदलने की आवश्यकता है. सैयदा हमीद, जो कि ख़्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की नवासी भी हैं, का कहना है कि ख़्वाजा हाली और मौलाना आज़ाद ने इस मानसिकता के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थीं. उनके अनुसार, सर सैयद ने ख़ुद कोई पहल नहीं की, लेकिन पापा मियां ने इस संबंध में बहुत प्रयास किए और ए एम यू को गर्ल्स स्कूल और गर्ल्स कॉलेज बना दिया. इनका यह भी कहना है कि जब वह योजना आयोग में ज्वाइन करने से पहले सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत कोटे की अन्य लोगों के साथ मांग कर रही थीं, तब यह सवाल किया जाता था कि कहां हैं योग्य महिलाएं. जिनके लिए यह कोटा मांगा जा रहा है. तब हमारा जवाब होता था कि महिलाएं पुरुषों के साथ–साथ खड़ी हैं और योग्यता में किसी से कम नहीं हैं. आज मेरा सवाल है कि क्या ए एम यू कोर्ट में शामिल करने के लिए उन्हें शिक्षित और योग्य महिलाएं नहीं मिल रही हैं? सच तो यह है कि ऐसी हज़ारों महिलाएं हैं, जो योग्य हैं और उन्हें संस्था में शामिल किया जाना चाहिए. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की सदस्य डॉक्टर उस्मा ज़हरा, जो हैदराबाद की प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, कहती हैं कि अगर हर जगह कोटे की बात होती है, तो ए एम यू कोर्ट में महिलाओं के लिए कोटा होना चाहिए. उनका कहना है कि जब महिलाओं ने संघर्ष करके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में अपना लोहा मनवा लिया है, तो वे यहां भी लोहा मनवा सकती हैं. उनके अनुसार, इसके लिए केवल पुरुषों के वर्चस्व को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इसके लिए कई और फैक्टर भी जिम्मेदार हैं. उनका यह भी कहना है कि समस्या केवल ए एम यू कोर्ट की ही नहीं है, बल्कि सभी विभागों और संस्थाओं में भी प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है.

एएमयू की पूर्व छात्रा रह चुकीं डॉक्टर हसीना हाशिया, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सदस्य भी हैं और जामिया मिलिया इस्लामिया के भूगोल विभाग में प्रोफेसर भी, को ए एम यू कोर्ट के इस प्रक्रिया पर बेहद आश्चर्य है कि फिलहाल उतने बड़ी निर्णायक संस्था में कोई भी चयनित महिला सदस्य नहीं है. इसे दुर्भाग्य बताते हुए वह कहती हैं कि महिला शिक्षा का आन्दोलन यहीं से शुरू हुआ, लेकिन यह क्या कि वहीं के महत्वपूर्ण संस्थानों में महिलाओं को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है. उनका कहना है कि मैं ही नहीं, एएमयू से पढ़ी हर छात्रा, बल्कि जो देश या विदेश में कहीं भी रहती हैं, वह यही चाहेंगी कि महिलाओं का इसमें भरपूर प्रतिनिधित्व हो. अपनी बात पर ज़ोर देते हुए वह आगे कहती हैं कि ए एम यू की ऐसी निर्णायक संस्था, जिस पर पूरी दुनिया की नज़र है, को चाहिए कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व करे और उन्हें आगे बढ़ाए. यह उसके लिए मर्दों की पुरुषवादी मानसिकता के साथ–साथ ए एम यू के जिम्मेदार लोगों और महिला संगठनों, सभी को दोषी मानती हैं. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक और सदस्य और ऑल इंडिया रेडियो में 1973 से लेकर 2004 तक अनुवादक और अनाउंसर रह चुकीं ममदूहा माजिद, जो उड़ीसा से हैं, का कहना है कि ए एम यू कोर्ट में औरतों के उचित प्रतिनिधित्व के लिए इसी प्रकार संघर्ष करना पड़ेगा, जिस प्रकार बोर्ड में संघर्ष किया गया और वहां महिला सदस्यों की संख्या पहले से अधिक हुई. यह भी उसके लिए पुरुषवादी मानसिकता को जिम्मेदार मानती हैं और ए एम यू कोर्ट में महिलाओं के कोटे की मांग पर ज़ोर देती हैं. ■

प्रोफेसर ए. ज़किया सिद्दीक़ी

डॉ. अस्मा ज़ेहरा

feedback@chauthiduniya.com

> अब जरा सरकारों द्वारा बनाए गए क़ानून पर भी नज़र डालिए. 1996 में पेसा एक्ट आया, जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को अनूसूचित क्षेत्र तक विस्तारित किया गया. 15 साल बीत गए, लेकिन अभी तक 9 में से सिर्फ़ तीन राज्यों ने ही इस संबंध में क़ानून बनाए हैं.

माओवाद

समस्या की जड़ में भी राजनीतिक तंत्र ही है

अगर आप माओवाद को सामाजिक-आर्थिक समस्या मानते हैं, तो आपको एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है. सवाल यह उठता है कि किसी सूबे का गृहमंत्री ऐसा क्यों चाहता है कि उसके सूबे के ज़्यादा से ज़्यादा जिले नक्सल प्रभावित घोषित हों? माओवादियों की मूल लड़ाई की जड़ में जल, जंगल, ज़मीन, खनिज हैं. तो फिर मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था इन संसाधनों की लूट की छूट कॉरपोरेट हाउसेज को देकर इन इलाकों में रहने वाले लोगों को क्या संदेश देना चाहती है? आख़िर लोकसभा और विधानसभा के आगे ग्रामसभा क्यों बेबस और लाचार हो जाती है? माओवादियों, जो इसी देश के वासी हैं, को अपने ही प्रतिनिधियों, यानी नेताओं पर विश्वास क्यों नहीं रहा?

शशि शेखर

आम तौर पर माओवाद को एक सोशियो-इकोनॉमिक (सामाजिक-आर्थिक) समस्या माना जाता है, लेकिन जब आप इस समस्या के पनपने के कारणों की जड़ में जाएंगे, तो पता चलेगा कि यह समस्या भी भारत की बाकी समस्याओं जैसी ही है. इसका कारण भी वही है, यानी सत्ता, शासन एवं व्यवस्था पर राजनीतिक दलों द्वारा पूर्ण कब्जा बनाए रखने की मानसिकता. केंद्रीयकृत सत्ता, शासन एवं व्यवस्था की वजह से इस देश में आज भ्रष्टाचार है, प्राकृतिक संसाधनों की खुली लूट मची हुई है. दरअसल, यही वह वजह है, जो माओवाद की जड़ को खाद-पानी मुहैया कराती है.

जाहिर है, संविधान की मूल भावना (जिसमें राजनीतिक दल का जिक्र नहीं है) के विपरीत यह देश आज राजनीतिक दलों के चंगुल में फंस चुका है. जनप्रतिनिधि आज जनता के नहीं, बल्कि अपनी पार्टियों के प्रतिनिधि बन चुके हैं और इसीलिए उन्हें जनता की समस्याओं से कोई मतलब ही नहीं रह गया है. लोकतंत्र पर इन राजनीतिक दलों द्वारा कब्जा जमाने और विकेंद्रीकरण के नाम पर शासन व्यवस्था को केंद्रीयकृत बना देने की वजह से भी आज इस देश में माओवाद की समस्या है. इस सबकी जगह अगर सत्ता सचमुच गांवों एवं आम आदमी के हाथ में होती, तो वे सारी वजहें पैदा ही न होतीं, जिनके चलते माओवाद जैसी समस्या जन्म लेती है. अगर सचमुच जनप्रतिनिधित्व, यानी जनता की भागीदारी (आम आदमी की भागीदारी) ग्रामसभा से लेकर विधानसभा एवं लोकसभा तक होती, तो आज यह समस्या ही न होती.

एक उदाहरण लेते हैं. अकेले छत्तीसगढ़ में तीस से ज़्यादा थर्मल पावर अभी स्थापित किए जाने हैं, जिनमें जिंदल से लेकर भूषण, बाल्को, एस्सार एवं जीएमआर आदि शामिल हैं. इनके अलावा, खनन कार्य में लगी कंपनियों को भी शामिल किया जा सकता है. सवाल यह है कि इस सबके लिए इन कंपनियों को आवश्यक जल एवं ज़मीन राज्य और केंद्र सरकार मिलकर मुहैया कराती हैं, तब क्या उसमें स्थानीय लोगों की भी राय ली जाती है? बिल्कुल नहीं. इसमें स्थानीय लोगों की राय के लिए कोई जगह ही नहीं होती. सरकारें अपने मन से भूमि या खदानों का आवंटन करती हैं और यह भी नहीं सोचतीं कि इससे विस्थापित हुए लोगों की क्या हालत होगी या उनके पुनर्वास के लिए क्या-क्या क़दम उठाए जाने चाहिए. यह कहानी सिर्फ़ छतीसगढ़ की ही नहीं है, बल्कि उन सभी राज्यों की है, जहां माओवाद की समस्या है, चाहे वह उड़ीसा हो या फिर झारखंड. अभी उड़ीसा में पोस्को एवं वेदांता को लेकर जिस तरह का जनसंघर्ष चल रहा है, उससे वहां माओवाद और माओवादियों की ताकत बढ़ेगी या घटेगी?

अब जरा सरकारों द्वारा बनाए गए क़ानून पर भी नज़र डालिए. 1996 में पेसा एक्ट आया, जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को अनूसूचित क्षेत्र तक विस्तारित किया गया. 15 साल बीत गए, लेकिन अभी तक 9 में से सिर्फ़ तीन राज्यों ने ही इस संबंध में क़ानून बनाए हैं. पेसा के तहत ग्रामसभा को महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए, लेकिन कहीं भी इस क़ानून का न तो सही इस्तेमाल हो रहा है और न ही सरकारें इसके क्रियान्वयन में कोई दिलचस्पी दिखा रही हैं. इसकी एक वजह यह है कि अगर स्थानीय स्तर पर लोगों को जल, जंगल, ज़मीन एवं खनिज से जुड़े फ़ैसले लेने का अधिकार मिल जाएगा, तो फिर राज्य सरकार क्या करेगी, यह विचार भी सरकारों को शासन की स्थानीय इकाई मजबूत बनाने से रोक देता है. नतीजतन, सत्ता, शासन एवं व्यवस्था से आम आदमी दूर होता चला जाता है और फिर जो नतीजा हमारे सामने आता है, उसे हम माओवाद के रूप में भी देखते हैं.

जहां तक वन अधिकार क़ानून का सवाल है, तो इसके तहत जंगल में परंपरागत तौर पर रहने वाले लोगों को कुछ वन उत्पाद इकट्ठा करने भर का अधिकार दिया गया है, या फिर उन्हें पट्टे पर खेती के लिए ज़मीन दी जा सकती है, लेकिन किसी भी क़ीमत पर वे वहां की ज़मीन या संपदा बेच नहीं सकते, या उस पर उनका मालिकाना हक नहीं हो सकता. आख़िर इस तरह के अधिकारों से उन लोगों को क्या फ़ायदा होगा, जो सैकड़ों वर्षों से न सिर्फ़ जंगलों में रहते आ रहे हैं, बल्कि उनकी रक्षा भी करते आ रहे हैं? दूसरी तरफ़, सरकारें जब चाहें, उन्हें उनकी ज़मीन से बेदखल कर उसे निजी कंपनियों को दे सकती हैं. आख़िर यह कैसा क़ानून है, कैसा अधिकार है कि लोग अपनी ही ज़मीन पर किराएदार की हैसियत से रहने के लिए मजबूर हैं. ऐसे में, एक लोकतंत्र की पारंपरिक परिभाषा संदेह के घेरे में आ जाती है, जहां जनता अपने ही प्रतिनिधियों की गुलाम बनकर रह गई है. ■

shashishekhar@chauthiduniya.com

नक्सलवाद से माओवाद तक

आख़िर वह क्या वजह रही कि पिछले 45 वर्षों से चली आ रही समस्या का समाधान इस देश की सरकार नहीं ढूंढ पाई? एक नज़र में देखते हैं कि कैसे नक्सलवाद के नाम से शुरू हुआ एक आंदोलन आज माओवाद के नाम से जाना जा रहा है.

- भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का गठन 21 सितंबर, 2004 को हुआ था.
- पीडब्ल्यूजी और एमसीसीआई के विलय से यह अस्तित्व में आई.
- पीपुल्स वार ग्रुप का गठन 1980 में हुआ था.
- कोंडापल्ली सीतारमैया इस ग्रुप के नेता थे.
- नारायण सान्याल के नेतृत्व वाले यूनिटी ग्रुप का अगस्त 1998 में पीपुल्स वार ग्रुप के साथ विलय.
- एमसीसी का गठन 20 अक्टूबर, 1969 को कानाई चटर्जी के नेतृत्व में हुआ. पहले यह ग्रुप दक्षिण देश के रूप में जाना जाता था.
- जनवरी, 2003 में एमसीसी और पंजाब आधारित रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विलय.
- नया नाम माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया (एमसी-सीआई) हो गया.

मध्य प्रदेश

अभी पिछले दिनों उमाशंकर गुप्ता ने मुरैना में नक्सल समस्या से निपटने के लिए मध्य प्रदेश को केंद्र से पर्याप्त सहयोग न मिलने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य के नौ ज़िलों में नक्सल गतिविधियों के सबूत होने के बावजूद केंद्र सिर्फ़ बालाघाट को प्रभावित ज़िला मानता है, बाकी आठ ज़िलों को नहीं. उनके अनुसार, सीधी, सिंगरौली, रीवा, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, मंडला एवं डिंडोरी में भी नक्सल गतिविधियां देखी गई हैं. गुप्ता का आरोप है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रदेश के नौ ज़िलों में नक्सल गतिविधियों के पर्याप्त सबूत पेश करने के बावजूद केंद्र से निर्धारित मापदंडों के मुताबिक संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं. मंडला, डिंडोरी, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया एवं अनूपपुर में राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई करके स्थिति नियंत्रित कर रही है.

गृहमंत्री का उतावलापन

नक्सल प्रभावित ज़िला घोषित कराने की असलियत

सूबे के जो ज़िले नक्सल प्रभावित नहीं भी हैं, उन्हें जबरन और साजिशन नक्सल प्रभावित घोषित कराने की कवायद ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. क्या राज्य सरकार नक्सल समस्या से निपटने के प्रति वाकई गंभीर है या फिर वह इसकी आड़ में पर्दे के पीछे से कॉरपोरेट्स के हित साधने में जुटी हुई है?

अरविंद वर्मा

छत्तीसगढ़ हमले के उपरांत नक्सलवाद के मसले पर जहां-तहां विशेषकर, टीवी चैनलों एवं मीडिया के अन्य मंचों पर जमकर चली बहस-मुबाहिसों में कांग्रेस और भाजपा जैसे राजनीतिक दलों के नेताओं को तो भरपूर मुंह चलाने के अवसर दिए जाते देखे गए, लेकिन उन सामाजिक कार्यकर्ताओं को सिरे से अनसुना किया जाता रहा, जो कह रहे थे कि नक्सलवाद के बढ़ते प्रभाव पर रोक लगाने के लिए केवल आदिवासी क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि देश भर में तथाकथित विकास की इस दिवस प्रक्रिया एवं अवधारणा में ही आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है. दरअसल, इसी की आड़ में कॉरपोरेट्स द्वारा केंद्र-राज्य सरकारों के सहयोग से न सिर्फ़ राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों की लूट निरंतर जारी है, बल्कि आदिवासियों, दलितों, छोटे किसानों, खेतिहर मज़दूरों और समाज के अन्य पिछड़े-कमजोर वर्गों का शोषण-दमन भी.

ऐसी और अन्य तमाम मिलती-जुलती परिस्थितियों के बीच यह कतई आश्चर्यजनक एवं बेवजह नहीं है कि विकास के ऐसे ही मापदंडों पर नए कीर्तिमान गढ़ने और दूसरे राज्यों को पछाड़ कर अव्वल आने की होड़ में जुटे छत्तीसगढ़ के पड़ोसी एवं पुराने मूल-राज्य मध्य प्रदेश में भाजपा की शिवराज सिंह सरकार के गृहमंत्री उमाशंकर गुप्ता एक अर्से से नक्सल प्रभावित जिलों की तादाद में इजाफा कराने की सुनियोजित मुहिम छेड़े हुए हैं. वह इस दिशा में केंद्र की ओर से आवश्यक सहायता-सहयोग न मिलने का रोना रोते हुए उसे कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे. अपनी मुहिम में वह मुख्य रूप से राज्य के उन्हीं आदिवासी, दलित एवं पिछड़े वर्गों की बहुलता वाले ज़िलों को रेखांकित कर रहे हैं, जहां के नैसर्गिक संसाधनों पर कॉरपोरेट्स की नज़र है और जिन पर मेहरबान राज्य के मुख्यमंत्री उनकी खातिर पलक पांवड़े बिछाने को आतुर हैं. उक्त ज़िलों के आदिवासी, किसान, मज़दूर आदि तबके अपने जीवन के आधारों को किसी भी क़ीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी सरकार प्रशासन-पुलिस के बलबूते उन्हें वहां से किसी भी तरह खदेड़ने पर उतारू है.

अभी पिछले दिनों उमाशंकर गुप्ता ने मुरैना में नक्सल समस्या से निपटने के लिए मध्य प्रदेश को केंद्र से पर्याप्त सहयोग न मिलने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य के नौ ज़िलों में नक्सल गतिविधियों के सबूत होने के बावजूद केंद्र सिर्फ़ बालाघाट को प्रभावित ज़िला मानता है, बाकी आठ ज़िलों को नहीं. उनके अनुसार, सीधी, सिंगरौली, रीवा, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, मंडला एवं डिंडोरी में भी नक्सल गतिविधियां देखी गई हैं. गुप्ता का आरोप है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रदेश के नौ ज़िलों में नक्सल गतिविधियों के पर्याप्त सबूत पेश करने के बावजूद केंद्र से निर्धारित मापदंडों के मुताबिक संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं. मंडला, डिंडोरी, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया एवं अनूपपुर में राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई करके स्थिति नियंत्रित कर रही है.

ग़ौरतलब है कि गुप्ता द्वारा उल्लेखित उक्त ज़िलों में कॉरपोरेट सेक्टर की विभिन्न प्रस्तावित औद्योगिक इकाइयों के लिए स्थानीय जल, जंगल एवं ज़मीनें बड़े पैमाने पर जबरिया छीने जा रहे हैं और प्रभावित लोग उसके विरोध में सड़क पर उतर रहे हैं, लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि राज्य सरकार की प्रायोजित प्रचार सामग्री का प्रकाशन करके खुद को धन्य समझ रहे प्रमुख प्रचार माध्यम इन ख़बरों को नज़रअंदाज कर रहे हैं. राष्ट्रीय मीडिया भी उदासीन बना हुआ है. ज़्यादातर प्रचार माध्यम शिवराज सरकार की विकास संबंधी थोथी आंकड़ेबाजी एवं घोषणाओं से पटे पड़े हैं और इसीलिए उन्हें पीड़ित, प्रभावित एवं विस्थापित होकर हाशिए से भी बाहर धकियाए जाते हज़ारों-लाखों लोगों की पीड़ा से कोई मतलब नहीं है. चूंकि सरकार की तरह इनमें से अधिकांश का मानना है कि यह तो विकास की सहज परिणति है, जिसे झेलने-भुगतने से इंकार करना विकास का विरोध नहीं, बल्कि राष्ट्रद्रोह है और ऐसा करने वाले लोगों से सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए. ऐसे में, अगर उमाशंकर गुप्ता कॉरपोरेट सेक्टर के हाथों सौंपे जाने वाले इलाकों में नक्सलवाद के बढ़ते प्रभाव का हौव्वा खड़ा करने के अपने सोचे-समझे अभियान में पूरी ताकत से जुटे हैं, तो यह स्वाभाविक है, क्योंकि इस तरह उन्हें केंद्र सरकार को उलाहना देने एवं कोसने का मौक़ा मिल रहा है, साथ ही खुद की ज़िम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने का भी. यही नहीं, भविष्य में नक्सलियों से निपटने के लिए केंद्र से मिलने वाले करोड़ों-अरबों रुपये की बंदरबांट की साजिश रची जा रही है और इस बाबत नौकरशाही को भी लालच दिया जा रहा है. राज्य सरकार की मदद से कॉरपोरेट सेक्टर के हाथों लूटे जाते एवं अपने जीवनयापन के प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल होने से इंकार कर आंदोलित हो रहे जनसमूहों और ऊंची से ऊंची क़ीमत पर भी बिकने को तैयार न होने वाले पीड़ितों-प्रभावितों का समर्थन करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं संगठनों पर नक्सलवादी होने का ठप्पा लगाया जा रहा है. केवल यही नहीं, सरकारी हिंसा के जरिए उनका दमन करने की कोशिश भी की जा रही है. दरअसल, इसके पीछे एक खेल यह भी है कि यहां अपना कारोबारी साम्राज्य खड़ा करने को आतुर कॉरपोरेट सेक्टर से उन भाजपा समर्थक नक्सलियों के लिए मनमानी लेवी वसूली के चोर दरवाजे खोल दिए जाएं, जिनसे आगामी चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों को जिताने एवं विरोधियों को हराने और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें रास्ते से हटाने में मदद लेनी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

> गुप्ता द्वारा उल्लेखित उक्त ज़िलों में कॉरपोरेट सेक्टर की विभिन्न प्रस्तावित औद्योगिक इकाइयों के लिए स्थानीय जल, जंगल एवं ज़मीनें बड़े पैमाने पर जबरिया छीने जा रहे हैं और प्रभावित लोग उसके विरोध में सड़क पर उतर रहे हैं, लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि राज्य सरकार की प्रायोजित प्रचार सामग्री का प्रकाशन करके खुद को धन्य समझ रहे प्रमुख प्रचार माध्यम इन ख़बरों को नज़रअंदाज कर रहे हैं. राष्ट्रीय मीडिया भी उदासीन बना हुआ है. .

उमाशंकर गुप्ता

ईटीवी के इस कार्यक्रम में कांग्रेस एवं भाजपा के अलावा, जिन दूसरे दलों के नेता आमंत्रित किए गए थे, उनमें समाजवादी पार्टी के महासचिव सी पी राय, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता एवं यूपीए–1 के शासन में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रहे मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी एवं जनता दल यूनाइटेड के महासचिव के सी त्यागी प्रमुख थे.

अंधकार में है मुसलमानों का भविष्य

आगामी लोकसभा चुनावों के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है. मुस्लिम वोट कैसे हासिल किया जाए, इसे लेकर ज़ोर-आज़माइश चल रही है. भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह को जहां इस बात पर फ़ख़्र है कि भारत में सबसे अधिक, यानी 72 संप्रदायों के मुसलमान रहते हैं, वहीं केंद्रीय मंत्री सलमान ख़ुर्शीद कहते हैं कि वोट मांगने के लिए राजनीति तो की ही जाती है. आज गांव-देहात में रहने वाले मुसलमानों का अपनी ज़मीनों से मालिकाना हक़ तेज़ी से ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन उसका दूर-दूर तक कोई जिक्र नहीं होता. न तो कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को मालूम है कि भारतीय मुसलमानों की वास्तविक समस्याएं क्या हैं और न ही सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भाजपा को. ऐसे में मुसलमानों को अपना भविष्य एक बार फिर अंधकारमय दिखाई दे रहा है.

मोदी के दांत में ख़ून लग चुका है: स्वामी अधोक्षानंद

अक्लियतों को दरपेश चैलेंजेज़ विषय पर आयोजित सेमिनार की अध्यक्षता कर रहे पुरी के शंकराचार्य के शिष्य स्वामी अधोक्षानंद ने वह बात कह दी, जिसे केवल उन जैसा साहसी एवं सच्चा धार्मिक प्रतिनिधि ही कह सकता है. पाठकों को याद होगा कि अभी कुछ महीने पहले इलाहाबाद के महाकुंभ में जाने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी कोशिश की थी, ताकि वह हिंदू धार्मिक प्रतिनिधियों का आशीर्वाद हासिल कर सकें. मोदी को यह कोशिश नाकाम बनाने में शंकराचार्य स्वामी अधोक्षानंद का हाथ था. उन्होंने मोदी के इलाहाबाद महाकुंभ में न पहुंच पाने के राज़ से पहली बार पर्दा उठाते हुए कहा कि मोदी के दांत में ख़ून लग चुका है और ऐसे ख़ूनी को इलाहाबाद महाकुंभ में आने की अनुमति बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए. इसके लिए उन्होंने विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल पर भी दबाव बनाया. उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी आगाह कर दिया था कि मोदी के महाकुंभ में आने से हालात ख़राब और अनियंत्रित हो सकते हैं. स्वामी अधोक्षानंद ने कहा कि भाजपा नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाना और मुसलमानों को देश से बाहर खदेड़ना चाहती है, लेकिन वह इसकी अनुमति बिल्कुल नहीं देंगे. उन्होंने कहा कि धर्म एवं देश, दोनों को बचाना उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है और मुसलमानों को साथ लिए बिना देश विकास कर ही नहीं सकता. ■

डॉ. कमर तबरेज

आज देश में मुसलमानों की समस्याएं क्या हैं? आतंकवाद का आरोप, निर्दोष मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी, सांप्रदायिक दंगों में जान-माल का नुक़सान, आरक्षण न मिलना, शिक्षा का अभाव, पुलिस एवं अन्य सरकारी नौकरियों में तीन प्रतिशत से भी कम प्रतिनिधित्व, राजनीति में पर्याप्त हिस्सेदारी न मिलना, वक़्फ़ संपत्तियों की लूट या कुछ और? वर्तमान में उर्दू समाचारपत्रों एवं नेताओं के बयानों में आज सबसे अधिक ज़ोर केवल तीन बातों पर देखने को मिल रहा है, यानी आतंकवाद के आरोप में निर्दोष मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी, देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले सांप्रदायिक दंगे और आरक्षण. बाक़ी समस्याएं, जैसे शिक्षा का अभाव, पुलिस एवं अन्य सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का तीन प्रतिशत से भी कम प्रतिनिधित्व और राजनीतिक दलों में मुस्लिम नेताओं की तेज़ी से घटती संख्या आदि उस समय चर्चा का विषय बनती हैं, जब कहीं मुसलमानों की समस्याओं को लेकर किसी सेमिनार या कांफ्रेंस का आयोजन होता है, जिनमें धर्मनिरपेक्ष राजनीतिज्ञों, विद्वानों, पत्रकारों के साथ-साथ केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के प्रतिनिधियों या मंत्रियों को इसलिए बुलाया जाता है, ताकि उनसे मालूम किया जा सके कि मुसलमानों की समस्याएं हल करने के लिए सरकार क्या कर रही है. दूसरी ओर, विपक्षी दलों के नेता इसलिए बुलाए जाते हैं, ताकि वे बता सकें कि इस मामले में सरकार से कहां चूक हो रही है, या फिर अगर वे ख़ुद अगली बार सरकार बना सके, तो उनके पास उक्त समस्याएं हल करने के लिए क्या योजना है.

बीते 22 जून को राजस्थान में जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में ईटीवी उर्दू की ओर से एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसका विषय था-अक्लियतों को दरपेश चैलेंजेज़. इसमें शिरकत करने वाले विभिन्न दलों के नेताओं ने मुसलमानों की समस्याओं पर बात करने की बजाय इस मौक़े को लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र उनके वोट हासिल करने का प्लेटफ़ॉर्म समझा. केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के विदेश मंत्री सलमान ख़ुर्शीद सबसे पहले मंच पर आए और उन्होंने दो टूक कहा कि वोट मांगना कोई खराब बात नहीं है और यह हर सियासी नेता करता है. लेकिन सलमान ख़ुर्शीद से यह पूछा जाना चाहिए कि वोट मांगने के लिए झूठ बोलना कहां तक जायज़ है और क्या उन्होंने आरक्षण के नाम पर मुसलमानों से झूठ नहीं बोला था?

जब भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह की बारी आई, तो वह मुसलमानों के सामने एक गुनहगार की तरह खड़े नज़र आए. उन्होंने अपना अधिकतर समय अपनी पार्टी की ओर से सफ़ाई देने में लगाया. अपने संबोधन में उन्होंने एक और अजीबोग़रीब बात कह दी कि मुसलमानों में भी बहुत से संप्रदाय हैं. 72 संप्रदायों के साथ सबसे अधिक मुसलमान भारत में बसते हैं, दुनिया के किसी और कोने में नहीं, जिस पर उन्हें फख़्र है. ऐसा लगा, जैसे मुसलमानों को लेकर भाजपा अध्यक्ष का दिमाग़ चला भी, तो उन्होंने यह पहलू ज़रूर निकाल लिया कि संप्रदायों की बुनियाद पर मुसलमान कैसे बंटे हुए हैं, यानी ज़रूरत पड़ने पर देश के मुसलमानों को आपस में कैसे लड़ाया जा सकता है. राजनाथ सिंह को यह तो अब तक याद है कि उनकी शादी किसी मुस्लिम ने ही तय कराई थी, लेकिन वह और उनकी पार्टी दोनों ही भूल गए कि देश के मुसलमानों को दूसरी जातियों के साथ जोड़कर कैसे रखना है. दरअसल, भाजपा एवं उसके सहयोगी संगठनों ने पिछले 65 सालों में इसमें कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी कि मुसलमानों को कैसे देश का दुश्मन साबित किया जाए, कैसे उन्हें देश से भगाया जाए या फिर कैसे उन्हें देश में दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया जाए. यही वजह थी कि मंच पर देश की सबसे बड़ी विपक्षी और आगामी लोकसभा चुनावों के बाद सरकार बनाने का सपना पाले बैठी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में जब उन्होंने कहा कि चूंकि वह मुसलमानों का दर्द समझना चाहते हैं, इसलिए उनके बीच आए हैं. अगर किसी को उनकी पार्टी से शिकायत है या कोई यह समझता है कि भाजपा शासित राज्यों में मुसलमानों की समस्याएं हल नहीं हो रही हैं, तो उन्हें इसकी लिखित सूचना दी जाए और वह उक्त समस्याएं हल कराने की पूरी कोशिश करेंगे. इस पर राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन माहिर आज़ाद ने सवाल उठाया कि गुजरात में मुस्लिम छात्रों को अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से जारी मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से लाभांवित नहीं होने दिया जा रहा है. कुछ लोग माहिर आज़ाद से सवाल करने लगे कि केवल गुजरात की भाजपा सरकार ही नहीं, बल्कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार भी गोपालगढ़ दंगों के लिए जवाब दे. इसी बीच राजनाथ सिंह एवं सैयद शाहनवाज़ हुसैन हॉल से मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए, लेकिन उन्होंने वहां मौजूद मुसलमानों की बेचैनी दूर करने की कोई कोशिश नहीं की. ऐसे में सवाल यह उठता है कि देश का मुसलमान भाजपा से अच्छाई की उम्मीद करे भी, तो भला कैसे?

जब भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह की बारी आई, तो वह मुसलमानों के सामने एक गुनहगार की तरह खड़े नज़र आए. उन्होंने अपना अधिकतर समय अपनी पार्टी की ओर से सफ़ाई देने में लगाया. अपने संबोधन में उन्होंने एक अजीबोग़रीब बात कह दी कि मुसलमानों में भी बहुत से संप्रदाय हैं.

ईटीवी के इस कार्यक्रम में कांग्रेस एवं भाजपा के अलावा, जिन दूसरे दलों के नेता आमंत्रित किए गए थे, उनमें समाजवादी पार्टी के महासचिव सी पी राय, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता एवं यूपीए-1 के शासन में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रहे मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी एवं जनता दल यूनाइटेड के महासचिव के सी त्यागी प्रमुख थे. इनमें से अधिकतर नेताओं ने या तो कांग्रेस एवं भाजपा पर निशाना साधा, या फिर मुसलमानों को रिझाने का प्रयास किया. सपा महासचिव सी पी राय बाबरी मस्जिद का मुद्दा उछालते रहे. उन्होंने भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह (जो उस समय तक जा चुके थे) पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने कभी सड़क पर बच्चों को जन्म देने या कोठे पर जिस्म बेचकर जीवनयापन करने वाली ग़रीब हिंदू महिलाओं का मुद्दा नहीं उठाया, जबकि वह हिंदुओं की हमदर्द होने का दावा करती है. अली अशरफ़ फ़ातमी को सुनकर, तो ऐसा लगा कि यूपीए के शासन में मुसलमानों से संबंधित जितने भी कल्याणकारी कार्य हुए, वे केवल उन्हीं की देन हैं. उन्होंने कहा कि सच्चर कमेटी की सिफ़ारिशें लागू करने के लिए यूपीए-1 सरकार ने फ़ातमी कमेटी बनाई थी, जिसने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी स्थापित की एवं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पांच कैंपस खोलने का प्रस्ताव दिया, जिनमें प्रत्येक कैंपस पर 2200 करोड़ रुपये सरकार की ओर से ख़र्च किए जाएंगे. उन्होंने दावा किया कि अगर फ़ातमी कमेटी की रिपोर्ट पूरी तरह लागू कर दी जाती है, तो मुसलमानों की प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा की समस्या हल हो जाएगी. जदयू के महासचिव के सी त्यागी ने मुसलमानों को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात कही. उन्होंने कहा कि देश में सांप्रदायिक दंगे होते रहे हैं, लेकिन अगर दंगे के बाद मुसलमानों के अंदर यह एहसास ख़त्म हो जाए कि उन्हें अब कहीं से न्याय नहीं मिलेगा, तो यह देश के लिए बहुत ख़तरनाक होगा. उनका इशारा 1984 के सिख विरोधी दंगों और मेरठ एवं मलियाना दंगों के पीड़ितों को अब तक न्याय न मिलने की ओर था. उन्होंने कहा कि सारे आरोप तो बर्दाश्त किए जा सकते हैं, लेकिन देश से बग़ावत का आरोप ऐसा होता है, जो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता. लिहाज़ा सरकार को नागरिकों पर ऐसे आरोप लगाने से बचना होगा.

सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान ने कहा कि यूपीए सरकार की नीतियों के कारण आयात की आने वाली वस्तुएं महंगी और निर्यात की जाने वाली वस्तुएं सस्ती हो गई हैं. भारतीय मुसलमान भी एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट के काम में लगे हुए हैं, इसलिए अन्य नागरिकों के साथ-साथ उन्हें भी नुक़सान हो रहा है. अंजान ने ग़रीबी और बैंक का कर्ज़ वापस न करने के कारण देश में अब तक 5 लाख किसानों द्वारा आत्महत्या के लिए भी यूपीए सरकार की किसान विरोधी नीतियों को ज़िम्मेदार ठहराया. दरअसल, सभी नेताओं ने अपने-अपने ढंग से बात रखने की कोशिश तो की, लेकिन वे न तो मुसलमानों की समस्याएं गिना सके और न ही उनका कोई समाधान बता सके. कार्यक्रम में मौजूद लोगों को अगर किसी नेता को सुनने की बेकरारी थी, तो वह थे अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री के रहमान ख़ां, जो मंच पर आए, तो बड़े जोश के साथ, लेकिन अपनी बातों से न तो मौजूद लोगों को संतुष्ट कर सके और न ही पूरी दुनिया में ईटीवी का यह कार्यक्रम देख रहे दर्शकों को. जब वह बोल रहे थे, तो उनकी लाचारी साफ़ झलक रही थी. उल्लेखनीय है कि वक्ताओं ने इस कार्यक्रम के विषय शीर्षक पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि चूंकि यहां बात केवल मुसलमानों की हो रही है, इसलिए विषय शीर्षक अल्पसंख्यकों को दरपेश चैलेंजेज़ की बजाय मुसलमानों को दरपेश चैलेंजेज़ होना चाहिए था. उसका जवाब देते हुए के रहमान ख़ां ने कहा कि चूंकि भारत के अल्पसंख्यकों में 75 प्रतिशत मुसलमान हैं, इसलिए उनकी बात अधिक होती है. इसके बाद वह असल मुद्दे पर वापस आए और बोले कि देश का मुसलमान यह सोचने पर मजबूर हो गया है कि उसे किसी प्रकार की सुरक्षा हासिल नहीं है. निर्दोष मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है. कोई मुसलमान यह नहीं कहता कि दोषी को सज़ा मत दो, बल्कि उसकी केवल एक मांग है कि आरोपी को पूछताछ के लिए अगर आवश्यक हो, तो कुछ दिनों के लिए हिरासत में रखो और फिर उसे ज़मानत पर रिहा कर दो. अगर अदालत उसे अपराधी सिद्ध कर देती है, तो फिर सज़ा दो. उन्होंने कहा कि इस बारे में गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे से बातचीत हुई है, जिन्होंने वादा किया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर ऐसे मामले शीघ्र निबटाए जाएंगे. आरक्षण के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुसलमान एक सोशल ग्रुप हैं और हमने इस्लाम के नाम पर आरक्षण नहीं मांगा है, बल्कि हम देश के इस पिछड़े सोशल ग्रुप के लिए आरक्षण मांग रहे हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय धर्म के नाम पर यह आरक्षण देने से इंकार कर रहा है. लिहाज़ा, यह एक गंभीर समस्या है.

चौथी दुनिया के प्रधान संपादक संतोष भारतीय ने विदेश मंत्री सलमान ख़ुर्शीद को कांग्रेस का एक होशियार मंत्री बताया और के रहमान ख़ां को बेबस मंत्री. उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि अगर ये दोनों मंत्री मुसलमानों की समस्याएं हल कराने की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते, तो अपने-अपने पदों से इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे देते? संतोष भारतीय ने एक और बात कही, जिस पर अभी तक न तो किसी सियासी नेता ने ध्यान दिया और न ही मुसलमानों के तथाकथित प्रतिनिधियों ने, जबकि यह इस समय मुसलमानों की सबसे बड़ी समस्या है और जिसका समाधान शीघ्र न किया गया, तो देश का मुसलमान कहीं का नहीं रहेगा. यह समस्या है, मुसलमानों का ज़मीनों के स्वामित्व से तेज़ी से वंचित होना. मुसलमान ग़रीब, अशिक्षित हैं, इसीलिए उनके बच्चों की संख्या अधिक होती है और ख़ासकर, बेटियों की शादी का समय जब आता है, तो मुसलमान अपनी ज़मीनें एवं मकान बेचकर ही शादी के ख़र्च बर्दाश्त करता है. अगर यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा, तो आने वाले 40-50 सालों के बाद गांवों में रहने वाले मुसलमानों के पास अपनी ज़मीन एवं मकान नहीं बचेंगे. इसके बाद हम कल्पना कर सकते हैं कि अधिकतर मुसलमानों का हाल क्या होगा? ज़मीन और मकान ही नहीं रहेंगे, तो फिर वे ख़ुद को इस देश का नागरिक कैसे साबित करेंगे. इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सबको मिलकर सोचने और रणनीति बनाने की आवश्यकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

> अंतरराष्ट्रीय तौर पर यह समस्या इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को बीते 19 जून को अपने जर्मनी दौरे के दौरान वहां की चांसलर एंजेला मार्कल के साथ बर्लिन में एक विशेष प्रेस कांफ्रेंस में इसका खंडन करना पड़ा. समाचार एजेंसी एपी के अनुसार, उन्होंने अमेरिकी सर्विलांस प्रोग्राम का बचाव करते हुए कहा कि यह अमेरिकी अदालतों की निगरानी में है, जिसे यह देखना है कि किसी की भी प्राइवेसी में हस्तक्षेप की आशंका को सख्ती से कम किया जाए.

बिहार

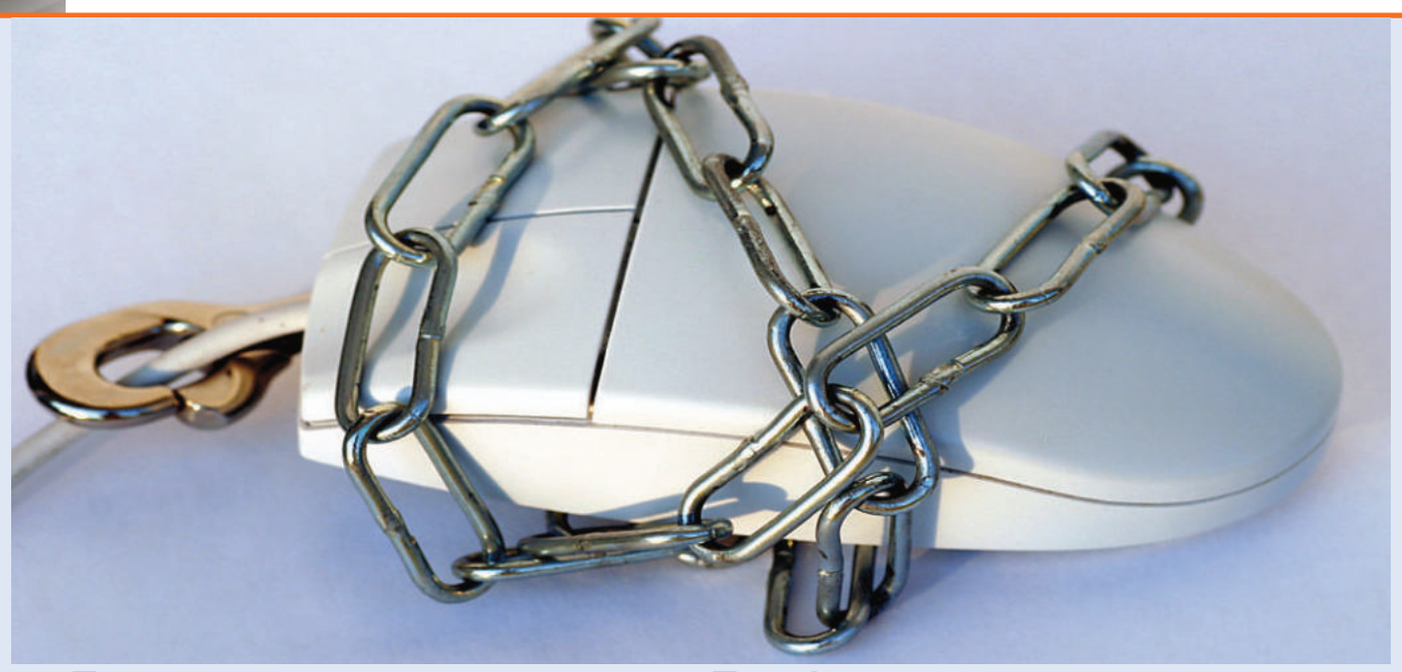

होशियार! अमेरिका आपकी जासूसी कर रहा है

कोई सोच भी नहीं सकता कि उसके कंप्यूटर के अंदर जो डाटा सेव हो रहा है, उसकी जासूसी हो रही है और उसकी प्राइवेसी को बड़ा ख़तरा हो सकता है. पिछले दिनों पूर्व सीआईए अधिकारी एडवर्ड स्नोडेन के ख़ुलासे से यह आश्चर्यजनक तथ्य सामने आए हैं कि अन्य देशों के साथ-साथ ईरान, पाकिस्तान, उर्दन, मिस्र एवं भारत भी अमेरिका के निशाने पर हैं. भारत के ख़िलाफ़ जासूसी का यह सिलसिला पिछले 6 सालों से निरंतर जारी है.

ए यू आसिफ़

भारत समेत पूरी दुनिया में इन दिनों सबसे चर्चित मुद्दा यह है कि अमेरिका 6 सालों से भारत सरकार और भारतीय नागरिकों की जासूसी कर रहा है, जिसके चलते प्राइवेसी और ख़ुफिया तंत्र के लिए गंभीर ख़तरा पैदा हो गया है. इसका अनुमान अभी हाल में पूर्व सीआईए अधिकारी एडवर्ड स्नोडेन, जो इन दिनों हांगकांग में शरण लिए हुए हैं, द्वारा किए गए ख़ुलासे से होता है. उल्लेखनीय है कि भारत ऐसा पांचवां देश है, जो अमेरिका के निशाने पर है. अन्य चार देशों में ईरान, पाकिस्तान, उर्दन एवं मिस्र हैं, जिन पर भारत के साथ सिर्फ़ नज़र ही नहीं रखी जा रही है, बल्कि कंप्यूटर नेटवर्क, टेलीफोन एवं मोबाइल डाटा द्वारा सभी जानकारियां अपने क़ब्ज़े में ली जा रही हैं. ब्रिटिश अख़बार गार्जियन के अनुसार, केवल मार्च 2013 में ही अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनएसए) ने ईरान से 14 बिलियन, पाकिस्तान से 13.5 बिलियन, उर्दन से 12.7 बिलियन, मिस्र से 7.6 बिलियन एवं भारत से 6.3 बिलियन डाटा एकत्र किए हैं. सवाल यह है कि उक्त सूची में क्या किसी खास वजह से इन पांच देशों को निगरानी के लिए क्रमानुसार शुरू में ही रखा गया है? कहीं ऐसा इनकी मुस्लिम बाहुल्यता एवं अन्य घटनाओं को दृष्टिगत रखकर तो नहीं किया गया है? ग़ौरतलब है कि ईरान में लगभग 7 करोड़, पाकिस्तान में 15 करोड़, उर्दन में 65 लाख, मिस्र में 8 करोड़ एवं भारत में 14 करोड़ मुस्लिम आबादी है.

सच तो यह है कि अमेरिका की यह हरकत सिर्फ़ अनैतिक ही नहीं, बल्कि आपराधिक भी है. अजीब बात यह भी सुनने को मिल रही है कि अमेरिकी संस्था एनएसए भारत के ख़िलाफ़ 2005-06 से साइबर घुसपैठ कर रही है. जहां एक ओर भारतीय सरकार एवं जनता के विरुद्ध यह जासूसी जारी थी, वहीं उन्हीं दिनों साइबर सुरक्षा मामलों को लेकर भारत एवं अमेरिका के बीच समझौते भी किए जा रहे थे. इसकी गंभीरता इसलिए भी बढ़ जाती है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर जासूसी का ऐसा कोई मामला इससे पहले कभी सुनने को नहीं मिला, जिसमें बड़ी मात्रा में डाटा हैकिंग हुई, उसे इंटरसेप्ट किया गया और फिर हासिल भी कर लिया गया. कहा जाता है कि इस काम को एनएसए प्रिज्म द्वारा अंजाम देती है. प्रिज्म दरअसल, ख़ुफिया इलेक्ट्रॉनिक निगरानी का कोड नेम है. इसे सरकारी भाषा में यूएस-984-एक्सएन कहा जाता है. जानकारी के अनुसार, 2007 में अमेरिकी कांग्रेस ने इसे मंजूरी भी दी थी. एनएसए प्रिज्म द्वारा किसी भी ईमेल, लॉगिंग नोटिफिकेशन, वॉइस चैट, सोशल नेटवर्किंग, नेटवर्किंग के विवरण सहित वीडियो, फोटो, आईपी बातचीत और फाइल ट्रांस्फर तक पहुंच सकती है. प्रीज़म ने इस दौरान अधिकतर गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, याहू, एओएल एवं स्काइप आदि सेंट्रल सर्वर्स तक अपनी पहुंच बना ली है. उल्लेखनीय है कि एनएसए के डाटा माइनिंग टूल को बाउंडलेस इंफॉर्मेंट कहा जाता है. जिस शख्स ने यह ख़ुलासा किया है, वह सीआईए से जुड़ा होने के अलावा, इस संबंध में एनएसए का ठेकेदार भी है. इस शख्स का कहना है कि अमेरिकी सर्विलांस सिस्टम ने पर्सनल डाटा तक अपनी पहुंच बनाने के लिए जीमेल का प्रयोग किया, जो कि अन्य ईमेल स्रोतों की तरह मुफ्त सेवाएं देता है.

जब यह मुद्दा चर्चा का विषय बना, तो इसकी गंभीरता कम करने के लिए यह तर्क पेश किया जाने लगा कि ऐसा सब कुछ आतंकवाद की रोकथाम के लिए किया जा रहा है. स्वयं अमेरिका के अंदर भी यह जासूसी विभिन्न स्तरों पर होती रही है. वहां यह दावा भी किया जा रहा है कि निजी फोन एवं क्रेडिट कार्ड द्वारा लेन-देन की इंटरसेप्टिंग से आतंकवादी गतिविधियां रोकी गई हैं. इसका अर्थ यह है कि जनता और सरकार की गोपनीयता के साथ खिलवाड़ को आतंकवाद विरोधी अभियान से जोड़ा जा रहा है. एक ओर भारत अमेरिका द्वारा भारतीय नागरिकों की डाटा माइनिंग पर हैरानी जताता रहा है, तो दूसरी ओर वह स्वयं अपनी साइबर स्नूपिंग एजेंसी (एनसीसीसी) लांच करने की तैयारी में व्यस्त हो गया है. नेशनल साइबर को-आर्डिनेशन सेंटर (एनसीसीसी) के नाम से शुरू की जा रही इस एजेंसी का उद्देश्य साइबर सुरक्षा ख़तरों का रियल टाइम एसेसमेंट करना बताया जा रहा है. इस एजेंसी की भी भारत के सोशल नेटवर्क, ईमेल अकाउंट्स एवं अन्य डाटा तक पहुंच हो सकेगी. सभी सरकारी एजेंसियां इसका हिस्सा होंगी और भारतीय टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स इस नई एजेंसी (एनसीसीसी) की ज़रूरतों की पूर्ति करेंगे.

अंतरराष्ट्रीय तौर पर यह समस्या इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को बीते 19 जून को अपने जर्मनी दौरे के दौरान वहां की चांसलर एंजेला मार्कल के साथ बर्लिन में एक विशेष प्रेस कांफ्रेंस में इसका खंडन करना पड़ा. समाचार एजेंसी एपी के अनुसार, उन्होंने अमेरिकी सर्विलांस प्रोग्राम का बचाव करते हुए कहा कि यह अमेरिकी अदालतों की निगरानी में है, जिसे यह देखना है कि किसी की भी प्राइवेसी में हस्तक्षेप की आशंका को सख्ती से कम किया जाए. उन्होंने कहा, हमने सर्विलांस की बदौलत अनगिनत लोगों की जानें बचाईं और लगभग 50 आतंकवादी घटनाओं को नाकाम किया. वहीं ताजा जानकारी के अनुसार, 30 वर्षीय एडवर्ड स्नोडेन ने हांगकांग छोड़ दिया है और वह दुनिया की नज़रों से छिपकर किसी अन्य देश में रह रहे हैं. हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि वह रूस में थे और अब वहां से इक्वाडोर चले गए हैं. लेकिन वह वास्तव में कहां हैं, इसका किसी को पता नहीं है. दूसरी ओर अमेरिका ने अपना राज दुनिया के सामने जाहिर होने से कुपित होकर उनके ख़िलाफ़ अमेरिकी अदालत में मुकदमा दायर कर दिया है और उनकी तलाश जोर-शोर से जारी है. एडवर्ड स्नोडेन पर आरोप है कि खुद भी पूरी प्रक्रिया से जुड़े रहने के बावजूद उन्होंने यह राजफाश किया. ■

feedback@chauthiduniya.com

भारत की बेचैनी

इस गंभीर मुद्दे पर चौथी दुनिया ने कई महत्वपूर्ण लोगों से बातचीत की और उन्होंने इसे देश और जनता के लिए एक बड़ा ख़तरा बताया. प्रसिद्ध स्तंभकार कुलदीप नैयर, जिन्होंने 1975-77 में इमरजेंसी के दौरान प्रेस पर लागू की गई सेंसरशिप का डटकर मुक़ाबला किया था और चार समाचार एजेंसियां भंग करके बनाई गई राष्ट्रीय एजेंसी समाचार को ख़त्म करके पूर्व एजेंसियों की बहाली की अनुशंसा की थी तथा जिस पर अमल भी हुआ था, कहते हैं कि वह राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस सेंसरशिप थी, जबकि अमेरिका की ओर से सर्विलांस और स्नूपिंग इंटरनेशनल सेंसरशिप है. उनका कहना है कि यह सब ग़लत है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. लोकतंत्र का दावा करने वाले अमेरिका की ओर से ऐसा किया जाना बहुत शर्मनाक है. हम सबको मिलकर इसका विरोध करना चाहिए. वह इसके ख़िलाफ़ हैं और इसकी निंदा करते हैं. नैयर कहते हैं कि सरकार का यह कहना कि वह भारतीय डाटा माइनिंग मुद्दे को अमेरिका के सामने उठाएगी, क्या इतना काफी होगा? उनके अनुसार, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इसके विरुद्ध मिलकर आवाज़ उठाते हुए इस मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से ख़ुद बात करनी चाहिए, ताकि ऐसी शर्मनाक हरकतें तुरंत बंद हों. वरिष्ठ पत्रकार एवं पूर्व सांसद संतोष भारतीय कहते हैं कि यह सब केवल देश के नागरिकों की प्राइवेसी में घुसपैठ नहीं है, बल्कि ऐसा योजनाबद्ध तरीक़े से किया जा रहा है. इस योजना का पहला ट्रायल चार साल पहले अमेरिका के संरक्षण में मनमोहन सिंह की सरकार में आधार कार्ड के रूप में हुआ था. उनके अनुसार, इस प्रकार देश के प्रत्येक नागरिक की सभी जानकारियां अमेरिका को उपलब्ध हो गईं, जिसका इस्तेमाल किसी भी व्यक्ति या समुदाय के ख़िलाफ़ किया जा सकता है और अब तो कंप्यूटर में भी घुसपैठ करने की ख़बरें मिल रही हैं. इसका मतलब साफ़ है कि आप कंप्यूटर पर जो भी काम करते हैं, उन सब तक अमेरिका की पहुंच है, क्योंकि अधिकतर सर्वर प्रोवाइडर्स अमेरिका में मौजूद हैं और इस प्रकार विभिन्न तकनीकों समेत प्रीज़म का प्रयोग करके उनके डाटा तक आसानी से पहुंचा जा सकता है. संतोष भारतीय के अनुसार, अमेरिका ने इस तरह किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गोपनीयता ख़त्म करके लोकतंत्र के अंत की शुरुआत कर दी है. उन्हें आशंका है कि अमेरिका के इस क़दम से एक नए सांस्कृतिक संघर्ष की शुरुआत हो सकती है, जो कि ईसाइयों एवं मुसलमानों के बीच होगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय और सीआरपीएफ से लंबे समय तक जुड़े रहे दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन सफदर हुसैन ख़ां कहते हैं कि यह समस्या बहुत गंभीर है और इसका सीधा संबंध देश की सुरक्षा से जुड़ा है. इससे जहां आम आदमी की प्राइवेसी ख़त्म हो रही है, वहीं सरकार की गोपनीय फाइलें, जो कि कंप्यूटर पर हैं, उन तक दूसरों की पहुंच होती जा रही है. केंद्र सरकार को इस संदर्भ में अविलंब कार्यवाही करते हुए अमेरिकी शासन से बात करनी चाहिए. नेशनल इंटिग्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य नावेद हामिद ने इसे सरकार और देश के नागरिकों पर साइबर हमला बताया और कहा कि इससे देश की अखंडता ख़तरे में पड़ गई है. वह इस ख़बर को सुनते ही इतने चिंतित हो गए कि उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस समस्या को गंभीरता से लेने का निवेदन भी किया. ■

बिहार

बाढ़, जनता और सरकार

बाढ़ का मौसम आते ही शासन-प्रशासन की सक्रियता देखते ही बनती है. बैठकें होती हैं और फ़ैसले होते हैं, लेकिन हकीकत के धरातल पर कुछ भी नहीं होता. नतीजतन, प्राकृतिक आपदा की मार अंतत: जनता को सहनी ही पड़ती है.

सरोज सिंह

बरसात का मौसम आते ही सरकार बाढ़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन पर अपनी रूटीन बैठकें शुरू कर देती है. कुछ फ़ैसले होते हैं, कुछ अतिरिक्त धन भी आवंटित होता है और शुरू हो जाता है बंदरबांट का खेल. बारिश कम हुई, तो इज्जत बची रह जाती है, पर जब कोशी जैसी त्रासदी हो जाती है, तो सारे दावों की पोल खुल जाती है. सरकार इस मामले में कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा कुसहा में बर्बाद हुए परिवारों के दर्द से लग जाता है. प्रभावित लोगों को फिर से आबाद करने का काम किस गति से चल रहा है, इसे सब जानते हैं. दरअसल, ऊपर से नीचे तक का प्रशासनिक अमला बाढ़ में अपनी आमदनी की रेत खोजने में लगा रहता है. नतीजतन, जो लोग इस त्रासदी में बर्बाद होते हैं, उनका दु:ख-दर्द सुनने को कोई तैयार नहीं होता, लेकिन क्या पहले भी ऐसी ही बात थी?

सामाजिक कार्यकर्ता एवं बागमती बचाओ अभियान के अनिल प्रकाश एक कहावत सुनाते हैं, बाढ़े जीली, सुखाड़े मरली. वह समझाते हुए कहते हैं कि हमारे इलाके में पुराने लोग शुरुआत में यही कहावत कहा करते थे. बागमती एवं कमला जैसी नदियां बाढ़ के दिनों में अपने साथ हिमालय के इलाके की गाद भी लाती थीं, जो बहुत उपजाऊ होती थी. बाढ़ धीरे-धीरे आती थी और खेतों में उपजाऊ मिट्टी बिछा जाती थी. बुजुर्ग बताते हैं कि फसल इतनी अच्छी होती थी कि लोगों को परदेस जाकर कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. यही वजह है कि तब लोग कमला एवं बागमती में बाढ़ आए, इसके लिए पूजा-पाठ करते थे, लेकिन कालांतर में मानव निर्मित वजहों से बागमती ने अपना स्वभाव बदला, क्योंकि अब वह इलाके के किसानों एवं खेतिहर मज़दूरों के लिए उपजाऊ मिट्टी लाने वाली बागमती नहीं रही.

अनिल प्रकाश बताते हैं कि बागमती की यह दुर्गति 1954 के बाद से शुरू हुई. तटबंध बनाने का सिलसिला शुरू हुआ और बारह किलोमीटर की चौड़ाई में बहने वाली बागमती को तीन-चार किलोमीटर में बांध दिया गया. और तभी से हर साल तटबंध टूटते हैं, जल प्रलय आती है. बागमती बचाओ अभियान की वजह से फिलहाल इलाके में तटबंध का निर्माण कार्य रुका हुआ है और स्थानीय लोग निर्माण कार्य का विरोध कर रहे हैं. कोशी महाप्रलय के समय भी विशेषज्ञों ने कहा था कि यह गलत जल प्रबंधन का नतीजा है. इलाके के लोगों एवं पर्यावरणविदों ने विकास का प्रतीक कहे जाने वाले महासेतु का भी विरोध किया था. उनका कहना था कि पुल बनाकर कोशी का बहाव क्षेत्र कम किया गया है.

राज्य के कुल 38 जिलों में से 18 जिले हर साल बाढ़ की चपेट में आते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर जान-माल का नुक़सान होता है. ये जिले हैं, सुपौल, दरभंगा, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, खगड़िया, शिवहर, मधुबनी, अररिया, सहरसा, समस्तीपुर, मधेपुरा, किशनगंज, कटिहार, बेगूसराय एवं पूर्णिया. ग़ौरतलब है कि बिहार भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे अत्याधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है. राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र 94 लाख 20 हज़ार हेक्टेयर में से 68 लाख 80 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है, जो कुल बाढ़ प्रभावित इलाके का 73.3 प्रतिशत है. उत्तर बिहार के कुल 58 लाख 50 हज़ार क्षेत्र में से 44 लाख 50 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है. मतलब यह कि उत्तर बिहार का 77 प्रतिशत हिस्सा बाढ़ प्रभावित है.

जानकार बताते हैं कि मानसून की वर्तमान स्थिति देखकर बाढ़ की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता. मुजफ्फरपुर के कई गांवों में बागमती का पानी घुस आया है. बेगूसराय एवं गोपालगंज में भी बाढ़ का प्रभाव देखने को मिला. इसी बीच पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक की. उन्होंने कहा कि बाढ़ से बचाव की तैयारी में किसी भी स्तर की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. बैठक में कहा गया कि चौकीदार, होमगार्ड एवं मल्लाहों की सूची बना ली जाए और यह संकल्प दोहराया गया कि किसी भी हालत में बाढ़ पीड़ितों को कोई भी असुविधा नहीं होने दी जाएगी. बाढ़ का समय नजदीक आते ही सरकार की यह सारी कवायद शुरू हो जाती है. अनिल प्रकाश कहते हैं कि सरकार भोज के वक्त कोहरा रोपना शुरू कर देती है और साल भर चुपचाप बैठी रहती है. कोशी के सत्य नारायण चौधरी ने बताया कि आज भी ऐसे कई लोग हैं, जिन्हें पुनर्वास तो दूर, मुआवजा तक नहीं मिला.

ग़ौरतलब है कि सरकार हर साल बाढ़ को लेकर बैठकों का दौर शुरू करती है, कुछ फ़ैसले भी लिए जाते हैं, पर उन पर अमल नहीं किया जाता. राजद विधायक अब्दुल बारी सिद्दीकी कहते हैं कि स्पष्ट नीति के अभाव के चलते ही यह सारा खेल होता है. कोशी आपदा के समय भी जब खूब हो-हल्ला मचा, तो सरकार ने सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन को लेकर कहा था कि इस बारे में वह कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेगी, पर लगता है कि उसने इस मामले में हर स्तर पर समझौता कर लिया है. यह तो शुक्र मनाइए कि बारिश कम हो रही है, वरना सरकार के दावों की पोल अब तक खुल गई होती! ■ ***-साथ में शशि सागर***

feedback@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश

> सपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पिछड़ों में पहले जैसी पैठ नहीं बना पा रही है, क्योंकि पूर्व प्रदेशाध्यक्ष स्वर्गीय रामशरण दास की भरपाई उसके लिए चुनौती बनी हुई है. हालांकि सपा नेतृत्व ने जाटों को लुभाने के लिए अपने जाट नेता राजेंद्र चौधरी को आगे कर दिया है, लेकिन बात फिर भी नहीं बन रही है.

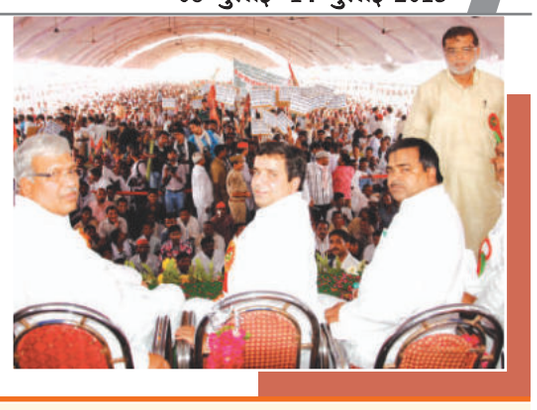

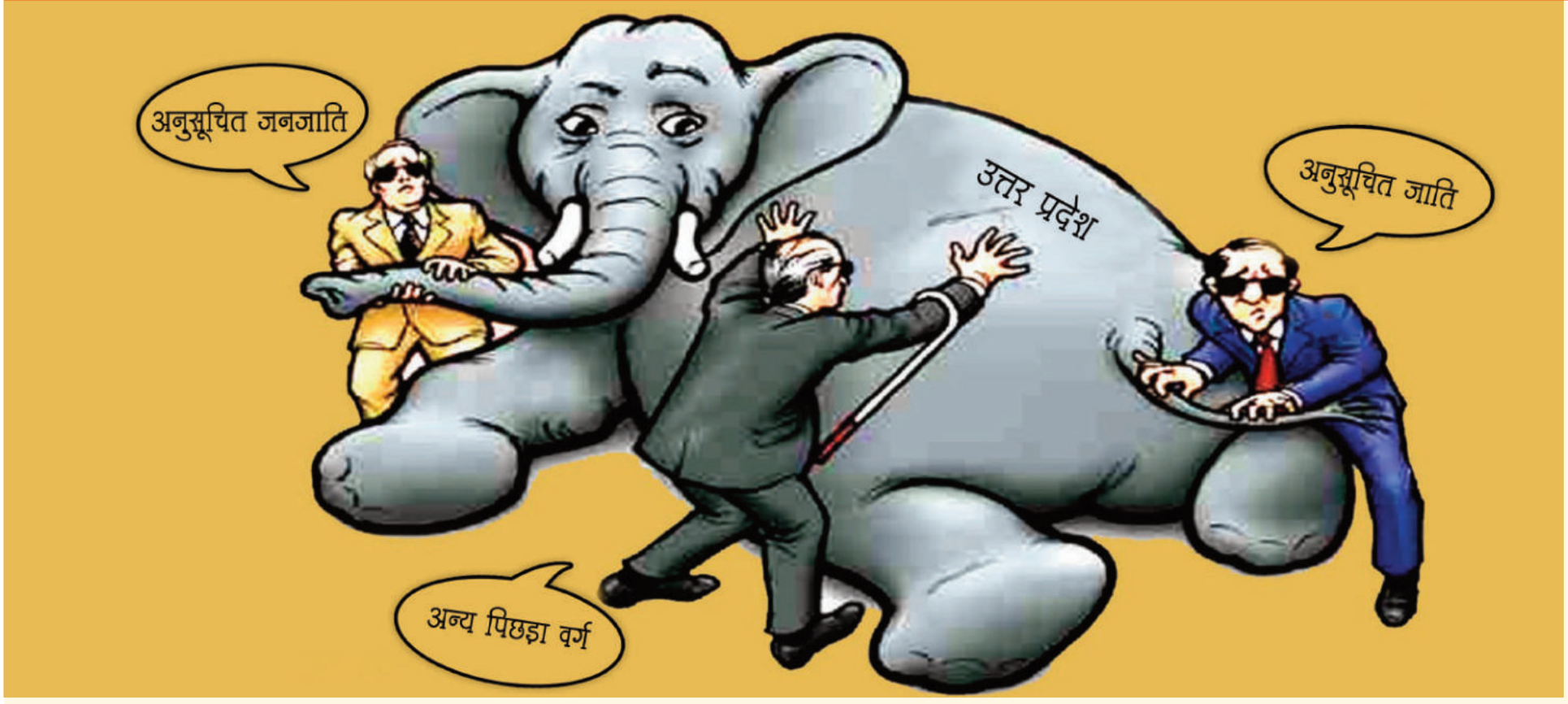

पिछड़े हैं, तो क्या ग़म है!

**देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में सियासी जोड़-तोड़ का खेल इन दिनों जोरों पर है. प्रत्येक राजनीतिक दल की नज़र पिछड़ा वोट बैंक पर है, जिसे अपनी तरफ़ करने के लिए तरह-तरह की जुगत भिड़ाई जा रही है. महत्वपूर्ण पदों पर पिछड़े वर्ग के नेताओं की ताजपोशी हो रही है, तो कहीं उन्हें लोकसभा भेजने का सब्जबाग भी दिखाया जा रहा है. पर्दे के पीछे और क्या खिचड़ी पक रही है, बता रहे हैं *अजय कुमार.*

अजय कुमार

सूबे की राजनीति में पिछड़ों की हमेशा अहम भूमिका रही है. इस समाज ने प्रदेश को न केवल कई बड़े नेता दिए, बल्कि इसके चार बड़े नेता मुख्यमंत्री तक बन चुके हैं. आज भी राज्य की कमान पिछड़े वर्ग से आने वाले अखिलेश यादव के हाथ में है. उनके पिता मुलायम सिंह भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं. इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्रियों, रामनरेश यादव एवं कल्याण सिंह की भी पिछड़ों में अच्छी-खासी पकड़ थी. दरअसल, जब भी किसी दल में मजबूत पिछड़े वर्ग के नेताओं का उभार हुआ, वह दल आसानी से सत्ता की सीढ़ियां चढ़ गया या फिर उसने प्रदेश की राजनीति में अपना ठोस आधार तैयार कर लिया. और दरअसल, इसीलिए आज भी प्रदेश की राजनीति में पिछड़े वर्ग से आने वाले नेताओं का दबदबा है. कांग्रेस नेता एवं केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल, बेनी प्रसाद वर्मा, भाजपा के हुकुम सिंह, राम नारायण साहू, शंकर प्रसाद जायसवाल, विनय कटियार, उमा भारती एवं कल्याण सिंह, बसपा के स्वामी प्रसाद मौर्य, लाल जी वर्मा, चंद्रदेव राम यादव, धर्म सिंह सैनी, राम अचल राजभर एवं सुखदेव राजभर, राष्ट्रीय लोकदल के नेता एवं केंद्रीय मंत्री चौधरी अजित सिंह, जयंत सिंह एवं सच्चिदानंद गुप्ता उर्फ मंत्री जी का नाम प्रमुखता के साथ लिया जा सकता है. समाजवादी पार्टी में तो पिछड़े वर्ग के नेताओं ने पूरी तरह आधिपत्य ही जमा रखा है. मुलायम सिंह यादव, राम गोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव, राम गोविंद चौधरी, अंबिका चौधरी एवं राम आसरे विश्वकर्मा जैसे नेताओं की लंबी-चौड़ी सूची है, लेकिन मुलायम सिंह के चलते कोई भी खुद को पिछड़े वर्ग का नेता नहीं कहता.

उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का क़रीब-क़रीब आधा हिस्सा पिछड़ों का है. इसलिए चाहे सत्ता में दावेदारी की बात हो या फिर आरक्षण का मुद्दा, सभी जगह यह वर्ग ताल ठोंककर खड़ा रहता है. राज्य में पिछड़ा वर्ग और समाज के अन्य वर्गों की स्थिति आधे में अध घर और आधे में सब घर जैसी है. दरअसल, आधी आबादी देखकर ही विभिन्न दलों द्वारा रणनीति बनाई और गोट बिछाई जाती है. हालात ऐसे हैं कि पिछड़ा होना आज गर्व की बात बन गया है. लोग कहते हैं कि पिछड़े हैं, तो क्या गम है! लोकसभा चुनाव 2014 के मद्देनज़र भी विभिन्न राजनीतिक दल एवं उनके आका पिछड़ों को लुभाने और अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गए हैं. न केवल पिछड़े वर्ग के नेताओं को खास तवज्जो दी जा रही है, बल्कि अगड़े वर्ग से आने वाले नेता भी खुद को पिछड़ों का मसीहा बताने की होड़ में हैं. मतलब यह कि प्रदेश की राजनीति में ताकत बढ़ाने एवं जातियों को लुभाने का हथकंडा इन दिनों खूब फल-फूल रहा है. मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में बसपा और सपा का मुस्लिम-ब्राह्मण प्रेम सुर्खियों में ज़रूर है, लेकिन अन्य जातियों पर भी उनकी नज़र है. किसी न किसी बहाने मतदाताओं को लुभाने के लिए कांग्रेस और भाजपा का अभियान भी जारी है. वोटों की इस जंग में छोटे दल भी जातियां जोड़कर नए समीकरण तलाश रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि दो-चार सीटें जीतकर बड़े दलों से सौदेबाजी की जा सकती है. छोटे दलों पर बड़े दलों की निगाहें हमेशा लगी रहती हैं. छोटे दलों में पीस पार्टी एवं अपना दल आदि का नाम लिया जा सकता है.

अनुप्रिया पटेल

कल्याण सिंह

डॉ. नेपाल सिंह

बेनी प्रसाद

श्री प्रकाश जायसवाल

राजेंद्र चौधरी

हुकूम सिंह

अजित सिंह

...पिछड़े पाएं सौ में साठ

विभिन्न राजनीतिक दलों के बड़े-बड़े नेता पिछड़ों की राजनीति के लिए हाथ-पैर मार रहे हैं. सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव तो पिछड़ा वोट बैंक के सहारे प्रधानमंत्री पद का भी सपना देख रहे हैं. बीते दिनों पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सोशलिस्टों ने पिछड़ों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने की पहल की थी और सपा ने उनकी अलग पहचान बनाई. उन्होंने कहा कि अन्य दलों का पिछड़ों से कुछ लेना-देना ही नहीं है. सपा का उनसे भावनात्मक लगाव है, इसलिए उनकी लड़ाई हमारी सामाजिक नीति का हिस्सा है. सपा सरकार पिछड़ों के हित में काम करेगी, पर असल चुनौती और संघर्ष का सामना आगामी लोकसभा चुनावों में करना होगा, क्योंकि प्रदेश में आपकी सरकार तो है, परंतु आपके अधिकार दिल्ली में कैद हैं, जिन्हें दिल्ली पर कब्जा करके ही पाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि सपा पर हमले तेज होने का अंदेशा है. पिछड़ों को बदनाम करने और उन्हें राजनीतिक ताकत न देने का षड्यंत्र चल रहा है, इसलिए उन्हें अपनी ताकत समझनी होगी. सपा पर जब भी संकट आया, पिछड़ों ने उसका साथ दिया. 1989 में पिछड़ों की मदद से ही सपा की सरकार बनी थी. अब दिल्ली हमारा लक्ष्य है और उसे हासिल करके ही हमें सामाजिक-राजनीतिक ताकत मिलेगी. उन्होंने याद दिलाया कि सोशलिस्टों ने ही सबसे पहले नारा दिया था, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पाएं सौ में साठ. संसद में जनगणना में जाति गणना करने की मांग की गई, तो भाजपा एवं कांग्रेस एक हो गए. अगर जाति गणना से पिछड़ों की तादाद का सही अंदाजा हो जाए, तो योजनाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है, इसीलिए उसमें रोड़े अटकाए जाते हैं. ■

विधानसभा चुनाव में छोटे दल कभी चमत्कार तो नहीं कर सके, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में पीस पार्टी, अपना दल, कौमी एकता दल एवं भारतीय समाज पार्टी के गठबंधन का असर ज़रूर देखने को मिला. पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारतीय समाज पार्टी, कौमी एकता दल, जनाधिकार मंच, फूलन सेना एवं जनवादी पार्टी आदि एकता मंच बनाकर लामबंद होने की प्रक्रिया में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. एकता मंच कुशवाहा, चौहान, मुसलमान, राजभर, निषाद, नाई, लोहार, कुम्हार, गोड़, खरवार, धोबी, पासवान, दुसाध, कमकर, कुंजड़ा, बिंद आदि जातियां जोड़कर क़रीब 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मंसूबा पाले हुए है. कुछ सीटों के लिए मंच ने प्रत्याशियों के नाम भी घोषित कर दिए हैं. एकता मंच के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर बताते हैं कि गाजीपुर से पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा, बलिया से पूर्व सांसद अफजल अंसारी, सलेमपुर से खुद ओमप्रकाश राजभर, आजमगढ़ से जनवादी पार्टी के ओमप्रकाश चौहान एवं वाराणसी से विधायक मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ेंगे. मंच के प्रत्याशियों में भी पिछड़ों के अच्छे-खासे नाम हैं. विधानसभा चुनाव में एकमात्र सीट जीतने वाले अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल की नज़र भी जातीय समीकरणों पर टिकी है. अनुप्रिया मुसलमानों के अलावा, पिछड़ों को भी साथ लाकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहती हैं.

पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी पिछड़ों की राजनीति परवान चढ़ रही है. राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के वर्चस्व वाले इस क्षेत्र में 54 फ़ीसद आबादी पिछड़ों की है. सपा ने भी विधानसभा चुनाव में यहां ठीक-ठाक सफलता हासिल की थी. बसपा दलितों एवं पिछड़े वर्ग में आने वाले गुर्जरों, जिनकी यहां अच्छी-खासी पकड़ है, को एक साथ नीले झंडे के नीचे लाने के लिए हाथ-पैर मार रही है. विधानसभा चुनाव में बसपा यह फॉर्मूला अपनाकर फ़ायदा भी उठा चुकी थी. उसके तीन गुर्जर प्रत्याशी विजयी रहे, लेकिन सपा का कोई भी गुर्जर या जाट प्रत्याशी नहीं जीत सका. अलबत्ता रालोद से एक (करतार सिंह भड़ाना) और भाजपा के दो गुर्जर (हुकुम सिंह एवं रवींद्र भड़ाना) विधानसभा पहुंचे. बसपा की खास उपलब्धि रालोद प्रमुख अजित सिंह के संसदीय क्षेत्र बागपत में सेंधमारी रही. लोकसभा चुनाव में भी बसपा यही फॉर्मूला आजमाते हुए प्रशांत चौधरी एवं मलूक नागर को आगे करके गुर्जरों को जोड़ने में लगी हुई है. बसपा नेता लखीराम, वेदराम भाटी, सतवीर एवं हेमलता चौधरी, जो कि पिछड़े वर्ग से आते हैं, बसपा की गोटें बिछाने में लगे हुए हैं.

सपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पिछड़ों में पहले जैसी पैठ नहीं बना पा रही है, क्योंकि पूर्व प्रदेशाध्यक्ष स्वर्गीय रामशरण दास की भरपाई उसके लिए चुनौती बनी हुई है. हालांकि सपा नेतृत्व ने जाटों को लुभाने के लिए अपने जाट नेता राजेंद्र चौधरी को आगे कर दिया है, लेकिन बात फिर भी नहीं बन रही है. मुलायम परिवार के अलावा, सपा में राजेंद्र चौधरी को सर्वाधिक प्रमुखता हासिल है. प्रवक्ता होने के अलावा, वह कारागार एवं खाद्य रसद मंत्री भी हैं. वैसे, पिछड़े वर्ग की विभिन्न जातियों पर सपा की असरदार पकड़ है. उसने गुर्जरों को लुभाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रखा है. इसीलिए राम सकल गुर्जर को विधान परिषद सदस्य एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्यमंत्री बनाया गया, वहीं नरेंद्र भाटी एवं वीरेंद्र सिंह को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया. हालांकि यह प्रयोग कितना सफल होगा, यह आने वाला समय ही बताएगा. राम सकल का कहना है कि गुर्जरों को सपा के अलावा, किसी ने इतना सम्मान नहीं दिया. पिछड़ों को उनका हक दिलाने में सपा सदैव आगे रही है.

भाजपा में बतौर पिछड़ा कार्ड, कल्याण सिंह की वापसी और मोदी की एंट्री को अहम माना जा रहा है. नेता विधायक दल पद पर हुकुम सिंह और विधान परिषद में नेपाल सिंह को पार्टी की कमान सौंपकर भाजपा पिछड़ों की सियासत में अगुवा बनना चाहती है. पार्टी आलाकमान ने पिछड़े वर्ग के गुर्जर अशोक कटारिया को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाकर उन्हें नए चेहरे के रूप में पेश किया है, वहीं लोधी समाज में साध्वी उमा भारती, कल्याण सिंह एवं उनके पुत्र राजवीर सिंह पर ही सारा दारोमदार रहेगा. जाटों पर पकड़ बनाने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सतपाल मलिक को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, वहीं पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष पद पर भूपेंद्र सिंह की ताजपोशी की गई. अति पिछड़ों को लुभाने के लिए भाजपा मोदी मंत्र पर भरोसा करेगी. भाजपा जाटों को यह बताने की कोशिश कर रही है कि उन्हें कहीं से आरक्षण नहीं मिलने वाला, लेकिन सत्ता में आने पर वह ज़रूर इस दिशा में काम करेगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

जमकर उड़ीं अनुशासन की धज्जियां

संजय सक्सेना

बीते 26 जून को इलाहाबाद के केपी कॉलेज मैदान में आयोजित समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के इलाहाबाद-चित्रकूट मंडल का मंडलीय सम्मेलन अनुशासनहीनता का शिकार हो गया. पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी और उनकी डांट-डपट के बावजूद कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ़ धक्का-मुक्की और मंच पर कब्जा करने का प्रयास किया, बल्कि स्थिति नियंत्रण करने के लिए बुलाई गई पुलिस से भी वे उलझ गए. ग़ौरतलब है कि यह सम्मेलन प्रदेश अध्यक्ष एवं एमएलसी नरेश उत्तम ने बुलाया था. उन्होंने एक 11 सूत्रीय प्रस्ताव भी पेश किया. हंगामे की शुरुआत उस समय हुई, जब वरिष्ठ सपा नेता रघुराज सिंह शाक्य सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. हुआ यह कि इलाहाबाद के सपा कार्यकर्ता अनीस अहमद विरोध दर्ज कराने के लिए अपने समर्थकों के कंधे पर सवार होकर मंच पर जबरन चढ़ने लगे. उनका कहना था कि पिछड़ा वर्ग के नाम पर बुलाए गए इस सम्मेलन में वर्ग विशेष की एक जाति विशेष, यानी यादवों की चर्चा हो रही है, जबकि मुसलमानों में भी पिछड़े वर्ग की कई जातियां हैं, लेकिन उनका कोई उल्लेख नहीं किया जा रहा है. इस पर इलाहाबाद मंडल के अध्यक्ष पंधारी यादव ने उन्हें फटकार लगाई, लेकिन अनीस एवं उनके समर्थकों का हो-हल्ला फिर भी जारी रहा. वे पंधारी यादव से भी उलझ गए, मामला हाथापाई तक जा पहुंचा.

इसी दौरान कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एवं सांसद धर्मेंद्र यादव और प्रदेश के राजस्व मंत्री अंबिका चौधरी भी वहां पहुंच गए. कार्यकर्ता एवं नेता उन्हें अपना चेहरा दिखाने के लिए एक बार फिर मंच पर चढ़ने का प्रयास करने लगे. अंबिका चौधरी एवं धर्मेंद्र यादव ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने. स्थिति नियंत्रण के लिए मौक़े पर आई पुलिस को भी सपा कार्यकर्ताओं की नाराज़गी का शिकार होना पड़ा. सम्मेलन को संबोधित करते हुए अंबिका चौधरी ने कहा कि आज़ादी के 65 वर्षों बाद भी पिछड़ों को उनका हक नहीं मिल सका. 27 प्रतिशत आरक्षण का तय कोटा भी पूरा नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट अक्षरशः लागू करने का श्रेय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को जाता है. सम्मेलन में इलाहाबाद, कौशांबी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, चित्रकूट एवं बांदा से आए हज़ारों कार्यकर्ताओं-समर्थकों ने हिस्सा लिया. धर्मेंद्र यादव ने अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि किसानों एवं पिछड़ों का सम्मान सिर्फ़ सपा की सरकार में होता है. पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राम आसरे विश्वकर्मा ने 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करके उन्हें सुविधाएं देने के लिए सरकार की प्रशंसा की. कार्यक्रम संयोजक एवं राज्य मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति ने सम्मेलन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला. अध्यक्षता नरेश उत्तम ने की.■

feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

एक और बात साफ हो गई कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) एक अप्रभावी संस्था है. एनडीएमए के अध्यक्ष श्री रेड्डी टीवी पर आए और उन्होंने यह कहा कि राष्ट्रीय आपदा की कोई परिभाषा नहीं है. यह बयान कितना हास्यास्पद है! एनडीएमए, जिस पर सरकारी पैसा खर्च किया जा रहा है और जिसके अध्यक्ष यह कहते हों कि राष्ट्रीय आपदा क्या है, हम नहीं जानते.

...तो फिर ऐसी संस्था की ज़रूरत क्या है

उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा पूरे देश के लिए शोक का विषय है. सेना और अर्द्धसैनिक बलों के जवानों ने दिन-रात जुटकर प्रभावित लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. लेकिन इस दौरान स्थानीय प्रशासन और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की निष्क्रियता ने कई सवाल पैदा कर दिए. पेश है, एक विचारोत्तेजक टिप्पणी.

पिछले कुछ दिन केदारनाथ एवं रुद्र प्रयाग क्षेत्र में भारी बाढ़ की त्रासदी और उसके बाद की घटनाओं के साक्षी रहे. विभिन्न टीवी चैनलों ने नागरिकों को बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को दिखाया. एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सेना, वायुसेना एवं अर्द्धसैनिक बलों ने सराहनीय कार्य किया है. उन्होंने अपने दम पर आपदा प्रबंधन का काम संभाला. नदी पार करना यात्रियों के लिए संभव नहीं था. वे लोग न सिर्फ़ हेलिकॉप्टर उड़ा रहे हैं, बल्कि उन्होंने जहां-तहां फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए पलटन एवं छोटे पुलों का निर्माण क्नह किया, ताकि यात्रियों को एक रस्सी पर लटका कर नदी पार कराई जा सके. यह सब वास्तव में हमारे लिए गर्व की बात थी. हमें निश्चित तौर पर सुरक्षाबलों को धन्यवाद देना चाहिए.

दूसरी ओर, यह भी स्पष्ट है कि इस दौरान नागरिक प्रशासन लोगों की आशाओं के विपरीत

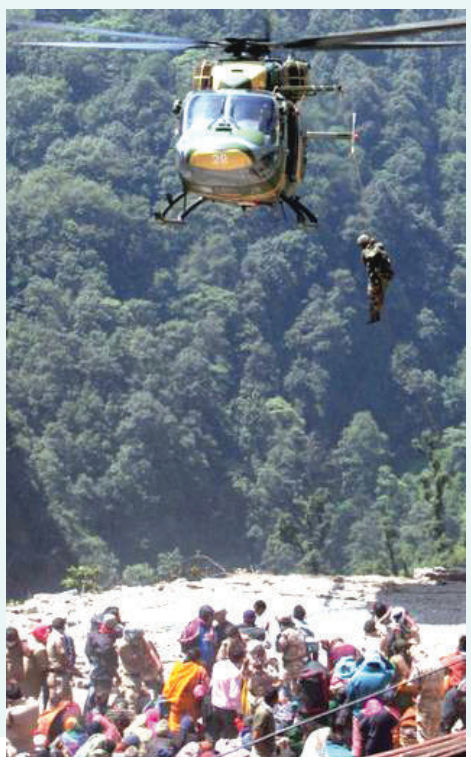

पूरी तरह विफल रही है. सिर्फ़ इन्हीं क्षेत्रों की बात नहीं है, बल्कि पूरे देश में सिविलियन अथॉरिटी की यही हालत है. वे इस तरह का काम करने के लिए सक्षम तक नहीं हैं. विशेष रूप से, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में सिविलियन अथॉरिटी की हालत और भी खराब है और यह इस वक्त उनकी कार्यप्रणाली और शैली देखकर समझा जा सकता है. यह उम्मीद थी कि एहतियाती तौर पर यहां की सिविलियन अथॉरिटी के पास कुछ तो उपाय होंगे, लेकिन अंतत: निराशा ही हाथ लगी. मैं नहीं जानता कि इस वक्त आपदा प्रबंधन के काम में उसका क्या योगदान है?

एक और बात साफ हो गई कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) एक अप्रभावी संस्था है. एनडीएमए के अध्यक्ष श्री रेड्डी टीवी पर आए और उन्होंने यह कहा कि राष्ट्रीय आपदा की कोई परिभाषा नहीं है. यह बयान कितना हास्यास्पद है! एनडीएमए, जिस पर सरकारी पैसा खर्च किया जा रहा है और जिसके अध्यक्ष यह कहते हों कि राष्ट्रीय आपदा क्या है, हम नहीं जानते. अगर एनडीएमए के अध्यक्ष को ही यह पता नहीं कि राष्ट्रीय आपदा क्या है तो इस संस्था का गठन क्यों किया गया?

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन सुनामी के बाद किया गया था. ऐसे प्राधिकरण का गठन इसलिए किया गया ताकि जब कोई आपदा हो तब राहत काम तेजी से हो सके. मुझे लगता है कि उत्तराखंड में इस वक्त आपदा प्रबंधन में भी इसका कोई खास रोल नहीं है. सरकार को यह अब तय करना पड़ेगा क्या हमें क्या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जरूरत है भी या नहीं क्योंकि आपदा प्रबंधन के प्रति संवेदनहीनता का आलम यह है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तीन साल से कोई मीटिंग तक नहीं हुई है. ■

feedback@chauthiduniya.com

संगठन और आंदोलन

अत: किसान और मज़दूर, दोनों का हित इसी में है कि कृषि से उत्पादित वस्तुओं का वाजिब दाम मिले और गांव में सुधरी हुई खेती एवं ग्रामोद्योग का जाल बिछे. आज किसान एवं मज़दूर, दोनों छोटे-छोटे मुद्दों को लेकर आपस में झगड़ते हैं. ऐसे में नगराधिष्ठित केंद्रित अर्थ-नीति इसका लाभ उठाकर दोनों का शोषण कर रही है. ये दोनों ही लूटे जाते हैं.

भारत का दारिद्र्य मिटाने के लिए किसान को आंदोलन की प्रेरणा की बात जैसे ही कही जाएगी, वैसे ही गांव में रहने वाला ग्रामीण फौरन कहेगा कि यह बात तो ठीक है, लेकिन किसान-मज़दूरों का संगठन होना असंभव है. प्रथम, ग्रामीणों का संगठन ही असंभव-सी बात है, ऐसा आम ग्रामीण सोचता है. साढ़े पांच लाख गांवों में बिखरे 50-55 करोड़ ग्रामीणों को एक सूत्र में कैसे बांधा जा सकता है? शहर में इकट्ठा रहने वाले थोड़े से मज़दूरों का संगठन आसान है, लेकिन लाखों गांवों में फैले और धर्म, जाति, दल, वर्ग में बंटे एवं बिखरे हुए करोड़ों व्यक्तियों का संगठन असंभव है. ऊपर-ऊपर से देखने में यह दलील अकाट्य मालूम होती है, लेकिन थोड़ी शांति के साथ सोचें, तो निरंतर शोषण के चलते क्षीण होकर समाप्त हो जाने और कठिन से कठिन काम संगठन द्वारा कर दिखाने के बीच, अगर कोई पर्याय न हो, तो मर-मिटने की बजाय कठिन काम करना कोई भी पसंद करेगा. जब हम यह देखते हैं कि असंभव माने जाने वाले कई काम पिछले 25-50 सालों में संभव हो गए हैं, तब निराशा के बादल छंटते हैं और उत्साह पैदा होता है. अहिंसा से निहत्थे लोगों को स्वराज्य मिलेगा, यह सन् 1947 के पूर्व गांधी जी एवं मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर किसने संभव माना था? जब कई असंभव काम संभव बन गए, तो ग्रामीणों के संगठन को भी संभव बनाना होगा.

किसान-मज़दूर एक आंदोलन के लिए कैसे संगठित होंगे? किसानों का हित अलग है और मज़दूरों का अलग, ऐसी मान्यता आम रूप से है. तथाकथित वामपंथियों ने गलत विचार के आधार पर इसे बढ़ावा दिया है. वास्तव में किसानों एवं मज़दूरों का हित-विरोध है ही नहीं. माल का वाजिब दाम मिले, तो मज़दूरों की मज़दूरी बढ़ाने के लिए परिस्थिति पैदा होती है, यानी वाजिब दाम दोनों के लाभ का मुद्दा है. यदि परिस्थिति पैदा होने पर भी किसान लोभ के कारण उसे न दे, तो मज़दूर इकट्ठा होकर उससे ले सकते हैं. लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर कुएं में पानी ही न हो, तो बाल्टी में कहां से आएगा? अत: किसान और मज़दूर, दोनों का हित इसी में है कि कृषि से उत्पादित वस्तुओं का वाजिब दाम मिले और गांव में सुधरी हुई खेती एवं ग्रामोद्योग का जाल बिछे. आज किसान एवं मज़दूर, दोनों छोटे-छोटे मुद्दों को लेकर आपस में झगड़ते हैं. ऐसे में नगराधिष्ठित केंद्रित अर्थ-नीति इसका लाभ उठाकर दोनों का शोषण कर रही है. ये दोनों ही लूटे जाते हैं. इन दोनों में किसान तगड़ा होने के कारण शोषण को अधिक से अधिक मज़दूर की ओर धकेल कर खुद को बचाना चाहता है.

आज ग्रामवासी ग़रीब हैं. ये ग़रीब लोग इकट्ठा होकर किस प्रकार का आंदोलन करेंगे? ग्रामीणों को अपनी निम्नलिखित त्रिविध शक्ति पहचाननी चाहिए:-

1 उनकी संख्या 100 में 75 से अधिक है. यह उनकी शक्ति है, जो अमेरिका या यूरोप में नहीं है.

2 वे प्राथमिक आवश्यकताएं पैदा करते हैं. अनाज के बिना किसी का काम नहीं चलता. कपास, गन्ना, जूट आदि कृषि में पैदा होने वाले कच्चे माल के बिना कारखाने नहीं चल सकते हैं. प्राथमिक आवश्यकताओं की मांग बे-लोचदार होती है, यानी उस मांग को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता. उस मांग का कोई विकल्प नहीं है. अत: किसान एक हो जाएं और वाजिब दाम की मांग करें, तो समाज को झुकना ही पड़ेगा.

3 किसान की मांग न्यायपूर्ण है. जीवन बीमा निगम या बैंक कर्मचारी या वायुयान सेवा में काम करने एवं हज़ार-दो हज़ार रुपये मासिक वेतन पाने वाले व्यक्ति अगर ग़रीब भारत में अधिक वेतन की मांग करें, तो उनकी मांग अनुचित है. लेकिन माल पैदा करने में जो खर्च हुआ, उसके आधार पर क़ीमत तय की जाए, यह मांग खेतिहर करता है, तो यह शत-प्रतिशत न्यायसंगत है. इससे कम कोई मांग हो ही नहीं सकती. किसान ज़्यादा भाव नहीं मांगता, बल्कि वह उचित भाव मांग रहा है. यह न्याय है और न्याय हमारे पक्ष में है, यही उसकी शक्ति है. इस प्रकार त्रिविध शक्तियुक्त यह त्रिशूल ग्रामीण यदि उपयोग में लाएगा, तो उसकी ताकत अजेय होगी.

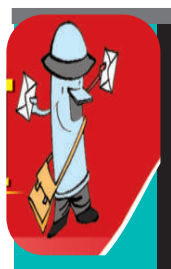

पाठकों की दुनिया

आज़ाद देश के गुलाम

मैं एक कड़वी सच्चाई की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. हमारे देश का यह दुर्भाग्य ही है कि कर्णधारों ने अंग्रेजों को हर समस्या के ताले की चाबी समझ लिया था. यदि अंग्रेजी से ही सब कुछ होना होता, तो अमेरिका मंदी का शिकार न होता. मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अंग्रेजी से देश से बेरोज़गारी दूर की जा सकती है? चीन ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली, जरा सोचिए, क्या इस तरक्की में अंग्रेजी का जरा भी हाथ है? सत्ता की नज़रों से देखें, तो हम पाएंगे कि हिंदी इस्तेमाल करने वालों की स्थिति दोयम दर्जे की ही दिखाई देगी. आप ही बताइए कि पूंजी एवं सत्ता की निरंकुशता के इस युग में और हो भी क्या सकता है. भारतीय प्रधानमंत्री अंग्रेजी बोलते हैं. केवल यही नहीं, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री एवं मानव संसाधन विकास मंत्री भी धड़ल्ले से अंग्रेजी बोलते हैं. सच तो यह है कि इन्हें देखकर यही लगता है कि ये हिंदुस्तान के नहीं, बल्कि इंग्लैंड के प्रतिनिधि हैं. यदि ये हिंदुस्तानी जनता के प्रतिनिधि होते, तो हिंदुस्तानी जनता की भाषा बोलते, इंग्लैंड की नहीं. जबकि सभी देशों के जन प्रतिनिधि अपने देश एवं जनता की भाषा बोलते हैं. अंग्रेजी बोलने के कारण विदेशों में अनेक बार अपमानित होने के बाद भी इन जन प्रतिनिधियों को तनिक भी शर्म नहीं आती, इन्हें राष्ट्र का स्वाभिमान झकझोरता नहीं है और इन्हें राष्ट्रभाषा का गौरव धिक्कारता नहीं है! पता नहीं, ये किस मिट्टी के बने हुए हैं?

-विकास कुमार पाटनी,
झुमरी तिलैया, झारखंड.

राजनीति का ककहरा पढ़ा

मुख्य आलेख-आडवाणी की चाणक्य नीति (24-30 जून) काफी अच्छा लगा. संतोष भारतीय के लेखन की सबसे खास बात यह है कि वह जो भी लिखते हैं, बेबाक लिखते हैं. इस आलेख में भी उन्होंने संघ पर दो टूक शब्दों में जो लिखा है, वह आंखें खोल देने वाला है. मैं पहले आडवाणी प्रकरण को ठीक से नहीं समझ पा रहा था, लेकिन भारतीय जी का आलेख पढ़ने के बाद आडवाणी की चाणक्य नीति न सिर्फ़ समझ पाया हूं, बल्कि उनकी नीतियों और आगे भारतीय राजनीति की संभावनाओं के बारे में लोगों से चर्चा भी कर सकता हूं. संतोष जी ने भाजपा एवं संघ के कद्दावर नेताओं को लेकर जो तर्क दिए हैं, उन्हें काटना मुश्किल है. उक्त नेता भले ही टीवी और समाचारपत्रों में बड़ी-बड़ी बातें करते नज़र आते हैं, लेकिन यह आलेख पढ़ने के बाद उनकी राजनीतिक चालों एवं इच्छाओं को अच्छी तरह समझा जा सकता है.

-महेश कुमार,
समस्तीपुर, बिहार.

गुरूर न कर...

अपने हिस्से का जीना,
चुपचाप जख्म सीना,
जयचंद कभी बनना,
देशद्रोही होता है कमीना!
गुरूर न कर तू बुलबुले,
इसने सब कुछ है छीना!
इंसानियत से महक गुलाब,
सदा बने रहना तुम नगीना!
जख्म जमाने को न दिखें,
नमक से बच, जख्मों को सीना!
यूं ही कुछ भी न मिले,
इसके लिए बहाया जाता है पसीना!
गैरों से ज़्यादा अपने दें पीर,
नैन नीर न बहा इन्हें तुम पीना!

-घनश्याम बेलानी,
कटनी, मध्य प्रदेश.

अन्ना जी, हम आपके साथ हैं

आलेख-अन्ना और मुसलमान पढ़ा. सबसे पहले जो ख्याल मेरे मन में आया, वह यह कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत...यह कहावत वयोवृद्ध समाजसेवी अन्ना हज़ारे पर बिल्कुल सटीक बैठती है. चौथी दुनिया को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि वह अन्ना को भरपूर कवरेज दे रहा है. हिंदू हों या मुसलमान, वे जाति-पात, धर्म के भेदभाव से परे हटकर भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों पर अन्ना को अपार समर्थन दे रहे हैं. अन्ना का प्रधानमंत्री को लिखा पत्र लाजवाब है. प्रधानमंत्री ने सचमुच अन्ना को ठगा है. यह सवाल मन में बार-बार उठता है कि प्रधानमंत्री ऐसा कैसे कर सकते हैं. मुझे देश के मुसलमानों की राय जानने की ललक थी, जो यह लेख पढ़ने से पता चली. अन्ना के आंदोलन के बारे में विभिन्न पार्टियों के नेताओं की ओछी सोच के बारे में भी पता चला. मैं अन्ना जी को सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने इस उम्र में यह बीड़ा उठाया है. सचमुच, अन्ना देश के सपूत हैं. हमें उनसे सीख लेनी चाहिए. हम उन्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि अन्ना जी, आप अपना आंदोलन जारी रखें, हम आपके साथ हैं.

-राकेश, *पटना, बिहार.*

बड़े मियां सुभानअल्लाह!

आलेख-बेटे से नाराज हैं पिता, पढ़ा. मुलायम सिंह पर तरस आता है. मन में यह सवाल भी उठता है कि क्या उन्हें उत्तर प्रदेश की याद आज ही आई है? क्या उत्तर प्रदेश में क़ानून व्यवस्था की स्थिति उनके समय में खराब नहीं थी, या फिर यह जनता को भरमाने की कोशिश भर है.

-शिवानी,
औरंगाबाद, बिहार.

कांग्रेस को हताशा हाथ लगी

मैं चौथी दुनिया का नियमित पाठक हूं. इस अखबार में छपी रिपोर्टें सच्चाई से रूबरू कराती हैं. उपचुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस का सपना चकनाचूर हो गया है, सही लिखा है लेखक ने. यह सच है कि गुजरात में जीत के कारण भाजपा के हौसले बुलंद हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस को सिर्फ हताशा ही हाथ लगी है.

-अश्विन कुमार,
दरभंगा, बिहार.

पाठक पूरे नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें:

चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

मुसलमानों को राजनीतिक ताकत बनना चाहिए

चुनाव नज़दीक आते दिख रहे हैं और मुसलमानों को लेकर हलचल भी तेज हो गई है. उर्दू के सबसे बड़े टेलीविजन चैनल ईटीवी ने जयपुर में दस घंटे का अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर एक सेमिनार किया, जिसमें अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों के नाम पर मुसलमान थे और गैर अल्पसंख्यकों के नाम पर राजनीतिक दलों के नेता थे, जिनमें बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के थे. कांग्रेस की तरफ़ से दो केंद्रीय मंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया. कुछ धार्मिक नेता थे और कुछ ऐसे लोग भी थे, जो न राजनेता हैं और न धार्मिक नेता.

यह अपनी तरह का चौथा सेमिनार था, जिसमें अल्पसंख्यकों की समस्याओं को रेखांकित करने की कोशिश की गई. सेमिनार में कई चीजें देश के लोगों के सामने उजागर हुईं. पहली, मुस्लिम राजनेताओं को मुसलमानों की समस्याओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था. इस सेमिनार में विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रहमान खान, दोनों ने भाषण दिया. सबसे पहला भाषण सलमान खुर्शीद का था. सलमान खुर्शीद न केवल समझदार हैं, बल्कि एक अच्छे वकील भी हैं, लेकिन जब मुसलमानों की समस्याओं की बात हो और सेमिनार में ज़्यादातर मुस्लिम नेता हों, तो कम से कम यह अपेक्षा थी कि सलमान खुर्शीद अपना राजनीतिक चेहरा एक तरफ़ रखेंगे, बड़े वकील का चेहरा दूसरी तरफ़ रखेंगे और अपना असली चेहरा, अपनी असली समझ सामने लाकर पहली बार मुसलमानों को यह बताएंगे कि वह उनके सच्चे हमदर्द हैं और उनकी समस्याओं को जानते हैं. लेकिन सलमान खुर्शीद ने, जिन नकाबों को उतार देना चाहिए था, उन्हें और कसकर अपने चेहरे पर लगा लिया. सारे देश को उन्होंने यह बताया कि वह मुसलमानों की समस्याओं को कोई तरजीह नहीं देते और उनकी समस्याएं दूर करने में मुस्लिम कौम के एक प्रतिनिधि होने के नाते भी कोई तवज्जो नहीं देते. शब्दों की बाजीगरी दिखाकर उन्होंने यह फिर साबित किया कि जैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनावों में मुसलमानों को नौ प्रतिशत आरक्षण देने का वादा कांग्रेस की तरफ से कराया था, वैसे भ्रम वाले बयान ही उनके असली बयान हैं. उस समय यह बात उठी थी कि सलमान खुर्शीद क्यों नहीं उन राज्यों में मुसलमानों को नौ प्रतिशत आरक्षण केंद्र सरकार की तरफ़ से मुख्यमंत्रियों से कहकर दिला देते, जहां कांग्रेस का शासन है. लेकिन उस समय भी सलमान खुर्शीद चुप रहे और अब भी वह मुसलमानों को आरक्षण देने के नाम पर बिल्कुल खामोश हैं. दरअसल, यह सलमान खुर्शीद की धर्मनिरपेक्षता है, जो चुनाव के समय सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देती है और उनकी कौम, यानी मुसलमानों को डर के साथ कोने में खड़ा रखने में रोल प्ले करती है. वैसे तो, हिंदुस्तान के मुसलमान सलमान खुर्शीद को अपना प्रतिनिधि नहीं मानते और सेमिनार में मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने यह कहा भी कि उन्हें सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं से ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, बनिस्बत उन नेताओं के, जो मुसलमानों का खुला विरोध करते हैं.

के रहमान खान अपने विभाग द्वारा किए गए कामों का ढिंढोरा पीटते नज़र आए. उन्होंने यह भी बता दिया कि इस देश का मुसलमान अंधा है, जाहिल है, बेवकूफ है, जो अपने आसपास होने वाले विकास को देख नहीं पा रहा है. के रहमान खान का कहना है कि सच्चर कमेटी की 69 सिफारिशों में से 66 सिफारिशें पूरी कर ली गई हैं. अब यह हिंदुस्तान का मुसलमान है, जो अक्ल से अंधा है और के रहमान खान के दिखाए हुए सच्चर कमेटी की सिफारिशों पर अमल को देख नहीं पा रहा है. सवाल यह उठता है कि के रहमान खान सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को क्या समझते हैं, सच्चर कमेटी को क्या समझते हैं और रंगनाथ मिश्र आयोग को क्या समझते हैं? बहुत सारे लोगों का मानना है, जिसे शायद के रहमान खान नहीं मानते कि सच्चर कमेटी बीमारी की डायग्नोसिस है, बीमारी की पहचान है, लेकिन बीमारी का इलाज रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट में ही है. रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट कितनी लागू की गई, इस पर के रहमान खान खामोश हैं, क्योंकि वह और उनकी सरकार रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट लागू ही नहीं करना चाहते थे. चौथी दुनिया में वह रिपोर्ट इस ख़तरे के साथ छापी गई कि संभव है, झूठी धाराएं लगाकर परेशान किया जाए. हमने वह रिपोर्ट चौथी दुनिया में छापी. उस समय के रहमान खान राज्यसभा में उप सभापति थे और उन्होंने वह रिपोर्ट राज्यसभा में लाने से भरसक रोका. यह तो भला हो लोकसभा का, जहां 25 से ज़्यादा सांसद चौथी दुनिया की प्रतियां लेकर खड़े हो गए, तो प्रधानमंत्री को ऐलान करना पड़ा कि वह रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट टेबिल करेंगे. रिपोर्ट सदन में रखना एक चीज है और रिपोर्ट पर अमल करना दूसरी चीज. आज के रहमान खान रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट पर खामोश हैं और ऐसा लग रहा है कि वह भी मुसलमानों को धोखा देने में वही रोल प्ले कर रहे हैं, जैसा आज तक कांग्रेस अदा करती आई है.

दरअसल, कांग्रेस मुसलमानों के लिए हमेशा वादे करती है, लेकिन उन्हें पूरा नहीं करती. उसे मालूम है कि मुसलमान उसके सिवाय आख़िर कहां जाएंगे? वे भारतीय जनता पार्टी के पास जा नहीं सकते. समाजवादी पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी की पहचान पूरे देश में नहीं है और जदयू भी अपने प्रदेश में सिमटा हुआ है. इसलिए सारे देश में मुसलमान कांग्रेस के साथ जाएंगे ही जाएंगे, ऐसा कांग्रेसी नेताओं का विश्वास है और उसी विश्वास ने मुसलमानों को कांग्रेस के यहां बंधुआ बना रखा है. जितने भी बड़े मुसलमान नेता हैं, चाहे वे मजहबों के हों, इदारों के हों, स्कूलों में पढ़ाने वाले हों, या जो भी यह दावा करे कि मुसलमान उसके कहने पर चलते हैं, उन सबके लिए कांग्रेस की दुकान में सामान रखा हुआ है. वे चुनाव के समय जाते हैं और अपने हिस्से का सामान उठा लेते हैं. मुझे यह कहते हुए बहुत संकोच हो रहा है, लेकिन अब इस सत्य को मुस्लिम समाज भी बुरी तरह तकलीफ के साथ समझने लगा है. यह समझदारी ही मुसलमानों के इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल स्टेटस के लिए एक आशा है.

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी सेमिनार में उपस्थित थे. उन्होंने मुसलमानों से भावनात्मक अपील की कि वे उनके साथ आएं और उन्हें अछूत न समझें. वह मुसलमानों को देश का हिस्सा मानते हैं. लेकिन शायद राजनाथ सिंह जब बोल रहे थे, तो टीवी कैमरे पर देश के लोग आवाज़ तो उनकी सुन रहे थे, लेकिन चेहरा नरेंद्र मोदी का देख रहे थे. यह एक अजीब मनोवैज्ञानिक स्थिति देश में पैदा हो गई है कि नरेंद्र मोदी का सौम्य चेहरा लोगों के सामने आ ही नहीं रहा है. जब नरेंद्र मोदी कहते हैं, सर्वे भवंतु सुखिन: तो वह सिर्फ़ हिंदू भवंतु सुखिन: की बात नहीं करते, बल्कि वह सबके भले की कामना करते हैं. फिर भी लोगों को यही लगता है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं. नरेंद्र मोदी की मुस्कुराहट के पीछे लोगों को मोहन भागवत की मुस्कुराहट नज़र आती है. ऐसा सच है या नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन देश में जो भी लोग टेलीविजन पर राजनाथ सिंह को बोलते हुए देखते हैं, उन्हें नरेंद्र मोदी का चेहरा नज़र आता है और जब नरेंद्र मोदी बोलते हैं, तो उनके पीछे उन्हें मोहन भागवत एवं प्रवीण तोगड़िया का चेहरा नज़र आता है. यही भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है कि वह जो बोल रही है, वैसा ही चेहरा लोगों को नज़र आए. इसके लिए भाषा बोलते हुए किस तरह की शारीरिक लोच या चेहरे पर सौम्यता नज़र आनी चाहिए, उस पर वह ध्यान नहीं देती.

मुसलमानों के धार्मिक गुरु, जिन्होंने इस सेमिनार में भाषण दिए, उन्होंने समझदारी से अपनी बातें रखीं, लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि इन मुस्लिम धर्मगुरुओं की पार्टियों को भी आम मुसलमान वोट नहीं देता. हालांकि जिस शख़्स के भाषण की सबसे ज़्यादा तारीफ़ हुई, वह स्वामी अधोक्षानंद थे, जिन्हें पुरी के शंकराचार्य का पट्ट शिष्य माना जाता है. उन्होंने जिस तरह सफाई से अपनी बातें रखीं, उसे सारे देश के लोगों ने स्वीकार किया, पर स्वामी अधोक्षानंद साधुओं की जमात में अल्पमत में है. साधुओं का बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं नरेंद्र मोदी के साथ है. नरेंद्र मोदी के धनवान शिष्यों ने उन साधुओं को सारे देश में घुमाने और उनके जरिए देश में हिंदू राज्य का ध्वजवाहक होने का संदेश मोदी के लिए फैलाना शुरू कर दिया है. आज यह संदेश धार्मिक बंटवारे की सबसे निचली सीढ़ी पर है, लेकिन कल हो सकता है कि यह सबसे ऊंची सीढ़ी पर पहुंच जाए और उस समय यह देश दंगों की एक नई आग में घिर जाएगा.

मुसलमानों के सामने कई मुसीबतें हैं. पहली मुसीबत, हर राजनीतिक नेता मुसलमानों को इस पार्टी या उस पार्टी में देखना चाहता है. वह मुसलमानों को रोजी-रोटी, शिरकत और नेतृत्व के सवाल पर साफ़ बात बताता ही नहीं है. दूसरी, धार्मिक नेता एक साथ बैठकर यह तय नहीं कर पाते कि उन्हें मुसलमानों से क्या कहना चाहिए. सच तो यह है कि कोई भी धार्मिक नेता दूसरे धार्मिक नेता के साथ मिलकर, जब तक यह तय न हो जाए कि वह खुद सर्वोच्च है, मुसलमानों को सही बात बताना ही नहीं चाहता. इसका नतीजा यह कि पूरी मुस्लिम कौम एक तरफ़ अपने नेताओं की चालाकी और दूसरी तरफ़ धार्मिक नेताओं की आपसी जलन से परेशान है. हो सकता है, वह इन चुनावों में अपने दर्द एवं तकलीफ को महसूस करके कुछ और फ़ैसला करे, लेकिन वह फ़ैसला भी राजनीतिक तौर पर किसी तरफ़ असर करता नहीं दिखाई देता, क्योंकि आज मुसलमान खुद को राजनीतिक ताकत के रूप में संगठित नहीं कर पा रहा है.

मुसलमानों को यह समझ में नहीं आता कि जब तक वे अपने प्रतिनिधि दूसरी कौमों के साथ मिलकर नहीं भेजेंगे और उन्हें यह भरोसा नहीं दिलाएंगे कि उनके प्रतिनिधि भेजने में उनका भी हिस्सा होगा, तब तक इस देश में मुसलमानों की न तो कोई राजनीतिक हैसियत बनेगी, न उनकी ज़िंदगी में कोई बदलाव आ पाएगा और न ही राजनीति में वे दबाव डाल पाएंगे. सबसे ग़रीब तबका होने के नाते मुसलमानों को दलितों एवं पिछड़ों के साथ एकता की कोशिश करनी चाहिए. दूसरी तरफ़ दलित एवं पिछड़े हैं, जो राजनीतिक तौर पर बंटे हुए हैं और जिन्हें मुसलमानों के साथ यह समझना चाहिए कि जब तक वे किसी राजनीतिक पार्टी के कब्जे में रहेंगे, तब तक उनके हितों के लिए कुछ नहीं होगा. यह बहुत बड़ा सवाल है कि दलितों की पार्टी ने दलितों के लिए और पिछड़ों की पार्टियों ने पिछड़ों के लिए आज तक क्या किया? मुसलमान अगर पार्टी बना लेंगे, तो वे नुक़सान में रहेंगे. वे अगर किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे, तो वहां बंधुआ कौम के रूप में जाने जाएंगे. इसका मतलब यह कि देश के ग़रीब तबकों, जिनमें दलित, पिछड़े एवं मुसलमान बड़ी संख्या में हैं, को राजनीतिक दलों की गुलामी से बाहर निकलना होगा और एक दबे-कुचले वर्ग के रूप में अपनी ताकत बनानी पड़ेगी. यह ताकत वोट की ताकत है. यह वर्ग अपने प्रतिनिधि लोकसभा एवं विधानसभा में भेजे, न कि राजनीतिक पार्टियों के दलालों के रूप में अपने प्रतिनिधि वहां भेजे.

कोई भी राजनीतिक पार्टी जिस वर्ग का समर्थन लेती है, उसके पक्ष में आज तक एक भी फ़ैसला नहीं कर सकी, क्योंकि हमारे देश का संविधान राजनीतिक पार्टियों को मान्यता ही नहीं देता. संविधान में राजनीतिक पार्टियों का कोई रोल नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों ने हमारे संविधान पर कब्जा कर लिया है और उसी तरह गुलाम बना लिया है, जिस तरह अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को गुलाम बनाया था. मुसलमानों, दलितों एवं पिछड़ों को हिंदुस्तान का संविधान पढ़ने की ज़रूरत है. हमारा संविधान लोगों को लोकसभा एवं विधानसभाओं में भेजने की बात करता है, राजनीतिक दलों को नहीं. मुस्लिम नौजवान, आलिम एवं मुस्लिम पत्रकार अगर इस कैच, इस मसले को नहीं समझेंगे, तो वे एक बार फिर अपनी कौम को राजनीतिक दलों के हाथों गिरवी रख देंगे और किसी भी राजनीतिक दल, चाहे वह कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, जदयू हो या कोई और, में उनके प्रतिनिधि मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के लिए काम करते नज़र आएंगे. नाम वे मुसलमानों का लेंगे, लेकिन काम मुसलमानों के ख़िलाफ़ करेंगे. ■

editor@chauthiduniya.com

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी सेमिनार में उपस्थित थे. उन्होंने मुसलमानों से भावनात्मक अपील की कि वे उनके साथ आएं और उन्हें अछूत न समझें. वह मुसलमानों को देश का हिस्सा मानते हैं. लेकिन शायद राजनाथ सिंह जब बोल रहे थे, तो टीवी कैमरे पर देश के लोग आवाज़ तो उनकी सुन रहे थे, लेकिन चेहरा नरेंद्र मोदी का देख रहे थे.

भाग-4

संविधान में राजनीतिक दल का जिक्र नहीं है

स्वतंत्रता की रक्षा हर क़ीमत पर होनी चाहिए

संविधान बनने के बाद केंद्र और राज्य की शक्तियों को लेकर कई सवाल उठे. ऐसा इसलिए भी हुआ, क्योंकि लोगों को इस विषय की पर्याप्त जानकारी नहीं थी या फिर वे इस व्यवस्था-प्रावधान को ठीक से समझ नहीं सके थे. पहले आरोप के बारे में आपने पिछले अंक में पढ़ा, अब आपको हम दूसरे आरोप के बारे में बता रहे हैं...

दूसरा आरोप यह लगता रहता है कि केंद्र को जो शक्तियां दी गई हैं, उन्हें वह राज्यों पर थोपता है. इस आरोप पर यहां ज़रूर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उक्त शक्तियों को लेकर संविधान की निंदा करने से पहले कुछ बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है. सबसे पहली बात यह कि उक्त शक्तियां संविधान की साधारण तस्वीर नहीं पेश करतीं. उक्त शक्तियों का प्रयोग और उनका संचालन सिर्फ़ आपातकाल में ही होता है. दूसरी बात यह ध्यान देने लायक है कि क्या केंद्र को जो शक्तियां मिली हुई हैं, उनका प्रयोग हम आपातकाल लागू होने पर रोक सकते हैं? जो लोग आपातकाल में केंद्र की उक्त शक्तियों को लेकर न्याय नहीं करना चाहते, समझिए कि उन्हें इस समस्या के बारे में ठीक से पता ही नहीं है कि आखिर इसकी जड़ कहां है. एक मशहूर पत्रिका में एक लेखक ने इस समस्या के बारे में बहुत साफ़-साफ़ बताया है. राउंड टेबल पत्रिका के दिसंबर, 1935 के अंक में छपे उक्त आलेख के लिए मैंने कोई क्षमा नहीं मांगी थी.

उक्त आलेख में कहा गया है, राजनीतिक व्यवस्था अधिकारों एवं कर्तव्यों को लेकर एक पूर्वाग्रह है, जो इन सवालों पर निर्भर करता है कि संस्था किसके लिए है और इस संस्था का क्या मतलब है? क्या नागरिकों के दिल में इसके प्रति स्वामिभक्ति के लिए कोई जगह है? साधारण तौर पर इस सवाल का जवाब नहीं मिलता. क़ानून को मानने वाले और ऐसे व्यक्ति, जो अपना व्यवसाय कर रहे हैं, सिर्फ़ एक ही संस्था की बात मान सकते हैं. संकट के समय शिकायतों को लेकर विवाद उठ सकते हैं. स्वामिभक्ति के मुद्दे का निर्धारण भी न्यायिक दखलंदाजी से संभव नहीं हो सकता. क़ानून इन तथ्यों को स्वीकार कर सकता है, लेकिन यह उसके लिए ठीक नहीं होगा. सारी औपचारिकताओं से पर्दा हटने के बाद एक बड़ा सवाल यह उठता है कि संस्था ने नागरिकों की विश्वास बहाली के लिए क्या किया? सवाल यह भी है कि यह केंद्र है या फिर संवैधानिक राज्य?

इस समस्या का समाधान सिर्फ़ एक के जवाब पर निर्भर करता है, जो इस समस्या का महत्वपूर्ण अंग है. इसमें कोई दो राय नहीं कि अधिकांश लोग केंद्र की इस शक्ति के पक्ष में हैं. लोगों का मानना है कि आपातकाल में नागरिकों की जवाबदेही सिर्फ़ केंद्र के प्रति होनी चाहिए, न कि राज्यों के. उनका यह भी मानना है कि सामान्य जनों की रुचि और वे क्या चाहते हैं, इसका ख्याल सिर्फ़ केंद्र ही रख सकता है, यह राज्यों द्वारा संभव नहीं है. जनमत को देखते हुए ही केंद्र को आपातकाल में कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं. सिर्फ़ उन्हीं लोगों को इसके ख़िलाफ़ शिकायत है, जो इसे नहीं समझ सके. हालांकि अब मैं इन चीजों को समाप्त कर सकता हूं. मैं अपने देश के भविष्य को लेकर आशान्वित हूं. 26 जनवरी, 1950 को भारत स्वतंत्र देश बना. भारत के स्वतंत्र घोषित होने से क्या हुआ? क्या इसने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की या यह अपनी स्वतंत्रता फिर से खो देगा? यह पहला सवाल था, जो मेरे मस्तिष्क में आया. ऐसा नहीं था कि भारत कभी स्वतंत्र देश नहीं था. बड़ा सवाल यह था कि भारत फिर एक बार अपनी स्वतंत्रता खो देगा. क्या यह दूसरी बार अपनी स्वतंत्रता खो देगा? यह एक ऐसी सोच थी, जिसने भविष्य को लेकर मेरे अंदर जिज्ञासा भर दी.

सबसे ज़्यादा मैं इस बात को लेकर चिंतित था कि भारत फिर से एक बार सिर्फ़ अपनी स्वतंत्रता ही नहीं खो देगा, बल्कि यह भारतीयों के साथ विश्वासघात भी होगा. मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर चढ़ाई के दौरान राजा दाहर के सेनापति ने अपने राजा की तरफ़ से न लड़ने के लिए मोहम्मद बिन कासिम के एजेंट से रिश्वत ली थी. जयचंद ने मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने और पृथ्वीराज के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए आमंत्रित किया था. जयचंद ने मोहम्मद गोरी से वादा किया था कि वह उसकी और सोलंकी राजाओं की मदद करेगा. जब शिवाजी हिंदुओं की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, तो उस समय अन्य मराठा एवं राजपूत राजाओं ने मुगल शासकों की तरफ़ से युद्ध किया था. जब अंग्रेज सिख शासक गुलाब सिंह के शासन को तहस-नहस करने का प्रयास कर रहे थे, तो उनका मुख्य सेनापति चुपचाप बैठा रहा और उसने सिख राज्य की रक्षा का कोई प्रयास नहीं किया. 1857 में जब भारत के एक बड़े हिस्से में स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के ख़िलाफ़ लड़ाई का बिगुल फूंक दिया गया, तो उस समय सिखों ने खड़े होकर सिर्फ़ उसे देखा.

क्या इतिहास फिर से इन सभी चीजों को दोहराएगा? ये ऐसे विचार हैं, जिनके बारे में जब मैं सोचता हूं, तो चिंतित हो जाता हूं. इस चिंता से इस बात को बल मिलता है कि हमारे पुराने दुश्मन अब जाति एवं धर्म के नए रूप में हमारे सामने हैं. हम लोग विभिन्न राजनीतिक दलों के उलटे सिद्धांतों को मानने लगे हैं. क्या भारतीय इन सिद्धांतों को लेकर अपने देश के साथ समझौता कर सकते हैं या इन्हें अपने देश से ज़्यादा तवज्जो दे सकते हैं? मैं नहीं जानता, लेकिन यह निश्चित है कि अगर किसी दल ने अपने सिद्धांतों को देश के ऊपर रखने की कोशिश की, तो हमारी स्वतंत्रता दूसरी बार ख़तरे में पड़ सकती है और हो सकता है कि हम अपनी स्वतंत्रता हमेशा के लिए खो दें. अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमें अपने खून के आख़िरी कतरे तक लड़ना चाहिए. ■

(अगले अंक में आप 26 जनवरी, 1950 को भारत के प्रजातांत्रिक देश बन जाने के बारे में पढ़ेंगे.)

feedback@chauthiduniya.com

डॉ. बी आर अंबेडकर

क़ानून को मानने वाले और ऐसे व्यक्ति, जो अपना व्यवसाय कर रहे हैं, सिर्फ़ एक ही संस्था की बात मान सकते हैं. संकट के समय शिकायतों को लेकर विवाद उठ सकते हैं. स्वामिभक्ति के मुद्दे का निर्धारण भी न्यायिक दखलंदाजी से संभव नहीं हो सकता. क़ानून इन तथ्यों को स्वीकार कर सकता है, लेकिन यह उसके लिए ठीक नहीं होगा. सारी औपचारिकताओं से पर्दा हटने के बाद एक बड़ा सवाल यह उठता है कि संस्था ने नागरिकों की विश्वास बहाली के लिए क्या किया? सवाल यह भी है कि यह केंद्र है या फिर संवैधानिक राज्य?

सूचना अधिकार

बीपीएल चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता कैसे आएगी?

RIGHT TO INFORMATION

चौथी दुनिया ब्यूरो

इस अंक में हम एक ऐसी समस्या पर बात कर रहे हैं, जो सीधे-सीधे ग़रीबों के अधिकारों और विकास से जुड़ी हुई है, यानी बीपीएल सूची, जिसके आधार पर ग़रीबों को बहुत-सी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है, मसलन सस्ता राशन, इंदिरा आवास या फिर पेंशन. जिस देश की अधिकांश आबादी ग़रीब हो, वहां यह ज़रूरी हो जाता है कि ग़रीबों से जुड़ी योजनाएं ईमानदारी से लागू की जाएं. लेकिन व्यवहार में अब तक यही देखने को मिला है कि ग़रीबों के विकास के लिए बनाई गईं लगभग सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है, चाहे वह मनरेगा हो या इंदिरा आवास योजना. इसीलिए इन योजनाओं का फ़ायदा उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, जो इसके हक़दार होते हैं या जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. ग़रीबों के लिए बनी योजनाओं में घोटाले की ख़बरें आएदिन आती रहती हैं.

ज़ाहिर है, सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए बहुत सारे लोग किसी भी प्रकार से अपना नाम बीपीएल सूची में शामिल करा लेते हैं, नतीजतन, जो ज़रूरतमंद लोग हैं और जिन्हें वाक़ई सरकारी मदद की ज़रूरत होती है, वे इससे वंचित रह जाते हैं. कई राज्यों में तो बीपीएल सूची में एपीएल श्रेणी के लोग भी अपना नाम दर्ज करा लेते हैं. ज़ाहिर है, ऐसा सरकारी अधिकारियों एवं स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधियों (पंचायत प्रतिनिधियों) की मिलीभगत के बिना संभव ही नहीं है. इस अंक में ऐसा ही एक आवेदन प्रकाशित किया जा रहा है, जिसके इस्तेमाल से आप बीपीएल सूची में पारदर्शिता लाने का दबाव डाल सकते हैं और साथ ही सूची तैयार करते समय उसमें होने वाली गड़बड़ियों को पकड़ या उनका ख़ुलासा कर सकते हैं. हम उम्मीद करते हैं कि आप इस आवेदन का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है:

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)
उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप
(बीपीएल के चयन के लिए हुए सर्वे का विवरण)

सेवा में, दिनांक.....
लोक सूचना अधिकारी
विभाग का नाम.....
विभाग का पता.....

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत आवेदन.

महोदय,

.....ग्राम में ग़रीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के सर्वे के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं प्रदान करें:-

1. उपरोक्त गांव में ग़रीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्डधारक कितने हैं? उनकी सूची निम्नलिखित विवरण के साथ उपलब्ध कराएं:-
   क. कार्डधारक का नाम.
   ख. पिता का नाम.
   ग. कार्ड संख्या.
   घ. कार्ड पर सदस्यों की संख्या (यूनिट).

2. उपरोक्त कार्डधारकों का ग़रीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) का कार्ड किस आधार पर बनाया गया? इस संबंध में कार्डधारक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों की प्रतियां उपलब्ध कराएं.

3. उपरोक्त गांव में ग़रीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों का सर्वे पिछली बार कब हुआ था? उस सर्वे रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराएं, साथ ही सर्वे करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं पद बताएं.

4. ग़रीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों के सर्वे के समय चयन के लिए क्या मापदंड/मानक बनाए गए हैं? इस संबंध में समस्त शासनादेशों/नियमों एवं निर्देशों की प्रतियां उपलब्ध कराएं.

5. उपरोक्त सर्वे के उपरांत क्या कोई पुन:निरीक्षण (रिव्यू) किया गया? यदि हां, तो समस्त दस्तावेज़ों की प्रतियां उपलब्ध कराएं.

6. पुन:निरीक्षण (रिव्यू) के संबंध में समस्त शासनादेशों/नियमों एवं निर्देशों की प्रतियां उपलब्ध कराएं.

7. सर्वे के दौरान क्या किसी अनियमितता का मामला सामने आया है? यदि हां, तो शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई? विवरण दें.

मैं आवेदन शुल्क के रूप में 10 रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.
या
मैं बीपीएल कार्डधारक हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नं.....है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित न हो, तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम और पता अवश्य बताएं.

भवदीय

नाम.....
पता.....
फोन नं.....

संलग्नक:
(यदि कुछ हो)

राशिफल

आचार्य चंद्रशेखर

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
आर्थिक मामलों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि थोड़ा उतार-चढ़ाव महसूस होगा. कोई स्थायी संपत्ति खरीदने का योग है. स्वास्थ्य के कारण मन परेशान रहेगा और कार्यक्षेत्र में मन कम लगेगा. नौकरीपेशा एवं व्यापारी, दोनों कुछ चिंतित रहेंगे, लेकिन पारिवारिक वातावरण समर्थन में रहेगा.

वृष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
क़ानूनी मामलों से बचकर चलें. स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा समय रहेगा. नौकरीपेशा एवं व्यापारी, दोनों के लिए शुभ समय है. निवेश के अच्छे नतीजे मिलेंगे. विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है. शत्रुओं पर नज़र रखें. समाज में आपकी तारीफ़ होगी. जीवनसाथी से संबंध अच्छे रहेंगे.

मिथुन (21 मार्च से 20 अप्रैल)
मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा. हो सकता है, उम्मीद के मुताबिक आपको सफलता मिलने में थोड़ी देरी हो, लेकिन हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है. आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ी उथल-पुथल रहेगी. व्यापारी अपने साझीदार पर नज़र रखें. भाई- बहनों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं.

कर्क (21 मार्च से 20 अप्रैल)
कोई स्थायी संपत्ति खरीदने का योग है. वाहन चलाते समय ध्यान रखें. आर्थिक दृष्टिकोण से समय काफी अच्छा रहेगा, लेकिन जोखिम वाले बाज़ार से बचकर रहें. नौकरीपेशा एवं व्यापारी, दोनों अच्छा प्रदर्शन करेंगे. पारिवारिक वातावरण कुछ उतार-चढ़ाव वाला रहेगा. माता-पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

सिंह (21 मार्च से 20 अप्रैल)
सामाजिक क्षेत्र में प्रसिद्धि बढ़ेगी. परिश्रम करेंगे. व्यवसाय में बदलाव और अच्छे प्रदर्शन के योग हैं. पुरानी संपत्ति के क्रय-विक्रय से आगे की योजना बनेगी. विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव महसूस करेंगे. पैसों के लेनदेन से बचें.

कन्या (21 मार्च से 20 अप्रैल)
आर्थिक दृष्टिकोण से मिला-जुला फल देने वाला समय है. कई समस्याओं से निजात मिलेगी और आप उत्साहित रहेंगे. पारिवारिक सुख बढ़ेगा. मित्रों एवं परिवारीजनों का सहयोग मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों की तरक्की के योग हैं. तेज मसाले वाले भोजन से बचें, अन्यथा स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ेगा.

तुला (21 मार्च से 20 अप्रैल)
पुराने अनसुलझे कार्यों में सफलता मिलेगी और नवीन कार्यों की योजना बनेगी. परिश्रम का लाभ मिलेगा. पारिवारिक सुख उत्तम रहेगा. खर्च बढ़ेगा, लेकिन चिंता न करें, क्योंकि आमदनी में भी बढ़ोत्तरी होगी. विद्यार्थी अध्ययन पर अच्छी तरह ध्यान देंगे.

वृश्चिक (21 मार्च से 20 अप्रैल)
किसी मांगलिक कार्य में शरीक हो सकते हैं. रुके हुए कार्यों में उम्मीद से ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा. वाहन सावधानी से चलाएं. दौड़धूप और खर्च में बढ़ोत्तरी होगी. विरोधी नुक़सान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन असफल रहेंगे.

धनु (21 मार्च से 20 अप्रैल)
संतान के दायित्वों की पूर्ति और सुख-संसाधनों में बढ़ोत्तरी होगी. दिनचर्या में अनुशासन रखें, अन्यथा उसका कुप्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ेगा. उधार दिया गया पैसा वापस आने में दिक्कत आएगी. प्रशासनिक अधिकारी से सहयोग मिलेगा. अत्यधिक विश्वास में आकर कोई कार्य न करें.

मकर (21 मार्च से 20 अप्रैल)
नौकरीपेशा लोग कुछ तनाव में रहेंगे. सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. व्यापारी किसी नए निवेश की योजना बनाकर व्यापार का विस्तार करेंगे. स्वास्थ्य ठीक रहेगा. विद्यार्थी अध्ययन पर ध्यान देंगे. किसी आकस्मिक यात्रा की योजना बनेगी.

कुंभ (21 मार्च से 20 अप्रैल)
कई अनसुलझे कार्य बनने और लाभ के प्रबल योग हैं. नौकरीपेशा लोगों को मिला-जुला असर देखने को मिलेगा. नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा. विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन करेंगे. दांपत्य जीवन सुखी रहेगा. व्यापारी जोखिम वाले बाज़ार से बचकर रहें.

मीन (21 मार्च से 20 अप्रैल)
पारिवारिक तनाव न बढ़ने दें. अनिश्चितता का वातावरण रहेगा, लेकिन विचलित न हों. आमदनी बढ़ेगी. क़ानूनी मामलों में थोड़ा बचकर चलें. नौकरीपेशा लोग कार्यस्थल पर सतर्क रहें. व्यापारी अपने व्यापार का विस्तार करेंगे.

ज़रा हट के

मौत के 153 साल बाद विदाई

दुनिया की सबसे बदसूरत महिला केतौर पर मशहूर जूलिया पेस्टईराना केशव को आखिरकार 153 साल के बाद कब्र नसीब हो ही गया. पेस्ट राना का परंपरागत ढंग से अंतिम संस्कार कर दिया गया है. आपको बताते चलें कि 19वीं शताब्दी में जूलिया पेस्टाराना दुनिया की सबसे बदसूरत महिला के रूप में जानी जाती थीं, क्योंकि आनुवांशिक रूप से ही उनका चेहरा बालों से ढका हुआ था. इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में उन्हें भालू महिला के नाम से भी जाना जाता था. 1950 के दशक में जूलिया पेस्टाराना अमेरिकी सर्कस केमालिक थियोडोरे लेंट से मिलीं. उसकेबाद पेस्टाराना सर्कस में शो करने लगीं. कुछ समय केबाद जूलिया पेस्टीराना और थियोडोरे लेंट में प्यार हो गया और फिर एक दिन दोनों ने शादी कर ली. 1860 में पेस्टाराना ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिस दौरान उनकी मौत हो गई. हालांकि जूलिया ने जिस बच्चे को जन्म दिया था, उसकी शक्ल बिल्कुल उसी की तरह थी और कुछ समय बाद उसकी भी मौत हो गई. असली मामला दरअसल, इसके बाद शुरू हुआ. जूलिया के पति ने उसकेशव को दफनाने की बजाय उस पर रासायनिक लेप लगाकर अपने पास रख लिया और दुनिया भर में शो करने लगा. शो का सफर 1976 में नॉर्वे जाकर उस वक्त थमा, जब जूलिया केशव के चोरी होने की घटना सामने आई. हालांकि पुलिस ने शव को बाद में बरामद कर लिया. शव बरामदगी केबाद उसे ओस्लो विश्वविद्यालय में सुरक्षित रखा गया. अब जाकर उनका विधिवत रूप से अंतिम संस्कार हुआ. उन्हें सफेद ताबूत में और सफेद गुलाब केफुलों के बीच दफनाया गया. सिनालोओ द लेव्या शहर केलोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी. ■

उत्तराखंड त्रासदी

जज़्बा तारीफ़ के क़ाबिल

चौथी दुनिया ब्यूरो

उत्तराखंड में बादल फट जाने से जो क़हर बरपा है, उसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया है. जान और माल का भारी नुक़सान हुआ और अभी तक दिल दहला देने वाली ख़बरें बराबर मिल ही रही हैं. अभी भी लोग सैलाब में फंसे हैं. इस प्राकृतिक आपदा ने राज्य को जो नुक़सान पहुंचाया है, उसका असर 40 हज़ार वर्ग किलोमीटर पर पड़ा है. इस तबाही का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि लगभग 600 से अधिक गांव राज्य के अन्य हिस्सों से कटे हुए हैं और कुछ लोग लापता भी हैं. इस कठिन समय में नौसेना और वायुसेना को सलाम किया जाना चाहिए. सच तो यह है कि इन जवानों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए मलबे और पानी में फंसे बेसहारा लोगों को बचाया. इसी दौरान ख़बर यह भी आई कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ़) ने 5 गांवों को गोद लेने की घोषणा की है और साथ ही राहत कोष में 16 करोड़ रुपये देने का मन भी बनाया है. बचाव कार्य में मुस्लिम भी लगे रहे. चौथी दुनिया के पिछले अंक 1-7 जुलाई, 2013 में यह ख़बर दी गई थी कि जमाअते इस्लामी हिन्द ने असाम में पुनर्वास के लिए सराहनीय कार्य किये हैं. इसमें हिन्दू, ईसाई, गैर बोडो और साथ में मुसलमानों को भी बिना भेदभाव के मदद की गई. साथ ही दूसरे मुस्लिम संगठनों ने भी पुनर्वास कार्य में कोई भेदभाव नहीं किया. उल्लेखनीय है कि इस बार उत्तराखंड में आपदा के फौरन बाद जमाअते इस्लामी हिन्द, जमीअत उलेमा हिन्द, ऑल इंडिया मिल्ली कॉन्सिल, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिन्द, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिसे मुशावरत, ए एम यू टीचर्स एसोसिएशन, अलीगढ़ के जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डाक्टरों व संगठनों ने वहां पहुंचकर राहत व बचाव कार्य किया. हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर भी रिलीफ़ कैंप लगाया गया. रिलीफ़ कैंप में अन्य डॉक्टरों की टीमें भी थीं. जमाअत इस्लामी के पश्चिमी यूपी के अध्यक्ष मौलाना इनामुल्ला इस्लाही के अनुसार, यह आपदा आकस्मिक है और इसमें मानवीय जीवन और धार्मिक स्थलों की बड़ी हानि हुई है. मुस्लिम मजलिसे मुशावरत ने प्रधानमंत्री के नेशनल रिलीफ़ फंड में 50 हज़ार रुपये का चेक भी भेजा है. ऑल इंडिया मिल्ली कॉन्सिल के महासचिव डाक्टर मंज़ूर आलम ने सभी राज्यों में अपनी शाखाओं से इस सन्दर्भ में फंड जमा करने की अपील की है, ताकि प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ़ फंड में इसे भेजा जा सके. प्राकृतिक आपदा के समय किसी संगठन, संस्था या व्यक्ति का बिना किसी भेदभाव के मानव सेवा के लिए आगे बढ़ना सांप्रदायिक सौहार्द्र और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है. ■

feedback@chauthiduniya.com

सऊदी अरब

> बादशाहत का यह सिलसिला अब्दुल अज़ीज़ के बेटों में ही चलता रहा है, जिसके चलते शहज़ादों में यह बात होने लगी कि अब उनमें बादशाहत का बंटवारा होना चाहिए. लिहाज़ा शाह फहद के दौर में 1992 में एक क़ानून बनाया गया,

क़तर

शाही खानदान में शीतयुद्ध!

शाही खानदान की अंतर्कलह इन दिनों सऊदी अरब सरकार के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है. वैसे भी, देश में नए क़ानून निताक़ा के चलते खासी उथल-पुथल मची हुई है, तिस पर शहजादों की महत्वाकांक्षाओं ने और भी गर्मी पैदा कर दी है.

वसीम अहमद

पिछले कुछ महीनों से सऊदी अरब के शाही ख़ानदान में पदों और सरकार पर अपनी मज़बूत पकड़ बनाने को लेकर शीतयुद्ध चल रहा है. सवाल यह है कि इस पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है? अगर शाही ख़ानदान के मतभेद इसी तरह चलते रहे, तो यह देश की शांति व्यवस्था के लिए अरब क्रांति से अधिक ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इसी के चलते पश्चिमी देशों को देश के अंदर हस्तक्षेप करने का मौक़ा मिलेगा और पवित्र स्थलों को नुक़सान पहुंचने के आसार बढ़ जाएंगे. दरअसल, सऊदी अरब का शासकीय ढांचा बादशाहत पर आधारित है और यह तबसे चला आ रहा है, जब शाह अब्दुल अज़ीज़ अल सउद ने जनवरी, 1926 में बादशाह होने का ऐलान किया था. इसके बाद उनके बड़े बेटे सउद बिन अब्दुल अज़ीज़ और फिर शाह फैसल, शाह ख़ालिद एवं शाह फहद ने बादशाहत की कमान संभाली और वर्तमान में अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अज़ीज़ बादशाह हैं.

बादशाहत का यह सिलसिला अब्दुल अज़ीज़ के बेटों में ही चलता रहा है, जिसके चलते शहज़ादों में यह बात होने लगी कि अब उनमें बादशाहत का बंटवारा होना चाहिए. लिहाज़ा शाह फहद के दौर में 1992 में एक क़ानून बनाया गया, जिसके अनुसार सऊदी अरब पर पहले बादशाह अब्दुल अज़ीज़ बिन सउद की संतान शासन करेगी और कुरआन देश का संविधान एवं शरीअत सरकार की बुनियाद होगी. शाही ख़ानदान के महत्वपूर्ण सदस्य उलेमा की सहमति से शाही ख़ानदान के किसी एक व्यक्ति को बादशाह चुनते हैं और उसी के अधिकार में देश की पूरी व्यवस्था होती है. यहां दीनी मामलों की देखरेख मुफ़्ती-ए-आज़म करते हैं, जो सलफ़ी मसलक के अगुवा होते हैं.

> **सऊदी अरब की शाही व्यवस्था में 2005 के बाद लोकतंत्र की थोड़ी गुंजाइश निकाली गई और निकाय चुनाव कराने की अनुमति दी गई. हालांकि देश में किसी राजनीतिक पार्टी के गठन की अनुमति नहीं है, लेकिन ऐसा महसूस होता हैं कि धीरे-धीरे सऊदी अरब लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा है.**

सउद बिन अब्दुल अज़ीज़

सऊदी अरब की शाही व्यवस्था में 2005 के बाद लोकतंत्र की थोड़ी गुंजाइश निकाली गई और निकाय चुनाव कराने की अनुमति दी गई. हालांकि देश में किसी राजनीतिक पार्टी के गठन की अनुमति नहीं है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि धीरे-धीरे सऊदी अरब लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा है. पहले देश में किसी भी महिला को वाहन चलाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब महिलाओं को सशर्त यह अनुमति दे दी गई है. इसी प्रकार पहले किसी भी महिला को यह अधिकार नहीं था कि वह देश के बाहर का सफर अकेले करे, लेकिन अब वह व्यापार या किसी और पर्याप्त वजह से अकेली सफर कर सकती है. वहीं शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अज़ीज़ यूनिवर्सिटी में लड़कियों को हाईटेक शिक्षा दी जाती है और उन्हें यूनिवर्सिटी कैंपस में नक़ाब के बिना रहने की अनुमति भी दे दी गई है. उक्त सभी क़दम इस बात की ओर इशारा करते हैं कि बादशाहत की बुनियाद पर क़ायम इस देश में अब धीरे-धीरे लोकतंत्र के अंकुर भी फूटने लगे हैं.

सऊदी अरब की शाही व्यवस्था में अब्दुल अज़ीज़ अल सउद के कुल 21 बेटों में अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अज़ीज़ छठवें शासक हैं और शाह अब्दुल अज़ीज़ के अन्य बेटे, जो इस समय जीवित हैं, वे सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर हैं. लेकिन अब्दुल अज़ीज़ के बेटों की जो नस्लें चली हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक है और उन्हें सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन करना एक समस्या बना हुआ है. वे शाही ख़ानदान के शहज़ादे होने के कारण महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होना चाहते हैं, जबकि सरकार के लिए सभी को बड़े पद देना संभव नहीं है. यही वजह है कि अब शाही परिवार में पदों को लेकर अंतर्विरोध बढ़ने लगा है. हालांकि शाह अब्दुल्लाह की ओर से न केवल पारिवारिक मतभेद दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है, बल्कि जनता में यह संदेश भी दिया जा रहा है कि अंदरखाने सब कुछ ठीक है, लेकिन पिछले दिनों ख़ालिद बिन सुल्तान को जिस प्रकार उनके पद से हटाया गया, उससे परिवार के अंदर शीतयुद्ध के संकेत मिलते हैं.

ख़ालिद बिन सुल्तान पूर्व शासक सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़ के बड़े बेटे हैं. जब तक सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़ जीवित रहे, शहज़ादा ख़ालिद कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे. अंत में उन्हें उप रक्षा मंत्री बनाया गया. रक्षा मंत्री बनने के बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए. यमन की सीमा पर अलक़ायदा समर्थित गिरोह अलहोसीन को 2010 में देश से निकालने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही. इस सफलता के बाद ख़ालिद चाहते थे कि उन्हें रक्षा मंत्री बना दिया जाए, जिससे वह पिता सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़ के पद का फ़ायदा उठाएं, लेकिन उनके पिता इसके पक्ष में नहीं थे, इसलिए मामला कुछ दिनों के लिए टल गया, लेकिन ख़ालिद निरंतर प्रयासरत रहे कि उन्हें रक्षा मंत्री बना दिया जाए. इसी बात को लेकर ख़ालिद और सलमान के बेटे शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान में अंतर्विरोध पैदा हुआ. धीरे-धीरे यह अंतर्विरोध इतना बढ़ा कि मोहम्मद बिन सलमान ने अपने पिता सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की सहमति से मंत्रालय के कोई भी दस्तावेज़ या रक्षा समझौते की प्रतिलिपि ख़ालिद बिन सुल्तान के नोटिस में लाने से सभी संबंधित अधिकारियों को रोक दिया, जबकि वह उप रक्षा मंत्री थे और ऐसा किया जाना उनका हक़ मारने के बराबर था, लेकिन आपसी मतभेद के कारण यह सब कुछ हुआ.

यह भी कहा जाता है कि शहज़ादा ख़ालिद बिन सलमान सऊदी अरब में स्वतंत्र बनना चाहते थे. हालांकि सऊदी क़ानून के अनुसार, जब किसी भी बाहरी देश से कोई बड़ा रक्षा समझौता होता है, तो उसमें न केवल रक्षा मंत्री, बल्कि शासक की सहमति भी आवश्यक होती है, लेकिन शहज़ादा ख़ालिद बिन सुल्तान ने इस क़ानून का उल्लंघन किया. शायद वह अपने अधिकारों को इतना बढ़ाना चाहते थे कि उन्हें किसी की अनुमति की आवश्यकता न पड़े और उन्होंने बिना शाही अनुमति के चीन के साथ समझौता कर लिया, जो कि रॉकेट सीएसएस-2 से संबंधित था. यह रॉकेट सऊदी अरब ने 1987 में चीन से ख़रीदा था और इसकी देखरेख चीन करता था.

ख़ालिद ने गुप्त रूप से चीन के साथ नवीनीकरण के समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसकी सूचना शाह अब्दुल्लाह को भी नहीं दी. यह काम इतने खुफिया तरीके से किया गया कि सरकार को इसकी भनक तक नहीं लगी, लेकिन अमेरिका ने इस समझौते से पर्दा उठाते हुए सऊदी सरकार से कड़ा विरोध जताया. दरअसल, अमेरिका के ख़ुलासे के बाद ही सऊदी सरकार को इस समझौते के बारे में पता चला.

यह जानकर शाही ख़ानदान के कान खड़े हो गए और इसके बाद उत्तराधिकारी सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने शहज़ादा ख़ालिद को पद से हटाने की सिफ़ारिश की. लिहाज़ा उन्हें हटाकर यह पद फहद बिन अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद को दे दिया गया. कहा जाता है कि ख़ालिद बिन सुल्तान के इस काम में परिवार के कुछ अन्य शहज़ादे भी शामिल थे, इसलिए उन्हें उनके घरों में नज़रबंद कर दिया गया है. हालांकि शाही परिवार इन ख़बरों को जनता से छिपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब दुनिया पहले जैसी नहीं रही. लोग जागरूक हो चुके हैं और वे शासक वर्ग की हर आहट को महसूस करते हैं. यह बात सत्ताधारी पार्टी भी समझ रही है, लिहाज़ा सऊदीयाइजेशन (सऊदीकरण) की बात जोर-शोर से हो रही है, ताकि नई एवं शिक्षित पीढ़ी एवं जनता का ध्यान शाही परिवार की अंतर्कलह से हटाया जा सके. इसी मक़सद से एक नया क़ानून निताक़ा बनाया गया है, जिससे भारत के 50 हज़ार मज़दूरों समेत दुनिया के लगभग साढ़े चार लाख मज़दूर प्रभावित होंगे. सच तो यह है कि सऊदीयाइजेशन के चलते विदेशी विशेषज्ञों एवं मज़दूरों की एक बड़ी संख्या देश से बाहर चली जाएगी, नतीजतन देश का कामकाज प्रभावित होगा और उसका अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना निश्चित है. ■

feedback@chauthiduniya.com

क़तर में सत्ता हस्तांतरण

संभावनाएं और जोखिम

चौथी दुनिया ब्यूरो

क़तर खाड़ी देशों में एक छोटा सा देश है. पिछले दिनों यहां हुए दो बड़े एवं महत्वपूर्ण बदलावों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा. पहला, सत्ता का हस्तांतरण और दूसरा, उदारवादी तालिबान का दोहा में अपना कार्यालय स्थापित करना. सत्ता हस्तांतरण का असर खाड़ी एवं पश्चिमी देशों की विदेश नीति पर पड़ सकता है. 1995 में शेख़ हमद बिन ख़लीफ़ा ने अपने पिता को सत्ता से बेदखल करके देश की बागडोर संभाली थी. उन्होंने अपने 18 साल के शासन में क़तर की अर्थव्यवस्था मज़बूत बनाई. यही नहीं, उन्होंने खाड़ी देशों के प्रमुखों के स्वभाव से हटकर क़तर की राजनीति तय की. हालांकि अरब क्रांति, जिसने पूरे अरब में अराजकता पैदा कर दी थी, लेकिन शेख़ हमद बिन खलीफ़ा ने इस जनांदोलन का समर्थन किया. उनके दौर में क़तर की राजनीति अरब स्वभाव से हटकर थी, जिससे यूरोपीय देशों में उसे न केवल एक आधुनिक अरब देश समझा गया, बल्कि यूरोपीय एवं अमेरिकी हितों की अधिकतर गतिविधियां क़तर से ही चलाई जाने लगीं. अरब क्रांति का मामला हो या अलजज़ीरा चैनल, जो जाने-अनजाने अमेरिकी हित वाली ख़बरों को वरीयता देता है, का क़तर के अंदर होना कहीं न कहीं अमेरिकी हितों को संरक्षण देता है. शेख़ हमद ने अपने शासनकाल में केवल राष्ट्रीय हितों को देखा, चाहे उसके लिए उन्हें अरबों की रिवायत और सियासी तर्ज़ से हटना ही क्यों न पड़े.

इधर कुछ महीनों से शेख़ हमद की गतिविधियों से अनुमान लगाया जा रहा था कि अब वह सत्ता छोड़ने वाले हैं, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने दोहा के एक सम्मेलन में कहा था कि किसी को भी क़तर में हो रहे परिवर्तन के विरुद्ध खड़ा होने की अनुमति नहीं दी जा सकती. इससे लगा कि देश में कुछ बड़े परिवर्तन होने वाले हैं. इसके अलावा, बीते कुछ महीनों से बादशाह शेख़ तमीम प्रशासनिक मामलों में अधिक रुचि लेने लगे थे और महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों के साथ राय-मशविरे के बिना कोई फ़ैसला ही नहीं करते थे. राजदूतों से उनकी मुलाकातों का सिलसिला भी बढ़ गया था. यह सब कुछ किसी बड़े परिवर्तन की ओर संकेत कर रहा था. ऐसा ही हुआ, शेख़ हमद ने अपने 33 वर्षीय बेटे तमीम बिन हमद बिन ख़लीफ़ा को सत्ता सौंप दी.

क़तर में पिता द्वारा बेटे को सत्ता सौंपना अनोखी बात है, क्योंकि वहां अब तक ऐसा नहीं हुआ. शेख़ हमद ने अपने पिता से सत्ता जबरन हथियाई थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को अपनी सहमति से सत्ता सौंपी. इससे लगता है कि सऊदी अरब की तरह यहां भी संतानों को सत्ता सौंपने की प्रथा शुरू की जा रही है. हो सकता है, शेख़ हमद इससे खाड़ी देशों को यह संदेश देना चाहते हैं कि प्रचलित प्रथा से हटकर अब सत्ता नई नस्ल को सुपुर्द कर देनी चाहिए. कहा जाता है कि नए शासक शेख़ तमीम अपने पिता से अधिक निकट रहे हैं और वह उनकी विचारधारा के समर्थक भी हैं. लिहाज़ा अगर सत्ता किसी और के हाथों में जाती, तो शेख़ हमद ने अपने 18 साल के शासनकाल में विश्व स्तर पर क़तर की जो छवि बनाई है, उसमें बदलाव हो सकता था. तमीम से उन्हें उम्मीद है कि वह उनकी विचारधारा पर आधारित अपनी राजनीति तय करेंगे और इसीलिए उन्होंने सहमति से अपना पद बेटे के हवाले कर दिया. अब शेख़ तमीम की यह जिम्मेदारी है कि वह अपनी सियासी सूझबूझ से देश को आगे ले जाएं और कोई ऐसा काम न करें, जिससे जनता में अनिश्चितता पैदा हो और अरब क्रांति, जिसका समर्थन उनके पिता ने किया था, उसे क़तर की जनता उनके ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल करे.

> **क़तर में पिता द्वारा बेटे को सत्ता सौंपना अनोखी बात है, क्योंकि वहां अब तक ऐसा नहीं हुआ. शेख़ हमद ने अपने पिता से सत्ता जबरन हथियाई थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को अपनी सहमति से सत्ता सौंपी. इससे लगता है कि सऊदी अरब की तरह यहां भी संतानों को सत्ता सौंपने की प्रथा शुरू की जा रही है. हो सकता है, शेख़ हमद इससे खाड़ी देशों को यह संदेश देना चाहते हैं कि प्रचलित प्रथा से हटकर अब सत्ता नई नस्ल को सुपुर्द कर देनी चाहिए. कहा जाता है कि नए शासक शेख़ तमीम अपने पिता से अधिक निकट रहे हैं और वह उनकी विचारधारा के समर्थक भी हैं.**

तमीम बिन हम्द

खालिद बिन सुलतान

मोहम्मद बिन सलमान

शेख़ तमीम के सामने कई समस्याएं हैं, जिनका सामना करना उनके लिए एक चुनौती है. ख़ासकर, विदेश नीति में अरब देशों के साथ रिश्ते मधुर बनाना और उनमें अपने लिए विश्वास बहाल करना, क्योंकि अरब देशों में सत्ता हस्तांतरण बादशाह की मृत्यु के बाद होता है, लेकिन शेख़ तमीम को सत्ता उनके पिता ने जीवित रहते सौंपी है. प्रचलित प्रथा के ख़िलाफ़ इस सत्ता हस्तांतरण को अरब देश किस नज़रिए से देखते हैं और शेख़ तमीम उनकी प्रतिक्रियाओं का सामना किस तरह करते हैं, यह आने वाला वक़्त ही बताएगा, लेकिन इस समय उनके सामने एक गंभीर समस्या यह है कि देश में तालिबानी कार्यालय का खुलना. इस संदर्भ में अरब एवं मित्र देशों को मनाना उनके लिए जोखिम भरा काम होगा. दरअसल, तालिबान ने दोहा में न केवल अपनी शाखा खोलकर उस पर इस्लामी अमीरात अफगानिस्तान की तख्ती चस्पां की है, बल्कि उस पर अपना झंडा भी लगाया है. इस घटना से अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करज़ई बहुत नाराज़ हैं और इसीलिए उन्होंने अमेरिका के साथ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा समझौते पर वार्ता रद्द कर दी है. करज़ई का कहना है कि तालिबान का विशेष चिन्ह और अमीरात की तख्ती लगाए जाने से यह नकारात्मक संदेश जाता है कि उन्हें दुनिया ने स्वीकार कर लिया है.

अमेरिका ने जब अफगानिस्तान पर हमला किया था, तो उस समय वहां तालिबान की सरकार थी. अमेरिका ने नाटो की मदद से तालिबान को सत्ता से बेदखल कर दिया और हामिद करज़ई को देश का राष्ट्रपति बना दिया. हालांकि भारत नाटो की सेना में शामिल नहीं था, लेकिन राजनीतिक रूप से वह तालिबानी व्यवस्था का विरोधी था. जब करज़ई की सरकार बनी, तो भारत ने अफगानिस्तान के विकास में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. अब जबकि एक बार फिर उदारवादी तालिबान के समर्थन और क़तर में उसकी शाखा खुलने की बात सामने आ रही है, तो ऐसे में भारत का चिंतित होना लाज़िमी है, क्योंकि तालिबानी ताक़त के उभरने से एक बार फिर आतंकवाद ज़ोर पकड़ सकता है. स्वयं करज़ई भी इससे चिंतित हैं कि तालिबान के साथ वार्ता का अर्थ है, सरकार में उसकी साझेदारी.

बीते 25 जून को अफगानिस्तान में हामिद करज़ई के निवास पर एक आत्मघाती हमला हुआ, जिसे क़तर में तालिबानी शाखा पर करज़ई की आपत्ति से जोड़कर देखा जा रहा है. हो सकता है, तालिबानियों ने करज़ई को चेतावनी देने के लिए हमला किया हो कि वह क़तर में उनकी गतिविधियों का विरोध करना छोड़ दें. यह भी हो सकता है कि यह काम किसी तालिबानी का न हो, बल्कि स्वयं करज़ई के लोगों ने अंजाम दिया हो, ताकि अमेरिका को यह संदेश दिया जा सके कि अगर क़तर में तालिबानियों को कार्यालय खोलने की अनुमति दी जाती है, तो अफगानिस्तान की शांति भंग हो सकती है. यह भी हो सकता है कि करज़ई जनता की सहानुभूति हासिल करना चाहते हों, ताकि 2014 में होने वाले चुनाव में वह एक बार फिर राष्ट्रपति चुन लिए जाएं या फिर यह कि अमेरिका, जो अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलाने की तैयारी कर रहा है, को एहसास दिलाया जा सके कि अफगानिस्तान में शांति बनाए रखने के लिए अमेरिकी सेना की मौजूदगी ज़रूरी है. जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि अगर तालिबानियों को अफगानिस्तान में दोबारा सक्रिय होने का मौक़ा मिल गया, तो वहां की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था और सरकार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा. साथ ही भारत-अफगानिस्तान के मज़बूत रिश्तों की वजह से वहां जो भी विकास कार्य जारी हैं, वे भी प्रभावित होंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

साई

आस्था

दरअसल

> खजुराहो का सूर्य मंदिर अप्रतीम है. खजुराहो एक छोटा गांव है, जो बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में स्थित है. चंदेलों ने इसे राजधानी बनाया था. यह गांव चंदेल राजाओं द्वारा नागर शैली में बनाया गया है. इस गांव में कुल 85 मंदिर हैं, जिनके लिए यह विश्वविख्यात है.

खंडूबा पहुंचे साई बाबा

चौथी दुनिया ब्यूरो

साई बाबा खंडूबा के एक मंदिर में पहुंचे. उन दिनों उस मंदिर के पुरोहित थे भगत महालसापति. आओ साई कहकर उन्होंने बाबा को देखते ही उनका स्वागत किया. शुरू-शुरू में बाबा कैसे भिक्षा मांगते थे और उनकी दिनचर्या क्या होती थी, इसी पर आधारित है बाबा की यह कथा...

शिरडी ही साई बाबा है और साई बाबा ही शिरडी. दरअसल, एक-दूसरे का प्रत्यक्ष पर्यायवाची होने के साथ-साथ यह आध्यात्मिक भी है. साई शब्द के उच्चारण से आशा और आदर का भाव उत्पन्न होता है. साई बाबा को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है. ऐसा माना जाता है कि साई बाबा 1858 में औरंगाबाद से एक शादी समारोह में शिरडी आए थे. उन्होंने सबसे पहला शिविर खंडूबा मंदिर में लगाया था. वर्तमान समय में यह मंदिर श्री साई बाबा संस्थान के सामने स्थित है. शुरू-शुरू में खंडूबा मंदिर के पुरोहित थे भगत महालसापति. उन्होंने आओ साई कहकर साई बाबा का स्वागत किया. साई एक संत के रूप में जाने जाते हैं. पश्चिम महाराष्ट्र स्थित शिरडी भारत का प्रमुख

शिरडी में सबसे प्रमुख समाधि मंदिर है, जिसका निर्माण भगवान विट्ठल ने किया था. इस मंदिर का वास्तविक नाम भुट्टीवाड़ा है. गोपाल भुट्टी बाबा के बहुत बड़े उपासक थे. बाबा ने भुट्टी से कहा था, मैं एक दिन वापस यहां रहने के लिए आऊंगा. साई बाबा ने 15 अक्टूबर, 1918 को देह त्याग किया. वर्तमान समय में शिरडी में साई बाबा की सफेद संगमरमर की समाधि और एक बड़ी सी मूर्ति है.

धार्मिक स्थान है. कोई भी श्री साई बाबा की पृष्ठभूमि के बारे में बहुत अधिक नहीं जानता है. साई बाबा ने महालसापति से कहा था कि उनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन उन्हें बड़ा किसी मुस्लिम फकीर ने किया था. साई लोगों के घर-घर जाकर उनसे अल्ला मालिक कहकर भिक्षा मांगा करते थे. बहुत सारे लोग उन्हें बाबा कहकर बुलाते थे. बाबा प्रत्येक व्यक्ति से न केवल रात-दिन, बल्कि सप्ताह के सातों दिन ईश्वर का स्मरण करने के लिए कहा करते थे, जिसे नामसप्तक के नाम से भी जाना जाता है. बाबा का कहना था कि दाकूरनाथ, विट्ठल और रणछोड़ (सभी कृष्ण के नाम), ये सब भी शिरडी में निवास करते हैं.

शिरडी में सबसे प्रमुख समाधि मंदिर है, जिसका निर्माण भगवान विट्ठल ने किया था. इस मंदिर का वास्तविक नाम भुट्टीवाड़ा है. गोपाल भुट्टी बाबा के बहुत बड़े उपासक थे. बाबा ने भुट्टी से कहा था, मैं एक दिन वापस यहां रहने के लिए आऊंगा. साई बाबा ने 15 अक्टूबर, 1918 को देह त्याग किया. वर्तमान समय में शिरडी में साई बाबा की सफेद संगमरमर की समाधि और एक बड़ी सी मूर्ति है. इस सर्वोत्तम मूर्ति की रचना मुंबई के मूर्तिकार भाहू साहब तलिम ने 1954 में की थी. भगवान विट्ठल की मूर्ति को शिरडी स्थित दीक्षित वाड़ा संग्रहालय में रखा गया है. श्री साई बाबा संस्थान एक विशाल प्रशासकीय इमारत और आध्यात्मिक मंदिर है. यहां स्थित शांति निवास में श्री साई वेंगमे कर्कशा नामक एक पुस्तकालय भी है. समाधि मंदिर में साई बाबा की समाधि है. प्रवेश स्थान से समाधि मंदिर की दूरी लगभग 800 मीटर है. यहां आए तीर्थयात्रियों के विश्राम के लिए अनेक बेंच लगाई गई हैं. मंदिर में भक्तों की भीड़ हमेशा रहती है. मंदिर में चार बार आरती होती है. सुबह 5.15 पर होने वाली कक्कड़ आरती सबसे प्रमुख है. शिरडी में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार गुरु पूर्णिमा, दशहरा और रामनवमी हैं. इन त्योहारों के समय 24 घंटे के लिए समाधि मंदिर खुला रहता है.

श्री साई बाबा अपने जीवन के अंतिम क्षणों में द्वारकामाई में ही ठहरे थे. द्वारकामाई एक पुरानी उबड़-खाबड़ मस्जिदनुमा कोठी थी. यहां बैठकर वह लोगों की समस्याओं, बीमारियों और चिंताओं को दूर करते थे. साई बाबा इसी द्वारकामाई में आकर रहने लगे. उनका मानना था कि सबका मालिक एक है. द्वारकामाई के प्रथम तल पर बाबा की फोटो और एक बड़ा पत्थर रखा है, जिस पर बाबा बैठा करते थे. यहां दो कमरे हैं. पहले कमरे में रथ और दूसरे में पालकी रखी है. पत्थर का एक चौकोर स्टूल भी है, जिसका इस्तेमाल बाबा नहाने के लिए करते थे. द्वारकामाई मस्जिद समाधि मंदिर के प्रवेश द्वार की दाईं ओर स्थित है. गुरुस्थान एक छोटा सा मंदिर है. इसमें शिवलिंग और साई बाबा की तस्वीर है. इस मंदिर में गुरुवार और शुक्रवार को बड़ी संख्या में भक्तजन आते हैं. यह वह स्थान है, जहां साई बाबा ने पहली बार शिरडी में बाल योगी के रूप में प्रवेश किया था. इसीलिए इसे गुरुस्थान के रूप में जाना जाता है. यहां एक छोटी सी मस्जिद भी है. मंदिर के प्रवेश द्वार पर शिवलिंग और नंदी का चित्र बना हुआ है. इसके अलावा, मंदिर में बारह ज्योतिर्लिंगों के चित्र भी लगे हैं. द्वारकामाई से थोड़ी ही दूरी पर साई बाबा की चावड़ी है. इस स्थान का प्रयोग बाबा सोने के लिए करते थे. चावड़ी दो भागों में विभाजित है. चावड़ी के पहले हिस्से में बाबा की एक बहुत बड़ी फोटो लगी है, वहीं दूसरे हिस्से में लकड़ी का पलंग और सफेद कुर्सी भी रखी हुई है.

अब्दुल बाबा की झोपड़ी से कुछ ही दूर मारुति मंदिर है. इस मंदिर में साई बाबा देवीदास (बाल योगी) के साथ सत्संग के लिए आते थे. देवीदास इस मंदिर में साई बाबा के आगमन से दस-बारह साल पहले से रह रहे थे. इसके अलावा, यहां शिरडी शनि, गणपति और शंकर के नाम से मंदिर भी हैं. गुरुस्थान से थोड़ी सी दूरी पर लेंडी बाग है. इसे स्वयं बाबा ने बनाया था. वह हर रोज यहां स्वयं पानी दिया करते थे. बाबा ने इस बाग को नुल्लाहा नाम दिया. इस बाग में बाबा सुबह-शाम नीम के पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए आते थे. इस बाग में आठ जगहों पर संगमरमर के पत्थरों से बने दीपगृह (नंदा दीप) हैं. यहां एक तरफ पीपल का पेड़ है, दूसरी ओर नीम का. खंडूबा मंदिर मुख्य मार्ग पर स्थित है. इसी मंदिर में पुजारी महालसापति ने साई बाबा का स्वागत आओ साई कहकर किया था. इस मंदिर में खंडूबा और महलसाई की मूर्तियां हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल feedback@ chauthiduniya.com

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

आस्था

खजुराहो
अद्भुत मूर्ति शिल्प का बेजोड़ नमूना

खजुराहो के मंदिरों की बात ही निराली है. यहां की मूर्तियां नृत्य और संगीत की छटा से भक्तों का मन मोह लेती हैं. दीवारों पर प्रणय में लीन जोड़े बरबस ही हमें अपनी ओर खींच लेते हैं. अद्भुत है यहां का सौंदर्य.

चौथी दुनिया ब्यूरो

साधारणतया खजुराहो के बारे में लोगों के बीच यही धारणा बनी हुई है कि खजुराहो नये जोड़ों के घूमने के लिए ठीक है, लेकिन यह धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि खजुराहो के मंदिरों और यहां की भव्य मूर्तियां देश के अन्य भागों में स्थापित मंदिरों की तुलना में कहीं से भी कम नहीं हैं. हमारे देश में सूर्य मंदिर बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन यह हसरत आपको यहां आने पर पूरी हो जाएगी. खजुराहो का सूर्य मंदिर अप्रतीम है. खजुराहो एक छोटा गांव है, जो बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में स्थित है. चंदेलों ने इसे राजधानी बनाया था. यह गांव चंदेल राजाओं द्वारा नागर शैली में बनाया गया है. इस गांव में कुल 85 मंदिर हैं, जिनके लिए यह विश्वविख्यात है. हालांकि अब सिर्फ 22 मंदिर ही बचे हैं, जो कि ठीक हालात में हैं. खजुराहो के मंदिरों में चंदेल काल के सामाजिक जीवन को मूर्तियों के माध्यम से नायाब तरीके से उकेरा गया है. मंदिरों में नृत्य और संगीत की छटाएं मन मोह लेती हैं. कहीं नृत्य की मुद्रा में संगीत वादन करती नारी की मूर्तियां दिखाई देती हैं, तो कहीं मुग्ध स्त्रियां आइने में खुद को निहारती दिखती हैं. मुख्य दीवारों पर प्रणय में लीन जोड़ों की मूर्तियां बरबस ही लोगों को अपनी ओर खींच लेती हैं.

▲खजुराहो का अद्वितीय सूर्य मंदिर

बेमिसाल मूर्तियां

मंदिरों की बेमिसाल मूर्तिशिल्प में जीवन का हर रंग बड़ी खूबसूरती के साथ चित्रित है. मंदिरों और मूर्तियों में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थरों का प्रयोग खूब हुआ है. इन मंदिरों का विषय है सामाजिक जीवन, नृत्य संगीत और प्रणय. मूर्तियों पर इन विषयों का अलंकरण बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है. ये मंदिर आठ किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं. यहां के प्रमुख मंदिरों में चौंसठ योगिनी, कंदरिया महादेव, जगदंबा, विश्वनाथ, हुलादेव, पार्श्वनाथ, जावरी और हनुमान मंदिर प्रमुख हैं. प्रवेश द्वार यहां के मंदिरों के वास्तुशिल्प का एक अनूठा उदाहरण है.

पार्वती मंदिर

पार्वती मंदिर का आकार छोटा जरूर है, लेकिन यह मंदिर बहुत ही सुंदर है. मंदिर पूर्व की ओर स्थित है. इसमें पार्वती की आकृति को गोह पर चढ़ा हुआ दिखाया गया है. पार्वती मंदिर की दायीं तरफ विश्वनाथ मंदिर खजुराहो का विशालतम मंदिर है. यह मंदिर शंकर भगवान से संबंधित है. एक लिंगम, चिट्ठियां लिखती अप्सराएं और संगीत का कार्यक्रम इस मंदिर में बहुत ही उत्कृष्ट रूप में दिखाए गए हैं.

दर्शनीय मंदिर

-पश्चिमी समूह के मंदिर

लक्ष्मी मंदिर, वराह मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, सिन्ह मंदिर, देवी जगदम्बा मंदिर, सूर्य (चित्रगुप्त) मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, नन्दी मंदिर, पार्वती मंदिर

-पूर्वी समूह के मंदिर

वामन मंदिर, जावरी मंदिर, जैन मंदिर

-दक्षिणी समूह के मंदिर

चतुर्भुज मंदिर, दुलादेव मंदिर

जगदंबा मंदिर

यह मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर के चबूतरे के ठीक उत्तर में है. यहां देवी पार्वती की प्रतिमा स्थापित है. इसलिए इस मंदिर को देवी जगदंबा मंदिर कहते हैं. यहां पर उत्कीर्ण मैथुन मूर्तियों में भावों की गहरी संवेदनशीलता देखने को मिलती है, जो शिल्प की महत्वपूर्ण विशेषता है. यह मंदिर शार्दूलों के काल्पनिक चित्रण के लिए प्रसिद्ध है. शार्दूल पौराणकि पशु था, जिसका शरीर शेर का और सिर तोते, हाथी या वराह का होता था.

कंदरिया महादेव मंदिर

इस मंदिर की पहचान सबसे अलग है. अपनी भव्यता के कारण यह मंदिर सबसे अलग है. यह शैव मंदिर है. इस मंदिर की प्रमुख विशेषता इसका मकर तोरण है. यहां सर्वाधिक मिथुनों की आकृतियां हैं.

सूर्य मंदिर

सूर्य मंदिर चबूतरे पर स्थित है. इसे चंद्रगुप्त मंदिर भी कहते हैं. इस तरह से यह चबूतरे पर स्थित चौथा मंदिर है. इस मंदिर में भगवान सूर्य की सात फुट ऊंची प्रतिमा है, जो कवच धारण किए हुए है. इसमें भगवान सूर्य सात घोड़ों के रथ पर सवार हैं. भगवान सूर्य के मुख की भव्य आभा इस मंदिर की प्रमुख विशेषता है. एक मूर्तिकार को काम करते हुए कुर्सी पर बैठा दिखाया गया है, जो इस मंदिर की खूबसूरती में चार चांद लगाता है. इसके अलावा, एक ग्यारह सिर वाली विष्णु की मूर्ति दक्षिण की दीवार पर स्थापित है.

चतुर्भुज मंदिर

बलुवे पत्थर से निर्मित खजुराहो का यह एकमात्र ऐसा मंदिर है, जिसमें मिथुन प्रतिमाओं का चित्रण नहीं के बराबर है. चतुर्भुज मंदिर के द्वार शार्दूल सर्पिल प्रकार के हैं. इनमें कुछ सुर-सुंदरियां निर्माण के क्रम में अधूरी ही छोड़ दी गई हैं.

खरीदारी

ज्यादातर धार्मिक स्थानों पर खरीदारी के लिए कोई खास चीजें नहीं मिलतीं, लेकिन आप खजुराहो आएं और खाली हाथ लौट जाएं, यह तो संभव ही नहीं है. यहां की दुकानों पर, विशेष रूप से पत्थरों और धातुओं पर उकेरी गई कामसूत्र की भंगिमाएं बिकती हैं.

कैसे पहुंचें

खजुराहो में एयरपोर्ट है, जो सिटी सेंटर से तीन किलोमीटर दूर है. खजुराहो का नजदीकी रेलवे स्टेशन है महोबा और हरपालपुर. दिल्ली और मुंबई से आने वाले पर्यटकों के लिए झांसी सुविधाजनक रेलवे स्टेशन है. खजुराहो महोबा, हरपालपुर, छतरपुर, सतना, पन्ना, झांसी, आगरा, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, वाराणसी और इलाहाबाद से सीधा जुड़ा हुआ है. यहां ऑटो और राज्य सरकार के पर्यटन बस से भी पहुंचा जा सकता है. इसके अतिरिक्त आप अपने निजी वाहनों से भी इन मंदिरों तक पहुंच सकते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

दरअसल

रामकृष्ण का जन्म

दिलीप कुमार

उनका नाम था खुदीराम चटर्जी, जहां इनका जन्म हुआ था, उस जगह का नाम था कामारपुकुर. कामारपुकुर बंगाल का एक जाना-पहचाना पॉश एरिया है. यह स्थान इन दिनों कोलकाता के साउथ इलाके में आता है. टाटा, बिड़ला आदि के बड़े-बड़े शो-रूम हैं यहां. इस इलाके का नाम कामारपुकुर इसलिए पड़ा, क्योंकि यहां एक बहुत बड़ा तालाब है. दरअसल, तालाब को बांग्ला में पुकुर कहते हैं और कामार का बांग्ला भाषा में मतलब होता है लोहार, यानी लोहारों का तालाब. वहां के लोगों का कहना है कि खुदीराम को किसी बात पर नाराज होकर गांव के लोगों ने कामारपुकुर से निकाल दिया था. उन्नीसवीं शताब्दी की शुरुआत थी. उन दिनों यात्रा करना इतना आसान नहीं था, खासकर तीर्थ यात्रा करना. पैसे वाले यात्रा करने के लिए तो अपना इंतजाम कर लेते थे, लेकिन गरीब नहीं कर पाते थे. खैर, हम बात कर रहे थे खुदीराम की. गांव से निकलने के बाद वह मायूस होकर गया की ओर चल दिए. गया तक पैदल यात्रा की. पांव में छाले पड़ गए, खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वे चलते रहे. उन्हें लगा कि पित्तरों के कोप के कारण उन्हें गांव से निकाला गया, इसलिए उन्होंने वहां जाकर यह सोचा कि यदि वे पित्तरों का तर्पण करेंगे, तो कोप मुक्त हो जाएंगे. गया में भगवान विष्णुपद का मंदिर है. खुदीराम ने किसी से सुना था कि गया में भगवान विष्णुपद के मंदिर में माथा टेकने से मनोकामना पूरी हो जाती है. इसलिए उन्होंने न केवल माथा टेका, बल्कि पूरी श्रद्धा के साथ हाथ भी जोड़े. हाथ जोड़ने के बाद उन्होंने मन ही मन भगवान से माफी मांगी और अपने पित्तरों को कोप मुक्त करने के लिए करबद्ध प्रार्थना की, तो उन्हें अचानक यह महसूस हुआ कि भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हो कर कह रहे हैं कि आज हमने तुम्हारे पित्तरों को मुक्त कर दिया है. तुमने यहां तक पैदल आकर मुझे प्रसन्न कर दिया. कहते हैं कि भगवान विष्णु ने उन्हें आग्रह किया कि क्या तुम अपने घर मुझे ले चलोगे.

खुदीराम बहुत गरीब थे, इसलिए उनको उस समय कुछ भी नहीं सूझा, क्योंकि उनके पास अपना कोई घर नहीं था. हां, एक छोटी सी कुटिया जरूर थी. इसलिए न चाहते हुए भी बोले कि ठीक है, आप मेरी कुटिया में आकर मेरे साथ खिचड़ी खा सकते हैं. जब भगवान उनकी कुटिया में आए, तब चमत्कार हो गया. कामारपुकुर के लोग आज भी यह कहते हैं कि उसी क्षण खुदीराम की पत्नी को यह महसूस हुआ कि कोई दिव्यशक्ति उनके शरीर में प्रविष्ट कर रहा है. पत्नी हैरान हो गई. इस घटना का जिक्र खुदीराम की पत्नी ने अपनी एक खास सहेली से किया था. वह उनकी पड़ोसन थीं. धनी लुहारिन नाम था उनका. घटना के नौ महीने बाद एक बच्चे का जन्म हुआ. उनका नाम रखा गया गोदई. बाद में यही बच्चा रामकृष्ण परमहंस के नाम से विश्वविख्यात हुआ. बता दें कि रामकृष्ण के परम शिष्य थे विवेकानंद.■

शिक्षा : श्रद्धा हो, तो ईश्वर भी दर्शन देते हैं

feedback@chauthiduniya.com

प्रसंगवश

हेमंत शर्मा अपनी कैलास यात्रा की कहानी के साथ–साथ उसके पौराणिक महत्व या किंवदंतियों के बारे में भी टिप्पणी करते चलते हैं. वह शिव और उनके व्यक्तित्व को भी व्याख्यायित करते हैं. जैसे कि हेमंत शर्मा लिखते हैं, आज पर्यावरण बचाने की चिंता विश्वव्यापी है.

समीक्षा

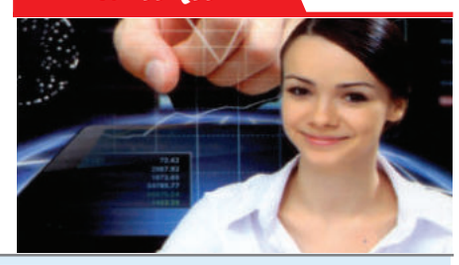

एको अहम की तलाश में द्वितीयोनास्ति

एक समय था, जबकि अख़बारों-पत्रिकाओं में न केवल अक्सर यात्रा वृत्तांत प्रकाशित होते थे, बल्कि पाठक उन्हें बड़े चाव के साथ पढ़ते भी थे, लेकिन बीते कुछ समय से यात्रा वृत्तांत लेखन की परंपरा थम-सी गई थी. हालांकि एक बार फिर यात्रा वृत्तांत लेखन की शुरुआत हुई है और यह शुरुआत की है, जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा ने अपनी पुस्तक-द्वितीयोनास्ति, कैलास-पर्वत एक अकेला के माध्यम से.

अनंत विजय

हिंदी में यात्रा वृत्तांत लिखने की एक समृद्धशाली परंपरा रही है. भारतेंदु युग में भी अनेक लेखकों ने यात्रा वृत्तांत लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया. खुद भारतेंदु ने कविवचन सुधा में 1871 से 1879 तक कई वृत्तांत लिखे, जिनमें हरिद्वार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा और सरयू पार की यात्रा विशेष रूप से पठनीय हैं. उस काल की पत्र–पत्रिकाओं में भी यात्रा वृत्तांत प्रमुखता से छपते थे और लोग उन्हें चाव के साथ पढ़ते थे. भारतेंदु युग में खास तौर पर विदेश यात्रा के कई लेख मिलते हैं, लेकिन उस दौर में भी दुर्गम पहाड़ों की यात्रा से लौटे लोगों ने भी जमकर यात्रा की दुश्वारियों से लेकर रोमांच और उसके पौराणिक महत्व को समेटते हुए कई लेख लिखे.1890 में विगू मिश्र ने बदरी–केदार यात्रा का अद्भुत वर्णन किया है. बाद में द्विवेदी युग में भी देवी प्रसाद खत्री, गोपाल राम गहमरी आदि ने भी यात्रा वृत्तांत लिखे, जो आज हिंदी साहित्य की थाती हैं. कालांतर में भी यात्रा वृत्तांत लिखने का क्रम जारी रहा. छायावादोत्तर काल तक आते–आते यात्रा वृत्तांत शैली, शिल्प एवं विषय की विविधता की वजह से अहम हो गए और लोकप्रिय भी. इसी दौर में राहुल सांकृत्यायन जैसे यायावर पैदा हुए, जिन्होंने प्रचुर मात्रा में इस विधा में लेखन करके हिंदी जगत को समृद्ध किया. इस दौर में ही भारत को स्वतंत्रता मिली थी, लिहाजा कई राजनेताओं ने भी विदेश यात्रा से लौटकर अपने संस्मरण लिखे. लेकिन जैसे–जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, हिंदी साहित्य की यह समृद्ध विधा हाशिए पर चली गई. दरअसल, वैश्वीकरण और इंटरनेट ने दुर्गम स्थानों को भी इतना सुलभ करा दिया कि लोगों की ज़्यादा रुचि यात्रा वृत्तांत में रही ही नहीं. नतीजा यह हुआ कि पत्र–पत्रिकाओं से इस तरह का लेखन गायब होता चला गया. बीच–बीच में अवश्य कोई किताब या फिर लेख यात्रा संस्मरणों पर दिख जाता है. फिलहाल कृष्ण नाथ जी इस विधा में सबसे अहम काम कर रहे हैं. कुछ दिनों पहले हिंदी की मशहूर कवयित्री गगन गिल की भी पुरोवाक् नाम से कैलाश मान सरोवर यात्रा पर एक किताब आई थी, जिसकी खासी चर्चा हुई. मैं इस पूरी परंपरा को इस वजह से लिख रहा हूं कि हाल में मुझे वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा की एक अद्भुत किताब–द्वितीयोनास्ति, कैलास–पर्वत एक अकेला मिली है, जो हेमंत शर्मा की कैलास मान सरोवर यात्रा की दास्तां है.

हेमंत शर्मा से मेरा परिचय उनके लेखन के माध्यम से ही रहा है. बाद में वह टीवी पत्रकारिता से जुड़ गए और इंडिया टीवी में नींव से लेकर निर्माण तक हैं. हेमंत की छवि एक संवेदनशील पत्रकार के तौर पर रही है, जो उनकी इस किताब से और पुष्ट होती है. कॉफी टेबल बुक स्टाइल में कैलास यात्रा की यह किताब हेमंत जी के पत्रकार व्यक्तित्व के अंदर के सहृदय लेखक को उभार कर पाठकों के सामने पेश कर देता है. लगभग सवा सौ पृष्ठों की यह किताब जब मुझे मिली, तो मैं चकित रह गया. हिंदी में इस तरह की किताबें दरअसल, कम ही छपती हैं. एक तो बेहतरीन आर्ट पेपर पर और शानदार फोटो के साथ. सारे फोटो भी लेखक हेमंत शर्मा द्वारा लिए हुए. हेमंत शर्मा फिलहाल टेलीविजन पत्रकारिता कर रहे हैं, इस वजह से उन्हें विजुअल की महत्ता का पता है. इसीलिए इस किताब

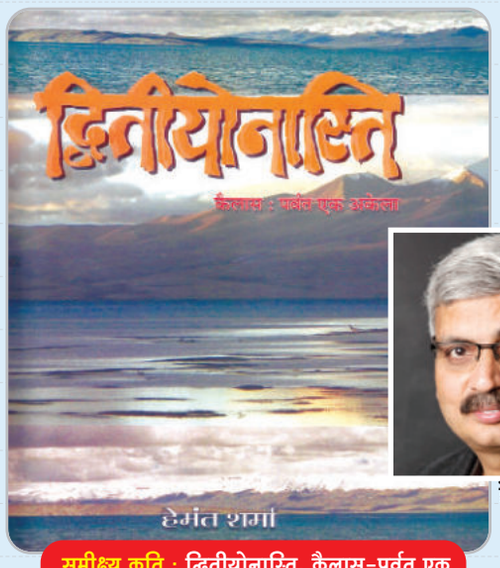

हेमंत शर्मा

समीक्ष्य कृति : द्वितीयोनास्ति, कैलास-पर्वत एक अकेला
लेखक : हेमंत शर्मा
प्रकाशक : प्रभात प्रकाशन
मूल्य : 750 रुपये

के हर पृष्ठ पर एक से एक बेहतरीन फोटो हैं और वहीं उस पर ही छोटी–छोटी टिप्पणियां. सिर्फ़ कुछ जगहों पर लंबी टिप्पणियां हैं, क्योंकि फोटो ही इतना कुछ कह जाता है कि ज़्यादा लिखने की गुंजाइश ही नहीं बचती. हेमंत शर्मा की लेखन शैली भी बेहतरीन है. अपनी यात्रा की शुरुआत से लेकर कैलास जाने और वहां से लौटने के क्रम में हेलिकॉप्टर खराब होने का जो उन्होंने वर्णन किया है, वह पाठकों को हटने ही नहीं देता है. मैंने जब इस किताब को पढ़ना शुरू किया, तो फिर ख़त्म करके ही उठा.

दरअसल, हेमंत शर्मा अपनी कैलास यात्रा की कहानी के साथ–साथ उसके पौराणिक महत्व या किंवदंतियों के बारे में भी टिप्पणी करते चलते हैं. वह शिव और उनके व्यक्तित्व को भी व्याख्यायित करते हैं. जैसे कि हेमंत शर्मा लिखते हैं, आज पर्यावरण बचाने की चिंता विश्वव्यापी है. शिव पहले पर्यावरण प्रेमी हैं, पशुपति हैं और निरीह पशुओं के रक्षक भी हैं. आर्य जब जंगल काटकर बस्तियां बसा रहे थे, खेती के लिए ज़मीन तैयार कर रहे थे, दूध के लिए गाय को दुह रहे थे, पर बछड़े का मांस खा रहे थे, तब शिव ने बूढ़े बैल नंदी को अपना वाहन बनाया, सांड को अभयदान दिया और जंगल कटने से बेदखल हुए सांपों को आश्रय दिया. हेमंत शर्मा का मानना है कि महादेव ने उपेक्षितों को भी गले लगाया. अपनी इस किताब में भाषा के प्रवाह और संप्रेषणीयता को बनाए रखने के लिए हेमंत शर्मा अंग्रेजी के शब्दों से भी परहेज नहीं करते हैं. जैसे एक जगह वह शिव के लिए ट्रबल शूटर शब्द का इस्तेमाल करते हैं. यह शब्द उसी सहजता से आता है, जैसे गुलजार के एक मशहूर गाने की लाइन है, उनकी आंखें कमाल करती हैं, पर्सनल से सवाल करती हैं, में पर्सनल शब्द आता है. भाषा की यह बाजीगरी इस किताब को विशिष्टता प्रदान करती है.

इसके अलावा, जिस तरह के शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग इस किताब में है, वह इसकी भाषा को चमका देता है. हेमंत शर्मा बनारस के हैं, लिहाजा बनारसीपन पूरी किताब पर दिखाई देता है, भाषा में खास तौर पर, जैसे हवा तेजी से चुभ रही है, हड्डियां कड़कड़ा रही हैं. इसके अलावा, खालिस हिंदी पट्टी के जुमले– सूर्य अस्त, पहाड़ मस्त भी पाठकों को बांधे रखते हैं. कैलास मान सरोवर की यात्रा जैसे–जैसे आगे बढ़ती जाती है, वैसे–वैसे रोमांच भी अपने चरम पर पहुंचता जाता है. हाड़ कंपा देने वाली ठंड में भी तड़के ब्रह्ममुहूर्त में मान सरोवर का रहस्य जानने के लिए लेखक सुबह साढ़े तीन बजे गेस्ट हाउस से निकल कर सरोवर के किनारे पहुंच जाते हैं. उसके सामने वाणभट्ट की कादंबरी और कालिदास के रघुवंश एवं कुमार संभव साकार होने लगते हैं. लेकिन यहां भी एक दिलचस्प प्रसंग है, लेखक को उनके गाइड ने अकेले और बगैर छड़ी के बाहर निकलने से मना किया था, क्योंकि बाहर हिंसक कुत्तों का झुंड शिकार की तलाश में घूमता है, लेकिन मान सरोवर में सुबह–सुबह देवताओं और अप्सराओं के दर्शन के उत्साह में गाइड की सलाह भुलाकर वह अकेले सिर्फ़ कैमरे के साथ सरोवर तक पहुंच जाते हैं. काफी देर बाद अचानक जब पीछे मुड़कर देखते हैं, तो कुत्तों का एक झुंड. डर से होश फाख्ता. किसी तरह जान बची.

कैलास यात्रा के दौरान लेखक हेमंत शर्मा के अंदर के पत्रकार की पैनी नज़र और विश्लेषण का नज़रिया भी देखने को मिलता है. जब भी चीन या तिब्बत की बात आती है, तो तिब्बत को नष्ट करने के लिए वह चीन की लानत–मलामत करते हैं. साफ़ तौर पर उन्होंने तिब्बत की बर्बादी के लिए माओ को ज़िम्मेदार ठहराया है. साहित्य को नष्ट करने के लिए जिस तरह से ऐतिहासिक पांडुलिपियां चीनियों ने जलाईं, वह वामपंथ के चेहरे पर ऐसा काला दाग है, जो कभी भी मिट नहीं सकता और न ही उसे माफ़ किया जा सकता है. हिंदी में इस तरह की किताब बिरले ही दिखाई देती है. इस किताब का प्रोडक्शन बेहतरीन है और इसके लिए इसके प्रकाशक, यानी प्रभात प्रकाशन की भी तारीफ़ की जानी चाहिए. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

उर्दू शायरी

सियासत

सियासत मुफ़लिसों पर इस तरह अहसान करती है।
वो आंखें छीन लेती हैं और चश्मा दान करती है।।

इस प्रजातंत्र (जम्हूरियत) के दौर में वोट बैंक की राजनीति के कारण हमारे सियासी नेताओं ने इस देश में ऐसा ज़हर बो दिया है, जो बटवृक्ष बन जाने के कारण अब एक नासूर बन गया है. दरअसल, इस सियासत ने हमें अनेक फिरकों/खानों में बांटकर हमारी कौमी एकता को भी तार–तार कर दिया है, जिसके कारण किसी भी बुनियादी आम समस्या के हल के लिए लोग एक मंच पर आकर उसका निदान नहीं कर पाते. ऐसे में भ्रष्टाचार, महंगाई और पुलिसराज के ख़िलाफ़ होने वाले आंदोलन भी अपना वजूद खोकर बिखर जाते हैं. अन्ना और रामदेव द्धारा चलाए गए आंदोलन का हश्र भी हम सब देख चुके हैं. ज़ाहिर है कि सियासत ने लोगों को जोड़ने के बजाय बांटने/तक़सीम करने में अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि ...

मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है।
सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है।।

आदमी आदमी का दुश्मन है,
इस सियासत की मेहरबानी से।
इसीलिए यह कहा गया है ...
आप इस गर्दे सियासत में न खो जाएं कहीं।
अपनी तहजीब के दामन को बचाए रखिए।।

बचे ही रहना सियासत के नर्म लहजे हैं,
वे ही चुभोते हैं खंजर, जो फूल वाले हैं।।
उर्दू शायरी में इन सियासतदानों की फितरत पर भी काफ़ी रोशनी डाली गई है. इससे बचकर निकल जाने में ही भलाई है. क़ाबिले गौर है ...

जुबां से करते हैं, दिल से दुआ नहीं करते,
सियासी लोग किसी का भला नहीं करते।
वतन की मिट्टी का वो क़र्ज़ क्या चुकाएंगे,
जो मां के दूध का हक़ भी अदा नहीं करते।।

सियासी लोग कुछ ऐसा कमाल करते हैं,
चुनाव जीतकर हमको हलाल करते हैं।।

कहते हैं तुम्हारे शहर को जन्नत बना देंगे,
ये नेताओं के वादे हैं, न जाने कब भुला देंगे।
इस तरह उर्दू शायरी में सियासत पर भी काफ़ी कुछ लिखा गया है, जिससे हमें निश्चय ही कुछ न कुछ सबक लेना चाहिए, ताकि सियासत वालों से धोखा खाने से बचा जा सके. ■

–शिवकुमार *फ़ैज़ाबादी*

किताब मिली

पुस्तक	लेखक
साहब बाथरूम में हैं	आश करण अटल
प्रकाशक	**मूल्य**
डायमंड बुक्स	125 रुपये

सिनेमा के शताब्दी वर्ष पर हास्य व्यंग्य की एक अनूठी पुस्तक. हमारा सिनेमा कथाविहीन, चरित्र कितने कृत्रिम और दर्शक कितना बेबस है, यही इस किताब का मूल संदेश है.

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई–मेल: feedback@chauthiduniya.com

समीक्षा

आर्थिक पत्रकारिता की अहमियत

आर्थिक पत्रकार को अगर सही ढंग से अर्थ जगत की शब्दावलियों के बारे में जानकारी न हो, तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है. अंग्रेजी का हिंदी में भावानुवाद और जटिल शब्दों को सरल शब्दों में लिखना ही आर्थिक पत्रकारिता की सही पहचान है.

समीक्ष्य कृति : आर्थिक पत्रकारिता
लेखक : हिमांशु शेखर
प्रकाशक : डायमंड बुक्स
मूल्य : 150 रुपये

निर्मलेंदु

आर्थिक पत्रकारिता करनी है, तो आर्थिक शब्दों से जूझना बेहद ज़रूरी है. दरअसल, अर्थव्यवस्था में हर शब्द की एक खास अहमियत होती है. लेखक हिमांशु शेखर अपने तर्कों के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे शब्दों को समझे बगैर, न तो सही तरह से पत्रकारिता हो सकती है और न ही लेखक पाठकों को ठीक से समझा सकता है. इस किताब के माध्यम से उन्होंने पाठकों को कई उदाहरण देकर समझाने की कोशिश भी की. एडीआर और जीडीआर का क्या मतलब होता है, इस पर भी उन्होंने रोशनी डाली. पीटीसी क्या है, इस पर उन्होंने विस्तार से बताया. उन्होंने बताया कि पीटीसी एक ऐसा प्रमाणपत्र है, जो किसी संपत्ति को गिरवी रखने के बदले में निवेशक को दिया जाता है. ये बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा निवेशकों को जारी किए जाने वाले बॉन्ड या डिबेंचर की तरह होते हैं.

उन्होंने जानकारी दी कि आम तौर पर पीटीसी में वित्तीय संस्थाएं, जैसे बैंक, म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियां ही निवेश करती हैं. दरअसल, लेखक का तर्क यह भी है कि अगर सही ढंग से इन टर्मों के बारे में लिखने वाले को जानकारी न हो, तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है. मतलब यह कि आर्थिक पत्रकारिता करने से पहले सही तरह से पढ़ना और जानना बेहद ज़रूरी है. लेखक ने लगे हाथों यह सलाह भी दे दी कि हिंदी की आर्थिक और बिजनेस पत्रकारिता करने के लिए यह बेहद ज़रूरी है कि सही ढंग से अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करना आए. मतलब, चूंकि ख़बर लिखने के लिए जो भी सामग्री मिलती है, वह आम तौर पर अंग्रेजी में ही होती है, इसलिए अगर आप डेस्क के साथ–साथ रिपोर्टिंग भी कर रहे हों, तो अनुवाद से साबका आपका होगा ही. ऐसे में, अंग्रेजी जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है. अनुवाद करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि शब्दशः अनुवाद न हो और भावानुवाद को महत्व दिया जाए. जटिल शब्दों को सरल शब्दों में लिखना ही आर्थिक पत्रकारिता की सही पहचान है. हां, अनुवाद करते वक्त अगर कोई कठिन तकनीकी शब्द आ जाए, तो बेहतर यही होगा कि उस शब्द को अंग्रेजी में ही जाने दें, ताकि अर्थ का अनर्थ न हो.

ध्यान रहे कि अनुवाद किसी भी दृष्टि से अनुवाद न लगे. पढ़ने वाले को यह एहसास हो कि जिस ख़बर को वह पढ़ रहा है, वह मूल रूप से हिंदी में ही लिखी गई है. वैसे, अनुवाद करना भी एक कला है और यह कला नियमित अभ्यास के जरिए ही आत्मसात की जा सकती है, बशर्ते कि हर शब्द का सही अर्थ लेखक जानता और समझता हो. हिमांशु यह समझाने की कोशिश करते हैं कि अनुवाद तभी सही तरह से पठनीय होता है, जब पत्रकार एक भाषा से दूसरी भाषा की आत्मा को समझे. ध्यान रहे कि अगर मूल पाठ को समझने में कोई दिक्कत हो, तो अर्थ का अनर्थ होने का ख़तरा सौ प्रतिशत बना रहता है.

आर्थिक पत्रकारिता करने वाले लोगों को यह समझने की कोशिश भी करनी चाहिए कि आखिर किसी खास क्षेत्र के बजट में अगर सरकार बेतहाशा वृद्धि कर रही है, तो उसकी असली वजह क्या है? यहां यह जानना और लोगों को समझाना भी जरूरी होता है, क्योंकि ऐसी बढ़ोत्तरी के लिए सरकार कुछ और तर्क देती है, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही होती है.

आर्थिक पत्रकारिता करने वालों को इस बात से भी वाकिफ होना चाहिए कि भले ही एक तरफ देश में विदेशी मुद्रा भंडार और अरबपतियों की संख्या बढ़ रही हो, लेकिन दूसरी ओर एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है, जो दिनोंदिन और, और गरीब होता जा रहा है. याद रखें, समाज में चौतरफा फैल रही विषमता के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार आर्थिक गैरबराबरी ही है. दरअसल, आर्थिक असमानता की वजह से ही समाज में जीवनशैली, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास के अलावा, कई बुनियादी मोर्चों पर गैरबराबरी बढ़ रही है. इन सभी मुद्दों पर लिखते वक्त हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि कहीं हम पूंजीपतियों की जी हुजूरी में तो नहीं लग गए हैं. दरअसल, हमें लिखते वक्त यह ध्यान भी रखना होगा कि आर्थिक गैरबराबरी की वजह से ही राज और समाज में कई तरह की विषमता फैलती है. इसलिए सरकार अगर कुतर्क करती है कि विकास हो रहा है, तो हमें समझना होगा कि क्या सही में विकास हो रहा है, या सरकार लोक–लुभावने आंकड़ों से हमें, यानी जनता को बेवकूफ बना रही है.

हिमांशु शेखर ने मुद्रास्फीति, पीएलआर, सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, टीजर लोन से लेकर वायदा कारोबार और आयकर की धारा 80–बी के बारे में ईमानदारी से पूरी जानकारी दी. 185 पृष्ठ की यह किताब आर्थिक पत्रकारिता कर रहे लोगों के लिए बेहद उपयुक्त है. लेखक के अंदर आर्थिक पत्रकारिता की जो बारीक समझ है, वह काफी सटीक है. ■

feedback@chauthiduniya.com

> तिपहिया वाहन (थ्री–व्हीलर) निर्माता के रूप में जानी जाने वाली कंपनी बजाज ऑटो लिमिटेड इन वाहनों के बाजार को बदलने की तैयारी में है. फिर से बादशाह बनना चाहती है यह कंपनी. कंपनी ने आरई 60 कोड नाम के साथ एक क्वाड्रीसाइकिल तैयार की है.

अन्य ख़बरें

स्पाइस कूल स्मार्टफोन

स्पाइस का यह स्मार्टफोन एंड्रॉएड जैली बीन 4.1 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है. साथ ही इसमें लेटेस्ट वर्जन से अपडेट करने का विकल्प भी मौजूद है. स्मार्टफोन में ड्युअल सिम स्लॉट उपलब्ध कराया गया है. इस डिवाइस में पांच कपैसिटिव डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 540–960 पिक्सल है. स्मार्टफोन में पांच मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा भी दिया गया है. इसके अलावा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए डिवाइस में वीजीए वेबकैम भी दिया गया है. इसका रैम एक जीबी का है. एमआई–515 में चार जीबी की इंटरनल मेमरी उपलब्ध कराई जा रही है और इसे 32 जीबी तक एक्सपैंड किया जा सकता है. इसका वजन 161 ग्राम है और कीमत है मात्र 9,990 रुपये. ■

एचसीएल मी कनेक्ट 2जी 2.0

एचसीएल ने मी कनेक्ट 2जी 2.0 टैबलेट लॉन्च किया है. डिवाइस का खास फीचर भारत की 11 क्षेत्रीय भाषाओं को सपोर्ट करता है. साथ ही इसमें 2जी वीडियो कॉलिंग की सुविधा भी मौजूद है. इसमें सात ईंच का मल्टीटच डिस्प्ले उपलब्ध कराया गया है और यह एंड्रॉयड जैली बीन 4.1 ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है. यह डिवाइस एंटरटेनमेंट के कई एप्लीकेशन और गेम्स से लोडेड है. इसके अलावा इसमें हेल्थ, बिजनेस, एजुकेशन और लाइफस्टाइल से संबंधित काफी कंटेंट मौजूद हैं. डिवाइस में एक गीगा हर्ट्ज की प्रोसेसिंग क्षमता वाला एआरएम कोरटेक्स ई9 प्रोसेसर लगाया गया है. इसमें चार जीबी की ऑन बोर्ड मेमरी मौजूद है, जिसे 32 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. इसकी कीमत है 8,499 रुपये. ■

एचटीसी डिजायर एक्ससी

एचटीसी डिजायर एक्ससी में ड्युअल सिम स्लॉट उपलब्ध कराया गया है. एचटीसी के इस डिवाइस में चार ईंच की डब्ल्यूवीजीए सुपर एलसीडी टचस्क्रीन मौजूद है. साथ ही इसमें पांच मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा भी दिया गया है. डिजायर एक्ससी एंड्रॉयड आइसक्रीम सैंडविच 4.0 ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित स्मार्टफोन है. यह डिवाइस एक गीगा हर्ट्ज के ड्युअल कोर प्रोसेसर से लैस है और इसमें चार जीबी की ऑन बोर्ड मेमरी उपलब्ध कराई जा रही है. बैकअप के लिए एक्ससी में 1650 एमएएच की बैटरी दी गई है. डिवाइस की रैम 768 एमबी की है. इसकी कीमत है 16,500 रुपये.■

95 लाख रुपये की कार

एडवांस्ड गियरबॉक्स की बदौलत कार 7 सेकेंड से कम समय में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है. नए मॉडल में ईको-प्रो मोड है, जिससे इंजन से अतिरिक्त दबाव को कम किया गया है.

बीएमडब्ल्यू ने 7–सीरीज का फेसलिफ्ट मॉडल 730एलडी लॉन्च किया है, पर नए मॉडल में कुछ खास बदलाव नहीं है. कंपनी ने कार की क्षमता को बेहतर, आरामदायक और पावरफुल बनाने पर जोर दिया है, जिसमें उसे काफी सफलता मिली है. कार की क्षमता और स्पीड में भी बदलाव आया है. न्यू 8–स्पीड गियरबॉक्स फीचर नया है, जिससे कार की क्षमता और स्पीड में बदलाव देखने को मिल रहे हैं. पुराने मॉडल की तरह नया मॉडल 2993 सीसी स्ट्रेट–6 डीजल मोटर से लैस है. एडवांस्ड गियरबॉक्स की बदौलत कार 7 सेकेंड से कम समय में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर दौड़ती है. नए मॉडल में ईको–प्रो मोड है, जिससे इंजन से अतिरिक्त दबाव को कम किया गया है. साउंड इंसुलेशन सिस्टम को बेहतर बनाया गया है, जिससे केबिन में बाहर का या इंजन का शोर ज्यादा सुनाई नहीं देता है.

इंटीरियर में कई बदलाव लाए गए हैं. पीछे बैठे लोग आसानी से दिखाई दें, इसके लिए सीट को स्लिम रखा गया है. कार को लग्जरी लुक देने के लिए डैशबोर्ड पर स्ट्रिप दी गई है. इसमें कई नए इंस्ट्रूमेंट हैं. ड्राइव मोड के अनुसार, इनका रंग बदला जा सकता है. आई–ड्राइव सिस्टम अपडेट किया गया है.

बीएमडब्ल्यू 7–सीरीज के फीचर्स

- इंजन: 6–सिलेंडर, 2993 सीसी
- टर्बो–डीजल
- पावर:255 बीएचपी–4000 आरपीएम
- टॉर्क: 57 किलो–1500 आरपीएम
- गियरबॉक्स: 8 स्पीड ऑटोमेटिक
- व्हीलबेस: 3210 एमएम
- टायर: 245/55 आर17
- एल/डब्ल्यू/एच: 3219/2142/1481एमएम
- 0–100 केपीएच : 6.61 सेकेंड
- नया 8–स्पीड गियरबॉक्स जबर्दस्त है
- रीयर सीट से बिजनेस–क्लास कम्फर्ट मिलता है
- हेडलैंप को एलईडी ट्रीटमेंट दिया गया है

क्या है खास: केबिन में शोर बिल्कुल सुनाई नहीं देता है. इंजन और गियरबॉक्स का रिस्पॉन्स अच्छा है.
क्या है कमी: कार को चलाने में खास मजा नहीं आता है. केबिन कुछ खास आकर्षक नहीं है.
कीमत : 95 लाख रुपये (अनुमानित, एक्स–शोरूम नई दिल्ली) ■

निसान की प्रीमियम एसयूवी कार

जापानी ऑटो मेकर निसान भारतीय बाजार में अपनी प्रीमियम स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) लॉन्च करने की तैयारी में है. निसान टेरैनो नाम की इस एसयूवी को कंपनी जल्द ही लॉन्च करने वाली है. इस बारे में निसान मोटर इंडिया के प्रेसिडेंट और सीईओ केनिचिरो योमुरा ने कहा कि टेरैनो के जरिए हमें भारतीय बाजार में बिक्री बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी. योमुरा के मुताबिक, टेरैनो निसान के लिए काफी महत्वपूर्ण मॉडल साबित होगी. ऐसे में हमें इस एसयूवी के नाम और पहली झलक का खुलासा करने में काफी खुशी हो रही है. उन्होंने कहा कि इस एसयूवी के प्रदर्शन और अन्य फीचर के बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी. गौरतलब है कि निसान मोटर इंडिया, जापान की निसान मोटर कंपनी लिमिटेड की 100 फीसदी हिस्सेदारी वाली सहायक कंपनी है.

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

बजाज थ्री व्हीलर फिर बना बादशाह

लोग चौपहिया वाहन होने के कारण आरई 60 को सस्ती कार मान रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं. दरअसल, यह चार पहियों वाला ऑटो ही है. इसमें चार पहिये होने की वजह से इसे क्वाड्रीसाइकिल की श्रेणी में रखा जाएगा. वैसे, नए सेगमेंट के इस ऑटो वाहन के लिए अभी नियम भी नहीं बने हैं. इसमें कार जैसी स्पीड भी नहीं है. कंपनी इसे चार पहियों वाले ऑटो के रूप में पेश कर रही है.

तिपहिया वाहन (थ्री–व्हीलर) निर्माता के रूप में जानी जाने वाली कंपनी बजाज ऑटो लिमिटेड इन वाहनों के बाजार को बदलने की तैयारी में है. फिर से बादशाह बनना चाहती है यह कंपनी. कंपनी ने आरई 60 कोड नाम के साथ एक क्वाड्रीसाइकिल तैयार की है. कंपनी का भविष्य में इरादा पैसेंजर तिपहिया वाहनों के बाजार में इसे एक मजबूत विकल्प के तौर पर उतारने का भी है.

कंपनी ने पहली बार इसे 2012 के दिल्ली ऑटो एक्सपो के दौरान प्रदर्शित किया था. अब यह वाहन भारतीय बाजार में लॉन्चिंग के बेहद करीब है. कुछ लोग चौपहिया वाहन होने के चलते इसे सस्ती कार मान रहे हैं. बजाज के इस नए चौपहिया वाहन के भारतीय सड़कों पर दस्तक देने के बाद इसकी बेहद संभावना है कि थ्री–व्हीलर या ऑटो बीते जमाने की बात हो जाए. किसी भी थ्री–व्हीलर के मुकाबले यह वाहन हर लिहाज से बेहतर है.

कवर्ड होने के चलते इसमें ऑल–वेदर प्रोटेक्शन मिलती है. इसके अलावा, चार पहियों की वजह से इसकी ब्रेकिंग क्षमता और सड़क पर स्टेबिलिटी तिपहिया वाहनों के मुकाबले बहुत बेहतर होगी. लिहाजा, शुरुआत से ही यह वाहन तिपहिया वाहनों पर भारी पड़ेगा. इसके अलावा आरई60 का माइलेज इसका सबसे मजबूत पक्ष है.

216 सीसी पेट्रोल इंजन से लैस यह वाहन 35–40 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगा. इसके अलावा, कंपनी की योजना यह भी है कि भविष्य में इसे सीएनजी, डीजल या इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स में भी लॉन्च करे. फिलहाल, इस वाहन को भारतीय बाजार में कंपनी लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. कंपनी को सिर्फ इंतजार है, तो क्वाड्रीसाइकिल संबंधी नए नियमों का. सरकार ने क्वाड्रीसाइकिल संबंधी नियमों को तैयार करने के लिए एक तकनीकी कमेटी की स्थापना कर दी है. यह कमेटी अगले कुछ महीनों के दौरान अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी. रिपोर्ट आने के बाद, इस वाहन में बदलाव कर बजाज ऑटो इसे भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकेगी. ■

खूबियां

- ऑटो का हो सकता है मजबूत विकल्प
- 216 सीसी पेट्रोल इंजन की क्षमता से लैस
- 35–40 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज
- 20 हॉर्सपावर की अधिकतम पावर मुहैया कराना
- 70 किलोमीटर है इसकी अधिकतम स्पीड
- सीएनजी में भी जल्द हो सकता है लॉन्च

वॉल्वो की वी40 क्रॉस कंट्री कार

स्वीडन की लग्जरी कार मेकर वॉल्वो ने कॉम्पैक्ट कार श्रेणी में कदम रखने की घोषणा की है. कंपनी ने 28.5 लाख रुपये में वी40 क्रॉस कंट्री कार लॉन्च की है. यह लॉन्चिंग वॉल्वो की भारत में बिक्री बढ़ाने की रणनीति का एक अहम हिस्सा है. गौरतलब है कि इस साल वॉल्वो इंडिया अपनी बिक्री में 50 फीसद का इजाफा करने की तैयारी में है. इसके तहत कंपनी भारत में बिक्री को 1,200 यूनिट तक बढ़ाएगी. अपनी नवीनतम कार पर इंश्योरेंस उपलब्ध कराने के लिए वॉल्वो ऑटो इंडिया ने बजाज एलियांज के साथ टाई-अप किया है. कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर टॉमस अर्नबर्ग ने कहा कि भारत में लॉन्च की जा रही यह नई कार, देश में हमारे कारोबार की बढ़ोत्तरी का रणनीतिक हिस्सा है. अभी तक, हमें इसके लिए 70 यूनिट की बुकिंग मिल चुकी है और इस साल के लिए हमने 120 यूनिट बेचने का लक्ष्य रखा है. उन्होंने कहा कि बिक्री बढ़ाने के लिए कंपनी दो नए कार और लॉन्च करेगी. लिहाजा, अक्टूबर तक सिडान एस60 और एसयूवी एक्ससी60 के नए मॉडल उतारे जाएंगे. पिछले साल कंपनी ने करीब 800 यूनिट की बिक्री की थी और इस साल के लिए हमने 1,100 से 1,200 यूनिट का लक्ष्य तय किया है. इस साल की पहली तिमाही में कंपनी ने 276 यूनिट की बिक्री की, जबकि एक साल पहले समान अवधि में 140 यूनिट की बिक्री की गई थी. ■

एप्पल का नया आईपैड

एप्पल ने नया आईपैड मिनी बाजार में पेश किया है. इसकी स्क्रीन 7.9 ईंच की है. 325 डॉलर यानी करीब 18,000 रुपये का आईपैड मिनी अभी अमेरिका में लॉन्च हुआ है, लेकिन दिसंबर तक इसके भारत में आने की संभावना है. यह आईपैड मिनी दुनिया का सबसे पतला आईपैड है. आईपैड मिनी में आईपैड वाले सारे फीचर हैं. तेज प्रोसेसिंग के लिए आईपैड मिनी में ए5 ड्यूअलकोर प्रोसेसर है. वीडियो कॉलिंग के लिए 5 मेगापिक्सल का फेसटाइम एचडी कैमरा है, जिसमें फुल एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग मुमकिन है. आईपैड मिनी का मुकाबला सैमसंग गैलक्सी टैब 2 और गूगल नैक्सस 7 से होगा. आईपैड मिनी के तीन वर्जन हैं 16, 32 और 64 जीबी. 16 जीबी वाईफाई है, जिसकी कीमत 329 डॉलर यानी करीब 18,000 रुपये है. 64 जीबी 4जी वर्जन है, जिसकी कीमत 459 डॉलर यानी करीब 24,000 रुपये है. मिनी आईपैड के लॉन्च के मौके पर एप्पल ने छह महीने बाद चौथी पीढ़ी के आईपैड लॉन्चिंग की भी घोषणा कर डाली. ■

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

भारतीय टीम क्षेत्ररक्षण के मामले में अन्य टीमों के मुकाबले बेहतर साबित हुई. सुरेश रैना, विराट कोहली, दिनेश कार्तिक, रोहित शर्मा, आर अश्विन और शिखर धवन ने फील्डिंग के स्तर को इतना ऊपर उठा दिया कि भारतीय टीम 1992 के विश्व कप में भाग लेने वाली दक्षिण अफ्रीकी टीम की तरह लग रही थी, जो कि अपनी बेहतरीन फील्डिंग के भरोसे विपक्षी टीम को एक–एक रन बनाने के लिए कड़ी मशक्कत कराती थी और हर मैच में 20 से 30 रन बचा लेती थी.

आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की शानदार जीत ने यह साबित कर दिया है कि अब क्रिकेट में जीत पुराने खिलाड़ियों के भरोसे नहीं है, क्योंकि इस ट्रॉफी में सचिन, सहवाग, गौतम गंभीर और जहीर खान जैसे खिलाड़ी नहीं थे. सही मायनों में यदि देखा जाए, तो यह यंगिस्तान की जीत ही कहलाएगी.

यंग क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया

यंगिस्तान की जीत

नवीन चौहान

भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को पांच रनों से हरा कर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है. साथ ही दुनिया को यह संदेश भी दे दिया है कि विश्व क्रिकेट में अब भी भारत की तूती बोलती है. देखा जाए, तो सही मायने में यह यंगिस्तान की जीत है. सचिन तेंदुलकर के एकदिवसीय क्रिकेट से संन्यास लेने और वीरेंद सहवाग, गौतम गंभीर और जहीर खान जैसे वरिष्ठ खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था. उसके बाद ही नए और युवा खिलाड़ियों के भारतीय टीम को जीत के रास्ते पर ले जाने की बहुत कम संभावनाएं जताई जा रही थीं, लेकिन महेंद्र सिह धोनी जैसे शांत, चपल और शातिर कप्तान ने अपनी बेहतरीन कप्तानी के बल पर असंभव को संभव कर दिखाया. इसके साथ ही वह टी–20 विश्वकप, एक दिवसीय क्रिकेट का विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले विश्व के पहले और अकेले कप्तान बन गए हैं. भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में चमत्कारिक प्रदर्शन करके अपराजेय रही. यहां तक कि यह टीम अभ्यास मैचों को भी बड़े अंतर से जीतने में सफल रही. सच तो यह है कि आईपीएल के दौरान हुई स्पॉट फिक्सिंग और उससे उपजे विवाद का असर भारतीय टीम पर बिल्कुल दिखाई नहीं दिया. खिलाड़ियों ने अपने खेल पर ध्यान दिया, परिणामस्वरूप नए–नए सितारों से सजी टीम इंडिया लोगों के सामने आ खड़ी हुई.

भारतीय टीम की जीत में सबसे प्रमुख भूमिका शिखर धवन ने अदा की. टूर्नामेंट में भाग लेने वाली अन्य टीमों और गब्बर कहे जाने वाले शिखर धवन ने भारतीय टीम को सबसे बड़े अंतर पर ला खड़ा किया. एकदिवसीय टीम में लंबे समय बाद वापसी करने वाले धवन इतने सहज और आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, जैसे वह लंबे समय से टीम के लिए पारी की शुरुआत कर रहे हों. दक्षिण अफ्रीकी टीम जैसी मजबूत टीम की सशक्त गेंदबाजी का सामना करते हुए उन्होंने प्रतियोगिता के पहले ही मैच में 84 गेंदों में शतक जड़कर यह संदेश दिया कि वह लंबे समय तक टीम इंडिया का हिस्सा बने रहेंगे. साथ ही वह प्रसंशकों को नज़फगढ़ के नवाब वीरेंद्र सहवाग की कमी भी नहीं खलने देंगे. गौरतलब है कि चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान शिखर धवन अपने खेल के शिखर पर थे. इस दौरान उन्होंने किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शा. उन्होंने प्रतियोगिता में खेले कुल पांच मैचों में दो शतक और एक अर्धशतक की मदद से 362 रन बनाए. चैंपियनशिप में उनका औसत 90.5 और स्ट्राइक रेट 101.39 का था. उन्हें सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज घोषित किया गया. शिखर के धमाकेदार टेस्ट डेब्यू के बाद लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर ने कहा था कि भारतीय टीम में जगह बनाने के लंबे इंतजार ने शिखर की रन बनाने की भूख को बढ़ा दिया है. उन्हें केवल थोड़ा सा धैर्य रखने और पिच पर ज्यादा वक्त गुजारने की जरूरत है. शिखर की धमाकेदार प्रदर्शन के बाद अब वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह और गौतम गंभीर के लिए भारतीय टीम में वापसी करना मुश्किल हो गया है.

इस बार टीम इंडिया की तेज गेंदबाजी की कमान इशांत शर्मा, उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार के हाथों में, तो स्पिन गेंदबाजी की कमान रामचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा के हाथों में थी. युवा भुवनेश्वर कुमार ने अपनी इकोनॉमी गेंदबांजी की बदौलत भारत को हर मैच में एक सधी हुई शुरुआत दे रहे थे. इशांत शर्मा ने सबसे अनुभवी गेंदबाज के रूप में तेज गेंदबाजी की कमान अपने हाथ में ले रखा था. उन्होंने प्रतियोगिता में 21.80 की औसत से कुल 10 विकेट लिए. फाइनल मैच में 33 रन देकर उन्होंने 3 अंग्रेज बल्लेबाजों को न केवल पवेलियन का रास्ता दिखाया, बल्कि टीम की जीत में महत्व–पूर्ण भूमिका भी अदा की. पूरे टूर्नामेंट में रविंद्र जडेजा की फिरकी का जादू ऐसा चला कि वह टूर्नामेंट में सबसे सफल गेंदबाज बन गए. जब–जब विकेट की जरूरत पड़ी, उन्होंने अपने कप्तान को निराश नहीं किया. वेस्टइंडीज के खिलाफ 36 रनों पर 5 विकेट लेकर जडेजा ने चैंपियंस ट्रॉफी का भारतीय रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. उन्होंने प्रतियोगिता में 12.83 की औसत से कुल 12 विकेट लिए. उन्हें इसके लिए गोल्डन बॉल के खिताब से नवाजा गया. इसके अलावा जडेजा ने अपने बल्ले का जौहर भी समय आने पर दिखाया. पूरी प्रतियोगिता में वह कप्तान के लिए तुरुप का इक्का साबित हुए, जिसकी काट किसी भी टीम के पास नहीं. उमेश यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभ्यास मैच में 5 विकेट लेकर और ऑस्ट्रेलिया को सस्ते में समेट कर यह बता दिया था कि गेंदबाजी भारतीय टीम की कमजोर कड़ी नहीं है. कुल मिलाकर भारतीय गेंदबाजी संतुलित और सधी हुई दिखाई दी.

भारतीय टीम की जीत में सबसे प्रमुख भूमिका शिखर धवन ने अदा की. टूर्नामेंट में भाग लेने वाली अन्य टीमों और गब्बर कहे जाने वाले शिखर धवन ने भारतीय टीम को सबसे बड़े अंतर पर ला खड़ा किया. एकदिवसीय टीम में लंबे समय बाद वापसी करने वाले धवन इतने सहज और आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, जैसे वह लंबे समय से टीम के लिए पारी की शुरुआत कर रहे हों.

भारतीय टीम क्षेत्ररक्षण के मामले में अन्य टीमों के मुकाबले बेहतर साबित हुई. सुरेश रैना, विराट कोहली, दिनेश कार्तिक, रोहित शर्मा, आर अश्विन और शिखर धवन ने फील्डिंग के स्तर को इतना ऊपर उठा दिया कि भारतीय टीम 1992 के विश्व कप में भाग लेने वाली दक्षिण अफ्रीकी टीम की तरह लग रही थी, जो कि अपनी बेहतरीन फील्डिंग के भरोसे विपक्षी टीम को एक–एक रन बनाने के लिए कड़ी मशक्कत कराती थी और हर मैच में 20 से 30 रन बचा लेती थी. दरअसल, बेहतरीन फील्डिंग का सीधा असर गेंदबाजों के प्रदर्शन पर पड़ता है. खराब गेंद पर अगर फील्डर रन बचा लेता है, तो गेंदबाज ज्यादा आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी करता है. यह टीम को मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाल लाती है. 20 ओवर के फाइनल मुक़ाबले को भारतीय टीम बेहतरीन फील्डिंग के भरोसे जीत लिया. इंग्लैंड की टीम के लिए 130 रनों का लक्ष्य 140 रनों जैसा लग रहा था. जिस टीम में अच्छे फील्डरों की फौज हो, वह टीम जीत के लिए ज्यादा भूखी हो जाती है. यह टीम आसानी से हार नहीं मानती है. यही एटीट्यूड अब भारतीय टीम में दिखाई देता है. यह भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत है. कुछ समय पहले सीनियर खिलाड़ियों की उपस्थिति से टीम को उनके अनुभव का लाभ तो मिल जाता था, लेकिन फील्डिंग की धार कुंद नजर आने लगती थी. कई मौकों पर यही बात भारतीय टीम के हार का कारण भी रही है. 2011 का विश्वकप जीतने वाली भारतीय टीम के आधे से ज्यादा खिलाड़ी इस वक्त टीम से बाहर हैं. बावजूद इसके, यह टीम बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है. कई मायनों में यह विश्व विजेता टीम ज्यादा सशक्त दिखाई पड़ रही है. यदि युवा खिलाड़ी धोनी के नेतृत्व में विश्वास रखते हुए यह टीम अच्छा प्रदर्शन करती रहे, तो भारतीय टीम को 2015 का विश्व कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता. ■

navinchauhan@chauthiduniya.com

खेल खबरें

टूर डी फ्रांस के आयोजन के 100 साल पूरे

विश्व की सबसे प्रतिष्ठित और ग्लैमरस साइकिल रेस टूर डी फ्रांस अपना सौवां टूर आयोजित कर रहा है. गौरतलब है कि 110 साल पहले सन 1903 में इस प्रतियोगिता का पहली बार आयोजन किया गया था. पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसका आयोजन नहीं किया गया. दरअसल, आयोजक इस आयोजन में डोपिंग प्रकरण को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके सामने आने पर प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को सबसे ज्यादा धक्का लगा था. जी हां, इस प्रकरण के सामने आने के बाद पिछले 15 टूर में से 9 टूर के विजेताओं से खिताब वापस ले लिए गए थे, जिसमें अमेरिका के लांस आर्मस्ट्रांग का नाम सबसे प्रमुख है, जिन्होंने सात बार यह खिताब अपने नाम किया था. ■

टूट सकता है सचिन का टेस्ट रिकॉर्ड!

आपको जानकर हैरानी होगी कि इंग्लैंड के कप्तान एलिएस्टर कुक मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का सर्वाधिक टेस्ट रनों के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं. यह बात हम नहीं, बल्कि इंग्लैंड के खिलाड़ी पीटरसन ने कही. उन्होंने कहा कि कुक की उम्र अभी बहुत कम है. गौरतलब है कि 29 साल की उम्र में वह इंग्लैंड के लिए 92 टेस्ट खेल चुके हैं और 7252 रन बना चुके हैं. अगर वह इसी कंसिसटेंसी से खेलते रहे, तो वह विश्व के सर्वाधिक टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज बन सकते हैं. गौरतलब है कि सचिन तेंदुलकर अब तक 198 टेस्ट मैचों में 15837 रन बना चुके हैं. सचिन अब भी टेस्ट मैचों में भारत की ओर से शिरकत करते दिख रहे हैं. इस रिकॉर्ड में अभी और इज़ाफा होना है. हालांकि सचिन के खेलते रहने से उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ना कुक के लिए शायद आसान नहीं होगा. ■

सायना विश्व रैंकिंग में नंबर तीन पर पहुंचीं

ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय बैडमिंटन सनसनी सायना नेहवाल विश्व रैंकिंग में तीसरे पायदान पर पहुंच गई हैं. हाल ही में जारी रैंकिंग में सायना के 73510 अंक हैं. दरअसल, सायना इस साल मार्च तक करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग दूसरे नंबर पर बनी हुई थीं, लेकिन थाईलैंड और इंडोनेशिया में खिताब का बचाव नहीं कर पाने से वह चौथे स्थान पर खिसक गई थीं. सिंगापर में अंतिम आठ में पहुंचने के कारण वह तीसरा स्थान हासिल करने में कामयाब रहीं. गौरतलब है कि मलेशियाई ओपन विजेता पीवी सिंधु घुटने की चोट के कारण जून में लगातार दो टूर्नामेंट में भाग नहीं ले सकी थीं. उन्हें रैंकिंग में 12वां स्थान हासिल हुआ है. चीन की लि जुरेई और यिहान वांग रैंकिंग में क्रमश: पहले और दूसरे स्थान पर काबिज हैं. पुरुष एकल में पी कश्यप के खराब प्रदर्शन का असर उनकी रैंकिंग पर भी पड़ा है. वह दो पायदान के नुकसान से 15वें से 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं. इनके अलावा, आरएमवी गुरु साईदत्त और अजय जयराम भी पुरुष एकल रैंकिंग में क्रमश: 22वें और 24वें स्थान पर पहुंच गए हैं. ■

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया
जगमग दुनिया
Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467
08 जुलाई–14 जुलाई 2013

सूरज की पहचान सिर्फ़ आदित्य पंचोली के बेटे के रूप में है. ज़िया हर लिहाज से सूरज से श्रेष्ठ थीं, फिर सवाल यह उठता है कि उन्होंने सूरज को क्यों चुना? सूरज एक आकर्षक फिजिक के मालिक हैं. लड़कियां उनकी डिलडौल और पर्सनैलिटी से आकर्षित हो जाती थीं.

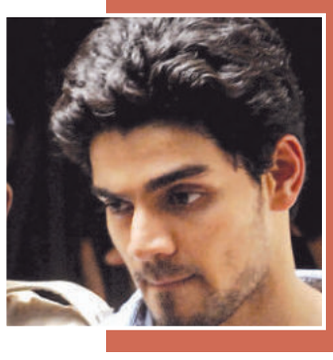

ख़ुदकुशी के लिए ज़िया ख़ुद ज़िम्मेदार

चौथी दुनिया ब्यूरो

प्यार, वफा, शक, नफरत और फिर ख़ुदकुशी. दो प्यार करने वालों में से एक दुनिया में नहीं है और दूसरा है सलाखों के पीछे. सूरज के जेल जाने को भले ही हम उसकी ग़लती की सज़ा के रूप में देख रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में क्या वाकई सूरज गुनहगार है? भला किस प्रेमी युगल में नोंक-झोंक नहीं होती! ज़िया और सूरज के बीच भी लड़ाई होती होगी, लेकिन अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना किसी कमजोर मानसिकता की ही निशानी कही जाएगी.

जिया की खुदकुशी पर पहले मीडिया ने फिल्म इंडस्ट्री को ज़िम्मेदार ठहराया. कहा गया कि उन्हें काम नहीं मिल रहा था. हम आपको बता दें कि मात्र 18 साल की उम्र में ज़िया ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ काम किया. उसके बाद मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर ख़ान और अक्षय कुमार के साथ भी उन्होंने काम किया. उन्होंने बड़े स्टार्स के साथ एक नहीं, तीन-तीन हिट फिल्में कीं. बाद में तहक़ीक़ात के बाद पता चला कि उन्होंने प्यार में नाकामयाबी मिलने की वजह से खुदकुशी कर ली. फिर यहां एक बड़ा सवाल यह है कि क्या ज़िया इतनी नादान थीं कि प्यार में नाकामयाबी मिलने पर मौत को गले लगा लें. वह कोई 15-16 साल की नासमझ लड़की तो थीं नहीं. ज़िया ने दुनिया देखी थी, लेकिन वह फैंटेसी की दुनिया में जीने वाली लड़कियों में से थीं. जिया ने अपने लेटर में अपना सबकुछ सूरज को समर्पित कर देने की बात लिखी थी. जिस समर्पण की बात उन्होंने अपने लेटर में लिखा था, क्या आज के समय में प्यार में समर्पण का कुछ ख़ास मतलब है? उनके लिए मां-बहन, परिवार और किसी रिश्ते का कोई मतलब नहीं था, सिवाए प्यार के.

देखा जाए, तो जिया और सूरज हमउम्र थे, बल्कि ज़िया सूरज से एक साल बड़ी थीं. या यूं कहें कि ज़िया कुछ मायनों में सूरज से कहीं ज़्यादा अनुभवी थीं. उन्होंने दुनिया देखी था. इंग्लैंड और अमेरिका में उनकी परवरिश हुई. करियर भी ठीक-ठाक था. पहली ही फिल्म से उन्हें अपार सफलता मिली. उन्होंने कुल तीन फिल्में कीं. वे भी बड़े बजट की. अभी और मेहनत करतीं और चुजी नहीं होतीं, तो उन्हें और काम मिलता. ज़िया को पढ़ने-लिखने का भी काफ़ी शौक़ था. वह काफ़ी क्रिएटिव भी थीं. वह अभिनेत्री होने के साथ ही गायिका भी थीं. अपनी पहली फिल्म नि:शब्द का एक गाना उन्होंने ख़ुद गाया था. वह अपना बैंड बनाना चाहती थीं. अपनी ऊर्जा को वह सही जगह लगातीं, तो बहुत कुछ कर सकती थीं और एक मिसाल बन सकती थीं. वह पब्लिक फिगर थीं. वहीं दूसरी ओर मात्र 23 साल के सूरज फिल्मों में आने के लिए हाथ-पैर मार रहे थे. अभी उनके करियर की शुरुआत भी नहीं हुई थी. सूरज की पहचान सिर्फ़ आदित्य पंचोली के बेटे के रूप में है. ज़िया हर लिहाज से सूरज से श्रेष्ठ थीं, फिर सवाल यह उठता है कि उन्होंने सूरज को क्यों चुना? सूरज एक आकर्षक फिजिक के मालिक हैं. लड़कियां उनकी डिलडौल पर्सनैलिटी से आकर्षित हो जाती थीं. मतलब साफ़ है, ज़िया उनके लुक से प्रभावित थीं. शायद इसीलिए वह सूरज को लेकर ओवर पोजेसिव भी थीं. सच तो यह है कि ज़िया जैसी लड़कियां या यूं कहें कि ज़िया जैसे लोग अपनी बेवकूफी से ही मरते हैं. लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि वे हमेशा सपनों के पीछे भागती हैं. उन्हें लगता है कि जो वे चाहती हैं और जो वे सोचती हैं, वही बेस्ट वे ऑफ लाइफ है. ज़िया भी उन्हीं में से एक थीं. जिस उम्र में उन्हें करियर पर फोकस करना था, उस उम्र में वह प्यार मोहब्बत में ज़्यादा इन्वॉल्व थीं. किसी भी रिलेशनशिप में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है. अति हमेशा बुरी होती है. उनकी यह चाहत कि सूरज हमेशा उनके इर्द-गिर्द रहें, उनका फोन उठाएं. उनकी जासूसी करना कि कब कितने बजे वह किससे मिलने वाले हैं. इन सारी बातों से यह साफ़ हो जाता है कि वह सूरज को लेकर ओवर पोजेसिव, ओवर इमोशनल और ओवर डिमांडिंग थीं. यह किसी रिश्ते की ख़राब शुरुआत भर है. यह तो हम सभी जानते हैं कि इंडस्ट्री में सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल काम है. लोगों से मिलना-जुलना, अच्छा पीआर होना, आज के प्रोफेशन की डिमांड है और ख़ासतौर पर इंडस्ट्री में तो इसके बिना काम ही नहीं चलता! ऐसे में यह कैसे संभव था कि सूरज अपना काम छोड़ कर उनके इर्द-गिर्द घूमते रहते और उनके हर डिमांड को पूरा करते! प्यार का मतलब यह तो नहीं कि ख़ुद को बर्बाद कर लिया जाए, या जिसे हम प्यार करते हैं, उसे बर्बाद कर दें. ज़िया और सूरज के एक साल के प्यार में लड़ाई-झगड़े, धोखा, शक़ अबॉर्शन सबकुछ था. ज़िया अपने लेटर में लिखती हैं कि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा. यहां एक सवाल यह भी उठता है कि जब उन्हें लगता था कि वह एक लड़की हैं और उनके पास खोने के लिए कुछ है, फिर वह उस रिश्ते में इतना आगे तक क्यों गईं? उन्होंने प्यार को सबकुछ मान लिया. यह जानते हुए कि सूरज के सामने अभी सबसे बड़ी प्रायोरिटी उनका करियर है, फिर एक ऐसे लड़के से रिश्ता क्यों जोड़ लिया, जो किसी मुक़ाम पर नहीं था. झगड़े उस दिन से पहले भी सूरज और ज़िया के बीच हुए थे, लेकिन उस दिन जिया ने शराब पी थी. नशा, अविश्वास और अत्यधिक गुस्से में आकर ज़िया ने अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर ली. शायद ज़िंदा रहतीं और सबकुछ ठीक करने की कोशिश करतीं, तो सब ठीक हो भी जाता और नहीं भी होता, तो सूरज से अलग एक नई ज़िंदगी की शुरुआत तो कर ही सकती थीं. हम अनुभव लेकर पैदा नहीं होते. हम इंसान हैं, भगवान नहीं, ग़लतियां तो होती हैं. ज़िया और सूरज एक-दूसरे से प्यार करते थे, उनके इंटिमेट रिलेशन थे और वे इस स्थिति में नहीं थे कि बच्चे को जन्म दे पाते या उसकी परवरिश कर पाते. जिया ने अबॉर्शन करा लिया, तो ऐसा नहीं था कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी या वह दुबारा मां नहीं बन सकती थीं. अबॉर्शन या उनके बीच लड़ाई-झगड़े होते थे, इन वजहों से खुदकुशी करना हरगिज सही नहीं माना जा सकता.

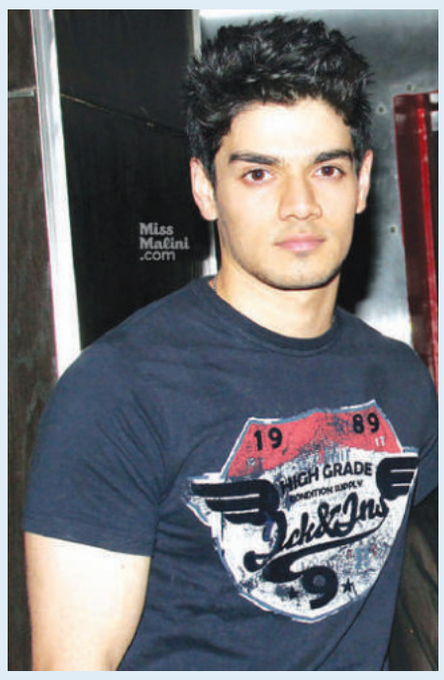

हादसों से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती. समझदार इंसान वही है, जो ग़लतियों से सीखे और उन्हें न दोहराए. किसी शायर ने ठीक ही कहा है...और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा. ऐसे लोग, जो प्यार में जान देने की बात सोचते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि किसी एक के लिए ज़िंदगी को ख़त्म नहीं किया जा सकता. ऐसे लाखों-करोड़ों लोग इस दुनिया में हैं, जिन्हें विरासत में कुछ नहीं मिला. उन्होंने संघर्ष किया, जीवन के कड़वे अनुभवों से सीखा और समाज में एक मिसाल क़ायम की. ■

feedback@chauthiduniya.com

प्रभु देवा का टपोरी डांस

वांटेड और राउडी राठौर जैसी हिट फिल्में दे चुके प्रभु देवा की अगली फिल्म है रमइया वस्तावइया. इस फिल्म में श्रुति हासन और गिरीश कुमार लीड रोल में हैं. यह एक म्यूजिकल हिट फिल्म है. एक न्यू कमर को फिल्म में लेने के बारे में प्रभु कहते हैं कि उन्हें गिरीश कुमार पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने यह फिल्म बनाई. साथ ही वह यह कहते हैं कि बॉलीवुड में न्यू कमर्स को अपनी फिल्मों के जरिये ब्रेक देने के लिए वह हमेशा तैयार रहते हैं. हालांकि किसी भी नए एक्टर को लॉन्च करते समय काफी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है. अपनी फिल्मों के नाम के बारे में प्रभु कहते हैं कि वॉन्टेड का नाम बोनी कपूर की देन है, जबकि राउडी राठौर संजय लीला भंसाली की, लेकिन रमइया वस्तावइया का टाइटल मैंने खुद सिलेक्ट किया. हमारे पास कई सारे ऑप्शन थे, जिनमें प्यार, इश्क वगैरह शामिल हैं, लेकिन अचानक किसी ने रमइया वस्तावइया टाइटल बताया. यह बहुत फेमस गाना भी है. मैंने इसे ही पसंद किया. दूसरी एक वजह यह भी है कि फिल्म के हीरो का नाम है राम. और रमइया वस्तावइया का मतलब है कि राम तुम कब आओगे. तो हमने इसे ही फाइनल किया. फिल्म के हीरो गिरीश के बारे में वह कहते हैं कि जब मैंने फिल्म पर काम करना शुरू किया, तब उसे ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसके साथ काम करना मेरे लिए अच्छा अनुभव रहा. प्रभु कहते हैं कि इस फिल्म में आपको हर तरह का डांस देखने को मिलेगा. टपोरी डांस से लेकर ईस्टर्न डांस सब. ■

शादी से काम पर फर्क नहीं पड़ा: विद्या बालन

शादी के बाद अक्सर अभिनेत्रियां ब्रेक ले लेती हैं. पर विद्या बालन कहती हैं कि शादी करकेवह बेहद खुश हैं, क्योंकि इससे उनके काम पर कोई फर्क नहीं पड़ा है. पहले की तरह ही वह अपनी पसंद की फिल्में और भूमिकाएं कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी. विद्या बालन इन दिनों अपनी फिल्म घनचक्कर को लेकर काफी उत्साहित हैं. फिल्म परिणीता से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद डर्टी पिक्चर्स, कहानी जैसी कुछ बेहतरीन फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड की स्थापित नायिकाओं में शामिल कर दिया है. वह कहती हैं कि निजी जिंदगी और काम केबीच सामंजस्य बिठाना मुश्किल नहीं हैं, क्योंकि उन्हें अपने पति का पूरा सहयोग मिलता है.

विद्या ने पिछले साल दिसंबर में डिजनी यूटीवी केमहाप्रबंधक सिद्धार्थ रॉय कपूर से विवाह किया. वह कहती हैं कि शादी के बाद सबसे अच्छी बात यह है कि दिन भर काम केलिए बाहर रहने केबाद आखिरकार शाम को आप घर पर साथ होते हैं. पति सिद्धार्थ की तारीफ करते हुए वह कहती हैं कि वह बहुत सहयोगी स्वभाव केहैं. उनकेसाथ रिश्ते में आने केबाद मैंने फिल्म द डर्टी पिक्चर में काम किया था. विद्या को नहीं लगता कि शादी केबाद उन्हें सोचकर भूमिकाएं चुननी पड़ेंगी. उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि शादी का मेरे काम पर कोई असर पड़ेगा. हम दोनों एक-दूसरे केकाम का सम्मान करते हैं. मैं अपने पसंद की भूमिकाएं कर सकती हूं और वह अपने पसंद की फिल्म बना सकते हैं. बस एक-दूसरे केपेशे केलिए सम्मान होना चाहिए. वह इन दिनों अपनी अगली फिल्म शादी के साइड इफेक्ट्स की शूटिंग में व्यस्त हैं.

विद्या कहती हैं कि कभी-कभी काम की अत्यधिक व्यस्तता केकारण वह और सिद्धार्थ ज्यादा समय साथ नहीं बिता पाते हैं. एक ही घर में रहने के बावजूद एक-दूसरे केसाथ नहीं रह पाते हैं. विद्या कहती हैं कि मैं 83 साल की उम्र तक अभिनय करना पसंद करूंगी. भगवान का शुक्र है कि अभिनय केक्षेत्र में मेरी बात बन गई. ■

विद्या ने पिछले साल दिसंबर में डिजनी यूटीवी के महाप्रबंधक सिद्धार्थ रॉय कपूर से विवाह किया. वह कहती हैं कि शादी के बाद सबसे अच्छी बात यह है कि दिन भर काम केलिए बाहर रहने के बाद आखिरकार शाम को आप घर पर साथ होते हैं.

जल्द ही शादी करेंगी किम

अभिनेत्री किम करदाशियां अब एक खूबसूरत बेटी की मां बन गई हैं. बेवर्ली हिल्स स्थित सेदर्स सिनाई मेडिकल सेंटर में बेबी को जन्म दिया. उनकी बेटी समय से पांच हफ्ते पहले ही पैदा हो गई. कहा जा रहा है कि उनकी बेटी बिल्कुल उन पर गई है.

गौरतलब है कि किम हमेशा सेक्सी फिगर को लेकर चर्चा में रहती हैं. एक बार मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने बताया था कि अक्सर लोग मेरे फिगर के बारे में पूछते हैं, तो मैं यह बताना चाहूंगी कि मैं डायटिंग बिल्कुल नहीं करती, बल्कि अपने आप को फिट रखने के लिए मैं सेक्स डाइट जरूर लेती हूं. यहां यह बता दें कि इससे पहले 32 वर्षीय किम का उनके बास्केटबॉल खिलाड़ी पति क्रिस हम्फ्रीज़ से विवाह होने के कुछ दिनों बाद ही अलगाव हो गया था. किम ने कहा कि बच्चे के जन्म के बाद वह अपने ब्वॉयफ्रेंड वेस्ट से जल्द ही शादी कर लेंगी. ■

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

08 जुलाई–14 जुलाई 2013

बिहार–झारखंड

एनडीए का हिस्सा बनेगी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी!

एनडीए और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बीच नये रिश्ते की शुरुआत के आसार प्रबल हैं. अगर ऐसा होता है, तो जदयू के अलग होने के बाद एनडीए काफी हद तक अपनी क्षतिपूर्ति कर लेगा, लेकिन यह कब संभव होगा?

चौथी दुनिया ब्यूरो

भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व बार-बार इस ओर इशारा कर रहा है कि जल्द ही एनडीए में दस-बारह नये सहयोगी जुड़ने वाले हैं. दरअसल, चौबीस दलों का एनडीए तीन दलों में सिमट कर रह गया है. इन्हीं आलोचनाओं का जवाब देने और लोकसभा चुनाव की मुकम्मल तैयारी के लिए भाजपा पूरे देश में एनडीए में कई नये सहयोगियों को जोड़ रही है. सूत्र बताते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद से मुकाबला करने के लिए भाजपा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को एनडीए में शामिल कराना चाहती है. दरअसल, इसका दो फ़ायदा भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को समझ में आ रहा है. पहला तो यह है कि जदयू व राजद से नाराज़ विधायक व सांसद, जो सीधे भाजपा को अप्रोच करने से हिचकते हैं, वे उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से एनडीए से जुड़ जाएंगे. जिन विधायकों और सांसदों के इलाके में मुस्लिम वोटों का पेंच फंस रहा है, उनके लिए उपेंद्र कुशवाहा का हाथ थामना ज़्यादा सुविधाजनक होगा. एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम को आधार बनाकर मिलने का मंच तैयार होगा और एनडीए का विस्तार कर लोकसभा चुनाव में बेहतर नतीजा लाने का प्रयास किया जाएगा. चूंकि उपेंद्र कुशवाहा और अरुण कुमार की जदयू व राजद में गहरी पैठ है, इसलिए इन दलों के नाराज़ लोग आसानी से अपनी बात इन नेताओं से कह सकते हैं. भाजपा नेतृत्व को दूसरा फ़ायदा यह समझ में आ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए में आ जाने से कुशवाहा समाज पूरी तरह साथ आ जाएगा और एक नया वोट बैंक एनडीए के खाते में जुट जाएगा. इसके अलावा, मध्य बिहार में अरुण कुमार की राजनीतिक उपयोगिता किसी से छिपी हुई नहीं है. संगठन के कामों के अलावा, चुनावी रणनीति बनाने में भी अरुण कुमार बेजोड़ हैं. ऐसे में अगर रालोसपा एनडीए का हिस्सा बन जाती है, तो फिर यह संदेश जाना शुरू हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष रहने के बावजूद नए साथी एनडीए से जूट रहे हैं. भाजपा और रालोसपा के नेता फिलहाल इस संभावित रिश्ते पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अंदरखाने इस पार्टी को एनडीए में शामिल कराने का खाका तैयार किया जा रहा है. अब सारा कुछ इसी खाके पर निर्भर करता है. अगर दोनों दलों को यह भा गया, तो फिर समझिए कि खिचड़ी पक गई, वरना दोनों दलों के नेता यह कहकर पल्ला झाड़ लेंगे कि हमने तो हांडी चढ़ाई ही नहीं थी, लेकिन दोनों दलों की इस रिश्ते को जोड़ने को लेकर जो तैयारी है, उसे देखने पर तो यही लगता है कि खिचड़ी पक जाएगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

नीतीश मुंह तो खोलें

गिरिराज सिंह कहते हैं कि अभी तो हमलोगों ने नीतीश के चेहरे से हल्का सा पर्दा ही उठाया है. मुंह खोलते ही हम पूरा पर्दा उठा देंगे. केवल मुसलमानों का वोट लेने के लिए जनादेश का अपमान करना कैसे ठीक कहा जा सकता है. ईमानदारी का जो लबादा नीतीश कुमार ने ओढ़ रखा है, जब उस पर से पर्दा हटेगा, तब वह क्या कहेंगे? इसलिए मुंह खोलने की हिम्मत उनमें नहीं है और भाजपाई गीदड़ भभकी से डरने वाले नहीं है...

सरोज सिंह

मैंने मुंह खोल दिया, तो हंगामा हो जाएगा. आमतौर पर नीतीश कुमार इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं करते, लेकिन लगता है, गठबंधन टूटने के बाद भाजपा द्वारा किए जा रहे तीखे हमलों से वह काफी बेचैन हैं. जवाब में वह कुछ कहना जरूर चाहते हैं, लेकिन कहते-कहते रुक जाते हैं. बस इतना कह कर निकल जाते हैं कि मैंने मुंह खोल दिया, तो हंगामा हो जाएगा. सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है, जिसे नीतीश कुमार कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं. भाजपा सांसद सी पी ठाकुर कहते हैं कि वह मुंह खोलें, उन्हें कौन रोक रहा है? भाजपा धमकियों से नहीं डरती. कुछ इसी तरह की बात पूर्व मंत्री गिरिराज सिंह भी कहते हैं. वह कहते हैं कि अभी तो हमने उनके चेहरे से हल्का सा पर्दा ही उठाया है, वह मुंह तो खोलें, हम पूरा पर्दा उठा देंगे. केवल मुसलमानों का वोट लेने के लिए जनादेश का अपमान करना कैसे ठीक कहा जा सकता है. ईमानदारी का जो लबादा नीतीश कुमार ने ओढ़ रखा है, जब उस पर से पर्दा हटेगा, तब वह क्या कहेंगे. इसलिए मुंह खोलने की हिम्मत उनमें नहीं है. भाजपाई गीदड़ भभकी से डरने वाले नहीं हैं.

दरअसल, नीतीश कुमार दुविधा में हैं. भाजपा के साथ सात साल तक सरकार चलाने के बाद वह भाजपाई मंत्रियों के कामकाज पर कैसे टिप्पणी कर सकते हैं. नीतीश ख़ुद सरकार के मुखिया थे, ऐसे में सरकार के कामकाज के ख़िलाफ़ वह कैसे बोल सकते हैं. देखा जाए, तो इस मामले में भाजपाई मंत्रियों पर कुछ कम बंधन है. इसकी पहली बानगी तो नंदकिशोर यादव ने विधानसभा में अपने पहले भाषण में ही दे दी. विधायक फंड के मसले पर उन्होंने नीतीश कुमार पर न सिर्फ़ हमला बोला, बल्कि यह भी कह दिया कि इस फंड को बंद करके आपने सारे विधायकों को बेईमान घोषित कर दिया है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैंने इसका विरोध किया और आपको चालीस मिनट लगा था, मुझे समझाने में. दरअसल, नीतीश की बैचेनी की वजह यहीं से शुरू होती है. सच्चाई तो यह है कि भाजपा के अलग होने से अब सरकार के अंदर की बात सामने आने लगी है. ध्यान देने की बात यह है कि भाजपा अब यह बात कह कर विधायकों की सहानुभूति बटोरने में लगी है कि पार्टी ने विधायक फंड बंद करने का विरोध किया था, लेकिन नीतीश कुमार के दबाव व गठबंधन धर्म निभाने के चलते उसे यह फ़ैसला मानना पड़ा. विधानसभा के अपने उसी भाषण में नंदकिशोर यादव ने यह कह कर नीतीश कुमार की आलोचना की कि आप तो मंत्रियों से कहीं ज़्यादा सचिवों की बात सुनते थे. इस बात को आगे बढ़ाते हुए शाहनवाज हुसैन कहते हैं कि नीतीश सरकार में भाजपाई मंत्रियों को काम करने की पूरी आज़ादी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भाजपा कोटे के मंत्रियों ने जबर्दस्त काम किया और बिहार को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया. राजनाथ सिंह भी जब पटना आए, तो उन्होंने नीतीश कुमार पर तीखे वार किए. जानकार बताते हैं कि आने वाले दिनों में भाजपा नेता सरकार के अंदर की कुछ ऐसी बातों का ख़ुलासा करेंगे, जिससे नीतीश कुमार की छवि धूमिल होगी. यही स्थिति नीतीश कुमार को परेशान करने वाली होगी. नीतीश कुमार अभी तक इस तरह के हमलों से बचते रहे हैं, लेकिन सात साल तक सरकार में शामिल मंत्री ही सरकार के अंदर की बातों का ख़ुलासा करेंगे, तो जनता तो यकीन करेगी ही. इसलिए नीतीश कुमार को यह कहना पड़ा कि मैंने मुंह खोल दिया, तो हंगामा हो जाएगा. सवाल यह उठता है कि अब वह भाजपा का कौन सा राज खोलना चाहते हैं, यह तो वहीं जानें, पर इतना तो तय है कि भाजपा ने अपना काम शुरू कर दिया है. भाजपा पर हमला बोलने के लिए फिलहाल जदयू के दूसरे लाइन के नेताओं को लगाया गया है. जदयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि नंदकिशोर यादव के आचरण के कारण सरकार व विभाग की छवि ख़राब हो रही थी. वह कहते हैं कि जदयू के लोग यह अच्छी तरह जान रहे हैं कि बहुत तेज हमला करने से नीतीश सरकार की ही छवि खराब होगी, क्योंकि कल तक यह नीतीश सरकार के ही मंत्री थे. इसलिए काफी संभलकर और संयम के साथ भाजपाइयों पर हमला करने की हिदायत दी गई है. जब तक इन बातों से काम चलेगा, चलाया जाएगा. लेकिन जब पानी सिर के ऊपर चला जाएगा, तो आख़िरकार नीतीश कुमार को मुंह खोलना ही होगा. ■

भाजपा के साथ सात साल तक सरकार चलाने के बाद वह भाजपाई मंत्रियों के कामकाज पर कैसे टिप्पणी कर सकते हैं. दरअसल, नीतीश खुद सरकार के मुखिया थे, ऐसे में सरकार के कामकाज के खिलाफ वह कैसे बोल सकते हैं. देखा जाए, तो इस मामले में भाजपाई मंत्रियों पर कुछ कम बंधन है. इसकी पहली बानगी तो नंदकिशोर यादव ने विधानसभा में अपने पहले भाषण में ही दे दी.

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

» एक नज़र «

लोकतंत्र में जनता मालिक

धनबाद के वार्ड नंबर 23 की पार्षद मिनाक्षी सिंह का मानना है कि नेताओं की ग़लत नीतियों के कारण झारखंड इन दिनों अस्थिरता का शिकार होकर रह गया है. आजसू नेता संदीप सिंह की धर्मपत्नी मिनाक्षी सिंह का कहना है कि प्रजातंत्र में जनता ही मालिक है, इसलिए राज्य में जनता का शासन होना बेहद ज़रूरी है. एमडीएम में लूट मची है और पोशाक वितरण में भारी धांधली हुई है. पुलिस के रवैये से ख़फ़ा मिनाक्षी सिंह का कहना है कि महिलाओं को समाज में उचित सम्मान मिलना चाहिए. उन्होंने दावा किया है कि वार्ड नंबर 23 के विकास के लिए हर संभव कार्य हो रहा है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वार्ड की जनता की सेवा के लिए मैं हमेशा तैयार हूं. मुझे आशा है कि जनता का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहेगा. – रणधीर झा

जनता को मिलना चाहिए हक़

वार्ड पार्षद इम्तियाज ख़ान झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने से बेहद ख़ुश हैं. धनबाद के वार्ड नंबर 20 के पार्षद इम्तियाज ख़ान का कहना है कि जनता को इसका हक़ मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि दाग़ियों को किसी भी क़ीमत पर टिकट नहीं मिलना चाहिए. ऐसे लोगों से ही झारखंड की छवि ख़राब हुई है. उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 20 में सभी मूलभूत सुविधाओं का ख़्याल रखा जा रहा है और वे जनता की सेवा के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध हैं. उनकी कोशिश यही रहेगी कि जनता की हर समस्या का समाधान हो. साथ ही वह यह भी चाहते हैं कि झारखंड में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन ख़त्म हो. – हैदर अली

राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सीतामढ़ी के पासवान चौक पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी का 44वां जन्मदिन मनाया गया. ज़िला कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष विमल शुक्ला की अध्यक्षता में साक्षरता दिवस के रूप में यह कार्यक्रम मनाया गया. मौक़े पर दलित बस्ती के बच्चों के बीच केक काटा गया. बच्चों के बीच मिठाई व पाठ्य सामग्री का वितरण भी किया गया. इस मौक़े पर कार्यक्रम संयोजक मनीष तिवारी, नगर अध्यक्ष सीमा गुप्ता, उपाध्यक्ष शीतलाम झा, सत्येंद्र कुमार तिवारी, मो. रमेश आलम अंसारी, मुकेश कुमार तिवारी, रामबाबू पासवान, विनोद पासवान, ललन पासवान, रवि पासवान, अंजारुल हक़ तौहिद, मो. शम्स शाहनवाज़, अनवर हुसैन व शिव शंकर शर्मा समेत अन्य नेता मौजूद थे.

सवर्ण मोर्चा सख़्त

बिहार प्रदेश सवर्ण मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सह सीतामढ़ी-शिवहर ज़िला प्रभारी राजीव कुमार मिश्र राजू ने कहा है कि अब किसी भी सूरत में सवर्णों की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने राष्ट्रीय चिंतन शिविर पर चर्चा करते हुए कहा कि देश की आज़ादी के बाद पूरे सवर्ण समाज के साथ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व प्रशासनिक स्तर पर भेदभाव व शोषण किया जा रहा है. सवर्ण समाज के उत्थान के लिए एक पैसे का भी आवंटन नहीं किए जाने पर न केवल उन्होंने चेताया, बल्कि यह भी कहा कि अब किसी भी सूरत में सवर्णों की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी. राजू ने लोगों से चिंतन-मनन कर पिछड़ते जा रहे सवर्ण समाज को बचाने और उन्हें आगे लाने में सहयोग की अपील की है. – ब्रजेश

अधिकारियों के ख़िलाफ़ आक्रोश

नगर पंचायत गोगरी जमालपुर के वार्ड नं. 20 में फैली गंदगी से निकलने वाली दुर्गंध से नगरवासियों का जीना हराम हो गया है, जिसके कारण नगरवासियों में नगर पंचायत अधिकारियों के ख़िलाफ़ आक्रोश व्याप्त है. स्थानीय नगरवासी अशोक शर्मा ने बताया कि नगर पंचायत कर्मियों के द्वारा वार्ड के दुर्गा मंदिर के पीछे फैले कूड़े-कचरे की सफ़ाई नहीं की जाती है, जिसके कारण यहां के लोगों को कचरे से निकलने वाली बदबू एवं बरसात में होने वाली बीमारी सता रही है. – उधव कुमार

खगड़िया लोकसभा क्षेत्र: जातिगत राजनीति का गणितीय खेल शुरू

अभी दिल्ली दूर है दोस्त...

जदयू-भाजपा गठबंधन टूटने के बाद खगड़िया लोकसभा का चुनावी माहौल बदला-बदला सा लगने लगा है. लोकसभा 2014 की सफलता को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा शुरू कर दिया है. अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जीत का सेहरा किसके सिर बंधता है.

दिनेश चंद्र यादव, कृष्णा कुमारी यादव, रेणु कुशवाहा, चंद्रमुखी देवी, सम्राट चौधरी, फैजल अहमद, रामानुज चौधरी, शशिभूषण प्रसाद, चौधरी महबूब अली कैसर

मनेंद्र कुमार

जदयू-भाजपा गठबंधन टूटने के बाद खगड़िया लोकसभा का चुनावी माहौल बदलना शुरू हो गया है. नये चेहरे गांव-गांव घूमने लगे हैं. वहीं पूर्व सांसद सह कांग्रेस नेता पप्पू यादव के कोर्ट से रिहा होन के बाद खगड़िया ही नहीं, बल्कि कोसी क्षेत्र का राजनीतिक परिदृश्य ही बदल गया है. मिशन 2014 की सफलता को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा शुरू कर दिया है, जबकि कई राजनीतिक दलों में उम्मीदवारी को लेकर अंतर्कलह शुरू हो गया है. खगड़िया लोकसभा में खगड़िया ज़िले की अलौली (सुरक्षित), खगड़िया, बेलदौर, परबत्ता, समस्तीपुर ज़िले की हसनपुर तथा सहरसा ज़िले की सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा है. सिर्फ़ परबत्ता विधानसभा को छोड़कर सभी सीटों पर जदयू का क़ब्ज़ा है. परबत्ता में राजद का क़ब्ज़ा है. इस गणितीय खेल में जदयू मजबूत ज़रूर दिखता है, लेकिन भाजपा-जदयू गठबंधन टूटने के बाद जदयू की राह अब आसान नहीं रह गई है. जातिगत मतदाता की बात की जाए, तो यह यादव, मुस्लिम तथा कुशवाहा बाहुल्य क्षेत्र है, जहां से इन जातियों का निर्णय अहम होता है. जदयू के वर्तमान सांसद दिनेश चंद्र यादव की राह इस बार आसान नहीं दिख रही है, क्योंकि यहां जदयू में अंदरूनी अंतर्कलह है. पूर्व विधायक रणवीर यादव की पत्नी जिला परिषद अध्यक्ष कृष्णा कुमारी यादव ने इस सीट पर अपनी दावेदारी ठोक दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से रणवीर यादव की नजदीकियां बढ़ जाने के कारण क़द और बढ़ गया है. इतना ही नही, उन्होंने चुनावी अभियान भी शुरू कर दिया है. यदि जदयू में इस प्रकार मारा-मारी की नौबत आई, तो उद्योग मंत्री रेणु कुशवाहा का नाम भी आ सकता है, जो खगड़िया की सांसद रह चुकी हैं. कुशवाहा जाति पर उनकी पकड़ भी मजबूत है, लेकिन उद्योग मंत्री रहते हुए खगड़िया में उद्योग नहीं लगने से क्षेत्र के मतदाताओं में नाराज़गी भी है. वहीं, सांसद दिनेश चंद्र यादव पर खगड़िया की बजाय सहरसा में ज़्यादा समय देने का आरोप लग रहा है. दरअसल, वह क्षेत्र के भ्रमण में भी पीछे रहे हैं. खगड़िया के विकास को लेकर बड़े-बड़े वादे किए गए, लेकिन सात वर्षों में हुए विकास ने इसकी पोल खोल कर रख दी है. मेडिकल, इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना, कोसी कॉलेज में पीजी, बीसीए सहित कई तकनीकी विषयों की पढ़ाई शुरू करने को लेकर कई बार आंदोलन भी हुए, लेकिन घोषणा के बावजूद कुछ भी नहीं हुआ. सदर अस्पताल में एएनएम की पढ़ाई भी शुरू नहीं हो सकी है. इसे लेकर क्षेत्र के लोगों में रोष है. इसलिए राजग गठबंधन टूटने के बाद जदयू की राह इन दिनों आसान नहीं दिखती है. वहीं, राजद से परबत्ता विधायक सह विधानसभा सचेतक राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे है, क्योंकि उनके पिता शकुनी चौधरी खगड़िया के सांसद रह चुके हैं. उन्होंने जदयू के कद्दावर नेता आरएन सिंह को विधानसभा चुनाव में पटकनी भी दी है.

वहीं, दूसरी ओर कुशवाहा समुदाय से आने के कारण उनकी दावेदारी भी मजबूत दिख रही है. यदि यह समुदाय गोलबंद हो जाए, तो उनकी स्थिति मजबूत हो सकती है. दूसरी तरफ़, भारतीय जनता पार्टी में कद्दावर नेता नहीं होने के कारण कई नेता टिकट की जुगत में लगे हुए हैं. पूर्व विधायक चंद्रमुखी देवी, भाजपा जिलाध्यक्ष रामानुज चौधरी एवं पूर्व ज़िला अध्यक्ष शशिभूषण प्रसाद टिकट के दावेदार माने जाते हैं. इसलिए उनकी दावेदारी मजबूत दिख रही है. वहीं, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री फ़ैजल अहमद ने भी अपनी दावेदारी को लेकर पत्ता खोल दिया है और क्षेत्र में भ्रमण शुरू कर दिया है. इस प्रकार भाजपा में भी टिकटों को लेकर राजनीतिक खेल शुरू हो गया है. भाजपा का कई वर्षों से खगड़िया में जनाधार खिसकता नज़र आ रहा था, लेकिन गठबंधन टूटने के बाद कई नेता दावेदारी ठोकते दिख रहे हैं.

भाजपा अगड़ी-पिछड़ी तथा वैश्य मतदाताओं को गोलबंद करने की जुगत में हैं, लेकिन भाजपा के लिए यह कांटों भरी राह है. यदि अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री फ़ैज़ल अहमद मुस्लिम मतदाताओं को गोलबंद करने में सफल हुए, तो खगड़िया लोकसभा में कमल खिल सकता है. कांग्रेस की बात की जाए, तो उनका पत्ता साफ़ नहीं है. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी महबूब अली कैसर, पूर्व प्रदेश युवाध्यक्ष ललन कुमार यादव और पूर्व सांसद पप्पू यादव भी क्षेत्र में चर्चा का विषय बने हुए हैं. 2014 के लोकसभा मिशन में किस दल और किसके सिर पर ताज होगा, अंदाज़ा लगाना फिलहाल मुश्किल है. इतना तो तय है कि भाजपा-जदयू गठबंधन टूटने के बाद मुक़ाबला रोचक हो गया है. हालांकि दूसरी ओर जातिगत राजनीति का गणितीय खेल शुरू हो गया है. कई दलों के नेताओं ने गोलबंदी भी शुरू कर दी है.■

feedback@chauthiduniya.com

सिर्फ़ दिखावे के हैं जनता दरबार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार के मामले पिछले कई वर्षों से लंबित हैं. लोगों का आरोप है कि अधिकारी दरबार लगाते हैं, लेकिन समस्याओं का निपटारा नहीं करते. इससे पूरे जनता दरबार के औचित्य पर ही सवाल खड़ा हो गया है.

अवधेश शर्मा

जनता दरबार सरकारी स्तर पर पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लगाया जाता है, लेकिन जब पीड़ित ही न्याय के लिए भटकने लगें, तो जनता दरबार सिर्फ़ दिखावे के ही रह जाएंगे. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दरबार का तो कम से कम यही हाल है. अधिकारियों के यहां आवेदनों की फाइल मोटी होती जा रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश की खुलेआम अवहेलना की जा रही है. आश्चर्य की बात तो यह है कि 2011 के आवेदनों का निपटारा अभी तक नहीं हो पाया है. जानकारी के अनुसार, ज़िला कार्यक्रम पदाधिकारी बैरिया के कार्यालय में 4, नौतन, लौरिया, नरकटियागंज में 2-2, रामनगर और मझौलिया में 1-1 मामले लंबित हैं. बीडीओ नरकटियागंज के कार्यालय में 6 मामले, बीडीओ नौतन के कार्यालय में 5 मामले,

चनपटिया, बगहा-1 में 3-3, बेतिया, लौरिया में 2-2, बैरिया, योगापट्टी, सिकटा में 1-1, वरीय प्रभारी पदाधिकारी बैरिया में 18, चनपटिया में 14, नौतन में 10 मामले, लौरिया में 5, योगापट्टी में 4, भितहा, नरकटियागंज 3-3, गौनाहा में 2, रामनगर, मैनाटांड, पिपरासी 1-1, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बेतिया के कार्यालय में 1, अनुमंडल पदाधिकारी बगहा के कार्यालय में 3, अनुमंडल पदाधिकारी बेतिया सदर के कार्यालय में 2 मामले लंबित हैं. सवाल यह उठता है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार से संबंधित मामलों का निपटारा अधिकारी नहीं करते हैं, तो फिर अन्य राजनेताओं व डीएम-एसपी के जनता दरबार से संबंधित मामलों का कितना प्रतिशत निपटारा होता होगा, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता. आम लोग अपनी समस्याओं को लेकर पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी के कार्यालय का चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन निराशा ही हाथ लगती है. उधर, कांग्रेस के रवींद्र सिंह जनता दरबार के नाम पर पीड़ितों को केवल परेशान करने का आरोप सरकार पर लगाते हैं. वह कहते हैं कि सरकार का यह दरबार केवल दिखावा है. उच्चाधिकारी जनता के आवेदन को थाना, प्रखंड और अंचल कार्यालय को भेजते हैं, लेकिन उनके निर्देश ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं. आश्चर्य की बात तो यह है कि जिला पदाधिकारी अनुमंडल, प्रखंड एवं अंचलाधिकारी के साथ महीने भर में तीन-चार बैठकें करते हैं, पुलिस अधीक्षक भी पुलिस पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हैं, तब यह हाल है. लोगों का आरोप है कि जनता दरबार के लंबित मामलों की दिशा में कार्रवाई पर जोर नहीं दिया जाता. यही कारण है कि जनता दरबार के औचित्य पर सवाल खड़ा होने लगा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

इंतेज़ारुल हक़

भाजपा से अलग हुई जदयू की हालत चंपारण में कुछ ठीक नहीं है, गुटबाज़ी का शिकार होकर पार्टी यहां अपना वजूद तलाश रही है...

मोतिहारी

जदयू में पुराने नेताओं की क़द्र नहीं

बबन कुशवाहा, डॉ. तफज्जुल हुसैन, डॉ. उमेश चंद्रा, शिव प्रसाद शाह, अब्दुल हमीद

युवा जदयू के जिला उपाध्यक्ष डॉ. उमेश चंद्रा का आरोप तो काफी निराला है. वह पार्टी के जिलाध्यक्ष सिन्हा पर खुलेआम कार्यकर्ताओं को बेइज्जत करने का आरोप लगाते हुए कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऐसे लोगों को अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए, जिनसे पार्टी को नुकसान पहुंचे.

हाल ही में भाजपा से अलग हुई सत्ताधारी दल जदयू की हालत चंपारण में ठीक नहीं है. गुटबाजी का शिकार होकर वह अपना वजूद तलाश रही है. गुटबाजी के कारण पार्टी के पुराने कार्यकर्ता एक तरफ़ जहां हाशिये पर हैं, वहीं दूसरी ओर पार्टी की तमाम गतिविधियों से दूर होकर वे ख़ुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं. रात-दिन एक कर पार्टी के सिद्धांतों को आम लोगों तक पहुंचाने और तमाम गतिविधियों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेकर, पार्टी को कामयाब बनाने वाले ज़मीनी कार्यकर्ता उपेक्षित हैं. कार्यकर्ता अब पार्टी से दूरी बनाने पर विचार कर रहे हैं. जानकार बताते हैं कि यहां पुराने नेताओं की कोई कद्र नहीं होती. वे कहते हैं कि जिलाध्यक्ष प्रमोद सिन्हा पार्टी के कुछ ख़ास नेताओं तक ही सीमित रहते हैं, जिससे पार्टी को काफ़ी नुक़सान हो रहा है. उनके इस रवैये से आगामी चुनाव में पार्टी के वोट पर व्यापक असर पड़ सकता है. पूर्वी चंपारण में जदयू के पुराने नेताओं व कार्यकर्ताओं की एक लंबी लिस्ट है, जो कभी पार्टी के लिए लुकमान साबित हुआ करते थे और हर परिस्थिति में समर्पित रहते थे, लेकिन आज वे दरकिनार कर दिए गए हैं. ऐसी बात नहीं है कि आलाकमान को इसकी जानकारी नहीं है. दरअसल, आलाकमान सब जानते हुए भी अंजान है.

हालात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि युवा जदयू का प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता बनाये जाने पर अमरेंद्र सिन्हा को पार्टी के ज़िला कार्यालय में बुलाकर अभिनंदन किया गया और उन्हें फुल-मालाओं का हार पहनाकर जिलाध्यक्ष प्रमोद सिन्हा द्वारा सम्मानित किया गया, लेकिन पूर्व में पार्टी के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों को शुशोभित करने वाले पुराने नेताओ की ख़बर तक नहीं ली जाती. पार्टी की महत्वपूर्ण गतिविधियों से भी उन्हें दूर रखा जाता है. जदयू के पूर्व उपाध्यक्ष व जमीअतुल हवारीन के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल हमीद कैप्टन, जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक मो. औबेदुल्लाह, वरिष्ठ नेता ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, पूर्व विधायक अजीजूल हक, युवा जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष फैजल रहमान, मो. तमन्ना, बबन कुशवाहा, डॉ. तफज्जुल हुसैन, बुलेट सिन्हा, शिव प्रसाद साह समेत दर्जनों ऐसे नेता व कार्यकर्ता हैं जो जिलाध्यक्ष की इस रणनीति से काफ़ी चिंतित हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में आस्था व्यक्त करते हुए किसी तरह से समय काट रहे हैं. यही स्थिति रही तो महाराजगंज चुनाव की तरह मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग ऐजेंट भी जदयू को नहीं मिलेगा. इधर, जदयू के वरिष्ठ नेता ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव तो अध्यक्ष के मनोनयन को ही ग़लत क़रार देते हैं और बताते हैं कि ऐसे आदमी को जिलाध्यक्ष बनाया गया जिसे पार्टी के अधिकांश कार्यकर्ता पहचानते तक नहीं थे. उनका मानना है कि ज़मीनी लोगों से दूरी बनाने वाले जिलाध्यक्ष चमचमाती गाड़ी वालों तक ही सीमित रहते हैं. वहीं पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष व जीमयतुल हवारीन के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल हमीद कैप्टन, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष डॉ. तफज्जुल हुसैन पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रमोद सिन्हा पर केवल डिक्टेटरशिप चलाने का आरोप लगाते हुए कहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज को जदयू से दूर किया जा रहा है. वे कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने के लिए एक तरफ़ जहां लगातार प्रयास कर रहे हैं, वहीं पूर्वी चंपारण में ठीक इसके उलट हो रहा है. पुराने नेताओं को कोई तरजीह नहीं दी जाती है और उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है. दूसरी तरफ़ पार्टी के ही पुराने नेता व युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव बबन कुशवाहा का कहना है कि पार्टी कार्यालय में जिलाध्यक्ष सिन्हा ने किसी ख़ास नेता के लिए सम्मान समारोह कर पार्टी के पुराने नेताओं को अपमानित करने का काम किया है. अगर सम्मान करना ही था तो पूर्वी चंपारण के कई ऐसे नेता हैं, जो प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश सचिव व प्रदेश महासचिव के पद पर हैं, जिन्हें पहले सम्मानित किया जाना चाहिए. यहां किसी को बढ़ावा दिया जाता है तो किसी की खुलेआम उपेक्षा की जाती है. इधर, क़रीब 12 वर्षों से नीतीश कुमार का झंडा बुलंद करने वाले मोतिहारी प्रखंड के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष शिवप्रसाद साह का भी यही आरोप है. वे वर्तमान जिलाध्यक्ष सिन्हा पर अनेक गंभीर आरोप लगाते हैं. युवा जदयू के जिला उपाध्यक्ष डॉ. उमेश चंद्रा का आरोप तो काफ़ी निराला है. वे पार्टी के जिलाध्यक्ष सिन्हा पर खुलेआम कार्यकर्ताओं को बेइज्जत करने का आरोप लगाते हुए कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऐसे लोगों को अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए, जिनसे पार्टी को नुक़सान पहुंचे. उन्होंने खुले तौर पर मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत करने की बात कही है और वोटिंग के तहत ऐसे महत्वपूर्ण पद का चुनाव कराने की मांग की है, ताकि ज़मीनी सच्चाई सामने आ सके. कुल मिलाकर पूर्वी चंपारण में पुराने नेता हाशिए पर हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर न्याय के लिए भरोसा किए हुए हैं. इधर, जिलाध्यक्ष सिन्हा ने इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि पार्टी के सिद्धांतों के अनुसार ज़िला में जदयू आम जनता तक अपनी पकड़ बना रही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

क्या जदयू छोड़ेंगे फैजल रहमान!

युवा जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष फैजल रहमान समेत पार्टी के कई नेता जदयू से शीघ्र अपना रिश्ता तोड़ेगे और किसी दूसरे राजनीतिक दल का दामन थामेंगे. इसकी चर्चा भी राजनीतिक गलियारों में शुरू हो गई है. आगामी लोक सभा चुनाव में इससे पड़ने वाले असर की समीक्षा अब की जाने लगी है. जानकार बताते हैं कि 31 जुलाई, 2008 को जदयू से राजनीति में क़दम रखने वाले फैजल युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाये जाने के बाद से ही ख़ुद को काफ़ी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं. आलाकमान द्वारा इसके बाद से ही कोई ठोस जिम्मेदारी नही सौंपे जाने के कारण वह काफ़ी परेशान हैं. चर्चा यह भी है कि जदयू के ज़िम्मेदार नेताओं द्वारा जदयू की महत्वपूर्ण गतिविधियों से अलग रखने व कार्यक्रमों की विधिवत सूचना नहीं दिए जाने से भी फैजल कई महीनों से गुमनाम जीवन गुजार रहे हैं. दूसरी तरफ़ यह भी ख़बरें आ रही हैं कि लालू यादव से फैजल की बात जम गई है और आगामी लोक सभा चुनाव में बेतिया लोक सभा क्षेत्र से टिकट देने का वादा लालू ने उन्हें किया है. हालांकि फैजल ने अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है. पर अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर मुस्लिम वोटों से जदयू को हाथ धोना पड़ेगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारी नुक़सान का सामना करना पड़ेगा. यहां बताते चलें कि फैजल पूर्व राज्य सभा सांसद स्वर्गीय मोतिउर्रहमान के पुत्र हैं और अपने पिता की तरह मुस्लिम समाज पर अपना पकड़ रखने का दावा करते हैं. हालांकि उनका यह दावा कितना सही है, यह तो चुनाव में दिखने को मिलेगा, लेकिन पूरे देश में मुसलमानों के नेता के रूप में अपना छाप छोड़ने वाले स्वर्गीय मोतिउर्रहमान का पुत्र होने का लाभ मिलने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता. कूल मिलाकर चंपारण में चर्चाओं का बाज़ार काफ़ी गर्म है और राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे पर समीक्षा भी की जाने लगी है. ■

» एक नज़र «

भागवत कथा आयोजित

नगर पंचायत गोगरी, जमालपुर में सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया गया. कथा का उद्घाटन डीएसपी अशोक सिंह ने किया. उद्घाटन के अवसर पर सिंह ने कहा कि आस्था से जुड़े सभी कार्यों में अनुमंडल पुलिस भक्तों के साथ है. वहीं श्रीमद्भागवत कथा वाचक शंभूशरण महाराज ने उपस्थित श्रद्धालुओं को भगवान कृष्ण के लीला के बारे में बताते हुए कहा कि भागवत कथा के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण ने भक्तों को जीवन के पथ पर कर्म के अनुसार चलने का संदेश दिया है. इस अवसर पर सावित्री देवी, अर्चना देवी, कल्पना कुमारी, पूजा कुमारी, पवन कुमार, दीपक कुमार सहित दर्जनों भक्त उपस्थित थे.

पौधों का किया वितरण

अनुमंडल गोगरी के मथुरापुर गांव के लगभग 3 सौ किसानों के बीच मोहगनी एवं आम के पौधों का वितरण किया गया. पौधों का वितरण पायोनियर कंपनी के टीबीएल अभिजीत कुमार झा के नेतृत्व में किया गया. इस मौक़े पर झा ने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए ही किसानों के बीच पौधों का वितरण किया गया है. उन्होंने कहा कि कंपनी के द्वारा लगभग 2 हज़ार पौधों का वितरण किया जा चुका है. इस अवसर पर मुकेश चौधरी, अजय चौधरी, रमेश चंद्र झा, राजेंद्र हिमांशु, संजीव चौधरी सहित दर्जनों किसान उपस्थित थे. – उधव कुमार

शिक्षक नियोजन में फंसा पेंच

पूसा प्रखंड में चयनित शिक्षकों को 10 जून, 2013 को ही नियोजन पत्र मिल जाना चाहिए था, लेकिन निर्धारित समय सीमा के बीत जाने के बावजूद अबतक शिक्षकों को नियोजन पत्र नहीं मिल सका है. चयनित शिक्षकों ने बताया कि जिला मुख्यालय ने इस संदर्भ में सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली हैं. इसके बावजूद प्रखंड मुख्यालय द्वारा नियोजन पत्र नहीं बांटा जा रहा है.■ – श्याम कुमार

जय गुरु ! जय तारा !!
अंतराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भविष्यवक्ता एवं वाममार्गी तांत्रिक
चंदन शास्त्री
तंत्र सम्राट
(डबल गोल्ड मेडलिस्ट)
पता- पुराना राजागढ़ झरिया, धनबाद
Mob : 09835329295

नीतीश कुमार जिन्दाबाद, आरसीपी सिंह जिन्दाबाद, साबिर अली जिन्दाबाद
साबिर अली
आरसीपी सिंह
नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विधान सभा में बहुमत सिद्ध किये जाने पर हार्दिक बधाई
निवेदक
साजिद रजा
जिलाध्यक्ष, युवा जदयू

नीतीश ही बेस्ट

डॉ. श्याम नारायण प्रसाद

बिहारशरीफ के जाने माने चिकित्सक डॉ श्याम नारायण का मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को काफी पहले ही भाजपा से अपना रिश्ता तोड़ लेना चाहिए। वह कहते हैं कि बिहार नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रगति की राह पर है और अब इस काम में और भी तेजी आएगी। डॉ श्याम नारायण कहते हैं कि बिहार के लोग मेहनती हैं और नीतीश कुमार जैसे नेता के मिल जाने से बिहारियों की प्रतिभा रोजाना निखर रही है। उनके अनुसार नीतीश कुमार ने विकास का जो मॉडल पेश किया है वही इस प्रदेश के लिए उपयुक्त है। कोई दूसरा मॉडल यहां प्रभावी नहीं हो सकता। नीतीश कुमार ने अपने मॉडल में समावेशी विकास का रास्ता दिखलाया है। बिहार जैसे राज्य के लिए यही सही रास्ता है। उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त नीतीश कुमार के लिए और भी चुनौतियों भरा है क्योंकि विकास की प्रतियोगिता में बिहार को सबसे आगे ले जाने का काम उनके जिम्मे हैं। डॉ श्याम नारायण को भरोसा है नीतीश कुमार इस काम में पूरी तरह सफल होंगे। ■ शिवानी

ariskon Pharma Pvt.Ltd.
AREX
Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.
MENSOSET
Her. Tonic with Ashoka 1800 mg
MUSTAL
Levocetirzine Hydrochloride Montelukast Sodium Tab.
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

संक्षिप्त ख़बरें

सरकार से परेशान हैं जनता

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री फैसल अहमद ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहें, क्योंकि देश में कभी भी चुनाव हो सकता है. केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि जब भी केंद्र में कांग्रेस सरकार आई है, भ्रष्टाचार, महंगाई और तानाशाही को बढ़ावा मिला है. फैजल ने कहा कि देश की जनता इस सरकार से तंग आ चुकी है. देश में एक ही विकल्प है भाजपा, जो देश की जनता के हित की सोचती है और सदन में जनता की आवाज़ बुलंद करती है. – गीता कुमार

राशि का भुगतान नहीं हुआ

समस्तीपुर ज़िले के पूसा प्रखंड के तेरह पंचायतों में पिछले वर्ष से कन्या विवाह योजना की राशि का वितरण नहीं किए जाने का मामला प्रकाश में आया है. सूत्रों की मानें, तो कन्या विवाह योजना के लाभुकों का पत्र पिछले कई माह से स्वीकृत होकर प्रखंड मुख्यालय में पड़ा हुआ है, दरअसल, इससे संबंधित अधिकारियों की उदासीनता के कारण अब तक लाभुकों को कन्या विवाह योजना राशि के पांच-पांच हज़ार रुपये का चेक नहीं मिल पाया है, इसलिए लाभुकों में चिंता है. गौरतलब है कि राशि स्वीकृत होने के बाद अविलंब शिविर लगाकर चेक वितरण का प्रावधान किया जाएगा. – श्याम कुमार

आजसू प्रभारी का दौरा

चतरा विधानसभा के आजसू प्रभारी अशोक गहलोत ने इन दिनों अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है. अशोक गहलोत ने चतरा विधानसभा के प्रतापपुर कुंदा, कान्हचट्टी, सदर प्रखंड चतरा एवं हंटरगंज का दौरा किया है. बुथ पर 25-25 कार्यकर्ताओं का सक्रिय सदस्य बनाया जा रहा है. पच्चीस सदस्यीय टीम में पांच छात्र, पांच महिला, पांच किसान एवं इतने ही प्रबुद्ध व्यक्तित्व शामिल हैं. आजसू पार्टी में ज़्यादातर कार्यकर्ता राजद से टूट कर आ रहे हैं. – अमरेन्द्र सिंह

सपा का धरना

मुंगेर ज़िले में किसानों की उपेक्षा, विद्युत, पेयजल संकट, बढ़ते अपराध और पुलिसिया जुल्म को लेकर एक धरना का आयोजन किया गया. यह आयोजन ज़िला मुख्यालय के शहीद स्मारक पर मुंगेर ज़िला समाजवादी पार्टी के तत्वावधान में ज़िला अध्यक्ष पप्पू यादव के नेतृत्व में किया गया. धरना के उपरांत पार्टी का एक शिष्टमंडल ज़िला पदाधिकारी से मिला और राज्यपाल के नाम 8 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन सौंपा. – शिवानी

कोचिंग संचालक पर मारपीट का आरोप

समस्तीपुर स्थित गुरुकुल कोचिंग संस्थान के निदेशक द्वारा एक छात्र को बुरी तरह पीटे जाने का मामला सामने आया है. सदर डीएसपी राजेश कुमार ने तेरह दिन बीत जाने के बाद निदेशक सौरभ चौधरी को इस मामले में गिरफ्तारी के आदेश दे दिए हैं. डीएसपी ने बताया कि सौरभ ने संस्थान में पढ़ रहे रजनीश कुमार को बेरहमी से पीटा और उसका मोबाइल अपने पास रख लिया था. घटना को लेकर पीड़ित छात्र रजनीश कुमार ने कोचिंग संचालक को गिरफ्तार करने की मांग की. संचालक के ख़िलाफ़ कांड संख्या 145/13 में दफा 341 / 323 / 324 / 387 / 504 /506/34 का मामला दर्ज कर लिया गया है. घटना की निंदा कई छात्र संगठनों के नेताओं ने की है और कई जगह धरना-प्रदर्शन और पुतले भी जलाए गए हैं. उनौस के जिलाध्यक्ष सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, जदयू के अकबर रजा, अरविन्द आनंद, सैयद अहमद, रूपेश कुमार झा, अखतरूल रहमान सिद्दीकी, सहित सैकड़ों छात्र नेताओं ने पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए एसपी वरुण कुमार सिन्हा, डीएसपी राजेश कुमार एसडीओ सुधीर कुमार, आईजी, डीआईजी सहित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आवेदन दिया है और कोचिंग के निदेशक सौरभ चौधरी को गिरफ्तार कर कोचिंग को अविलंब बंद कराने की मांग की है.■ – प्रमोद प्रभाकर

बेगूसराय

फर्जी इंदिरा आवास आवंटन

इंदिरा आवास के पैसों को हड़पने के लिए महिलाओं ने 6 से 14 वर्ष के नाबालिग बच्चों से शादी रचाई. अधिकारी और दलाल भी सरकारी पैसों की लूट में हैं शामिल.

कुमार मनीष

जनता सरकार को उसके घोटालों के लिए कोसती है, लेकिन जब वह खुद घोटाला करने लगे, तब क्या होगा. इंदिरा आवास योजना से मिलने वाले पैसे के मामले में कुछ इसी तरह का मामला सामने आया है. इस योजना के पैसे की लालच में शाहपुर और मसूदनपुर गांव की 25 से 30 साल की महिलाओं ने नाबालिगों से शादी रचा ली. आश्चर्य की बात तो यह है कि इन बच्चों की उम्र 6 से 14 वर्ष है. इन नाबालिगों को न तो शादी की और न ही इंदिरा आवास की समझ है. मामले का खुलासा तब हुआ, जब बेगूसराय जिले के भवानंदपुर पंचायत में इसकी शिकायत डीएम के जनता दरबार में की गई. शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डीएम मनोज कुमार ने एनईपी निदेशक अफजारुल रहमान के नेतृत्व में जांच दल का गठन कर मामले की जांच कराई.

जांच के क्रम में जब लाभुकों के बीपीएल कार्ड की जांच की गई, तो कई दिलचस्प खुलासे हुए. गौरतलब है कि बीपीएल कार्ड में कार्डधारी के पिता का नाम दर्ज होता है. जांच में लाभुक शीला देवी, लीला देवी, रीना देवी और बबीता देवी द्वारा योजना का नाजायज फायदा उठाने का पता चला है. आश्चर्य की बात तो यह है कि मध्य विद्यालय मसूदनपुर के कक्षा नौंवी के छात्र दिलीप राम, अष्ठम वर्ग के छात्र जितेंद्र राम, प्राथमिक विद्यालय बैरा शाहपुर के पांचवी के छात्र रौशन राम और चौथी वर्ग के छात्र सचिन राम को फर्जी पति बना कर इन महिलाओं ने प्रति लाभुक 70 हजार रुपये भी प्राप्त कर लिया. लूट का आलम देखिए कि महिलाओं ने इस राशि से 2 कमरे का मकान भी बनवा लिया है. अब जिला प्रशासन इस मकान को जरूरतमंदों को देने का मन बना रही है. इन महिलाओं ने अधिकारियों को लिखित स्वीकारोक्ति दी है, जिसमें उन्होंने नाबालिगों से शादी की बात स्वीकारी है. ताज्जुब की बात तो यह है कि इन महिलाओं के असली पति प्रवासी मजदूर के रूप में पंजाब और दिल्ली समेत अन्य महानगरों में रहते हैं. गौरतलब है कि भवानंदपुर पंचायत में 88 अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को इंदिरा आवास की स्वीकृति दी गई थी, जिनमें फर्जी आवंटन की शिकायत डीएम से की गई थी. प्रारंभिक जांच में ऐसे छह नाबालिगों को इंदिरा आवास आवंटित किए जाने की बात सामने आई है. योजना में दलालों, भ्रष्ट अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की भी खूब चांदी है. इन मामलों में जांच के दौरान छह में से चार मामलों में जांच दल ने शिकायत सही पाई है. यह रिपोर्ट एनईपी निदेशक ने जनशिकायत कोषांग को सौंप दी है. जनशिकायत कोषांग के प्रभारी सुधीर कुमार झा ने इस संबंध में स्थानीय बीडीओ अशोक कुमार सिंह, स्थानीय मुखिया, पंचायत सचिव, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी पर प्राथमिकी दर्ज कर विभागीय कार्रवाई की अनुसंशा की है. दूसरी ओर, बीडीओ अशोक कुमार सिंह ने मामले का खुलासा होते ही अपने बचाव में 3 लाभुक समेत 10 लोगों पर बलिया थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी. चार लाभुकों से राशि वापसी की बात भी कही जा रही है. यह तो एक पंचायत की बानगी भर है. जिले भर के विभिन्न प्रखंडों में हुए इंदिरा आवास के आवंटन की जांच की जाए, तो इस तरह के कई और मामले सामने आएंगे. डीएम मनोज कुमार ने बताया है कि जांच रिपोर्ट में जो लोग दोषी हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.■

feedback@chauthiduniya.com

बालमुकुन्द
डायमंड टी.एम.टी.
IS:1786
इसमें है दम
यही है नम्बर 1
Website : www.balmukundtmt.com
Email : bconcast@yahoo.com
भारत में पहली बार Q & Q कर हर बंडल के साथ

Enjoy with Nature
MOULDED FURNITURE
NATURE
WINNER OF NATIONAL AWARD
1 YEAR GUARANTY
Contact : 9386595926, 9334115955

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

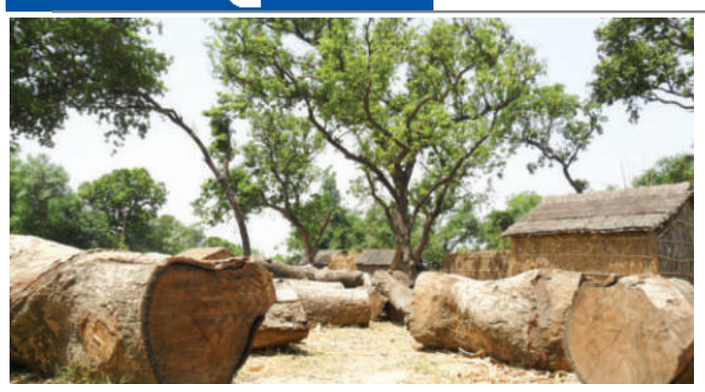

बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके गोपाल नारायण सिंह कहते हैं कि जो बात मैं पहले दिन से कह रहा था, वह अंततः सच हो ही गई, लेकिन फिर भी भाजपा में हर संकट से उबरने की ताक़त है.

लक्ष्मणा नदी को बचाने की मुहिम तेज

क्या सफ़ल हो पाएंगे शशि?

लक्ष्मणा नदी को बचाने के अब तक के प्रयास फेल हो चुके हैं, लेकिन इस बार आंदोलन की कमान हमेशा ज़िले की जनसमस्या को लेकर संघर्षशील रहे संघर्ष यात्रा के अध्यक्ष शशि शेखर ने थामी है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या वे लक्ष्मणा नदी को बचा पाएंगे?

वाल्मीकि कुमार

लक्ष्मणा नदी को बचाने की मुहिम अब तेज हो गई है. हालांकि इस बार भी वही पुरानी डफली पर नया राग वाली बात दुहराई जा रही है. दरअसल, इस बार भी आंदोलन के लिए वही पुराने जाने-पहचाने चेहरे नजर आ रहे हैं. गौरतलब है कि हर बार आंदोलन का एक ही लक्ष्य होता है, लेकिन आंदोलन का संचालन करने वाले चेहरे बदलते रहते हैं. इस बार इस आंदोलन की कमान हमेशा ज़िले में जनसमस्या को लेकर संघर्षशील रहे संघर्ष यात्रा के अध्यक्ष शशि शेखर ने थामी है. वैसे, इससे पूर्व शहर के प्रबुद्ध लोगों की सहमति से लोक चेतना समिति ने भी नदी को लेकर आंदोलन की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका. उनके बाद राजद नेत्री शाहीन परवीन ने भी शहर में नदी आंदोलन को तेज कर दिया, लेकिन प्रशासनिक आश्वासन की महज एक ही छुट्टी ने उनके आंदोलन का जनाजा निकाल दिया. इस दौरान काला दिवस मनाने से लेकर आत्मदाह की घोषणा तक की गई. पूर्व की तरह प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में जल्द ही समस्या का निदान निकाल लेने का भरोसा देकर आंदोलन को दिशाहीन बना दिया गया. नतीजतन, मामला ज्यों का त्यों रह गया. हाल के वर्षों में सामाजिक संस्था अमन परिषद ने विजयादशमी के मौक़े पर नदी में रावण दहन कार्यक्रम आयोजित कर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की तंद्रा तोड़ने की कोशिश की. इसके बाद जिले के किसान और आम-अवाम के लिए प्राणदायिनी लक्ष्मणा नदी के अस्तित्व रक्षा की दिशा में अब तक कोई पहल नजर नहीं आ रही है. इस बार एक अच्छी बात यह भी हुई कि संघर्ष यात्रा के अध्यक्ष शशि शेखर ने इस बार लक्ष्मणा के साथ ही अघवारा समूह की नदियों को भी अपने आंदोलन का हिस्सा बनाया है.

एक ओर अघवारा समूह की नदियों पर हो रहे तटबंध निर्माण कार्य को घातक करार देते हुए अविलंब निर्माण बंद कराने की मांग की जा रही है, तो दूसरी ओर लक्ष्मणा नदी के अवरुद्ध जल प्रवाह को शीघ्र चालू कराने की मांग भी शामिल है. केवल यही नहीं, शहर के लखनदेई पुल पर आयोजित दो दिवसीय सत्याग्रह के दौरान बागमती प्रमंडल संख्या-1 के कार्यपालक अभियंता भीम शंकर राय को बर्खास्त करने तक की मांग की गई. आपको बता दें कि लक्ष्मणा नदी के अस्तित्व को लेकर चौथी दुनिया में 13 से 19 मई के अंक में पृष्ठ संख्या-20 पर नदी की दुदर्शा से आहत हैं लोग शीर्षक से खबर प्रकाशित हुई थी. इस रिपोर्ट में नदी के सवाल पर विधान सभा और विधान परिषद के सत्र में हुई चर्चा का विशेष उल्लेख भी किया गया था. राज्य सरकार अपनी सत्ता बचाने की फिराक में लगी है, वहीं जनप्रतिनिधि भी अपने ही हिसाब किताब में लगे हैं. सरकारी फरमान के बाद भी अब तक न तो नदी की धारा में हो रहे भवन निर्माण कार्य पर रोक लगाया जा सका है और न ही नदी की धारा को अतिक्रमणकारियों के चंगुल से बचाने के लिए कोई अभियान शुरू किया जा सका है. हम डरा नहीं रहे, लेकिन इस लापरवाही का

लक्ष्मणा नदी के अस्तित्व को लेकर चौथी दुनिया में 13 से 19 मई के अंक में पृष्ठ संख्या-20 पर, नदी की दुदर्शा से आहत हैं लोग, शीर्षक से खबर प्रकाशित हुई थी. इस रिपोर्ट में नदी के सवाल पर विधानसभा और विधान परिषद के सत्र में हुई चर्चा का विशेष उल्लेख भी किया गया था. राज्य सरकार अपनी सत्ता बचाने की फिराक में लगी है, वहीं जनप्रतिनिधि भी अपने ही हिसाब किताब में लगे हैं.

खामियाजा जिलावासियों को एक न एक दिन भुगतना ही पड़ेगा. यहां के लोगों को पिछले साल की तबाही अभी भी याद है, जब नदी किनारे निर्मित कई कच्चे-पक्के मकान ध्वस्त हो गए थे. यहां प्रशासनिक उदासीनता का आलम यह है कि संभावित परेशानी को लेकर इस दिशा में अब तक किसी भी प्रकार की पहल नहीं की गई है. बरसात का समय करीब आने के साथ ही तटबंधों के सुदृढ़ीकरण की कवायद होती रही है, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि सीतामढ़ी शहर को सुरक्षित रखने में अहम साबित होने वाले रिंग बांध की पिछले कई सालों से मरम्मत नहीं हुई. अगर एक बार भी नदी की धारा में बाढ़ का पानी आ गया, तो शहर में बाढ़ आ जाएगा.

फिलहाल, बरसात के मौसम के साथ ही शुरू हुए नदी का आंदोलन इस बार अपने मुकाम तक पहुंच पाता है या नहीं, या फिर प्यास लगने पर कुंए की खुदाई जैसा ही साबित होकर रहेगा, यह कहना मुश्किल है. आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले अमन परिषद के मनोज कुमार शक्ति की मानें, तो नदी के अस्तित्व की रक्षा के सवाल पर स्थानीय सांसद अर्जुन राय ने पूर्व के वर्षों में ही घोषणा की थी. यह भी भरोसा दिलाने से परहेज नहीं किया था कि लक्ष्मणा नदी की उडाही को लेकर 4 करोड़ रुपये उपलब्ध करा दिया गया है. सच्चाई यह है कि अब तक नदी के धारा को सही दिशा में प्रवाहित कराने को लेकर कुछ भी नहीं किया जा सका है. यहां के लोगों को कोई भी विकल्प नजर नहीं आ रहा है. हैरानी इस बात की है कि इस गंभीर समस्या को लेकर स्थानीय लोग भी गंभीर नही हैं, जो सरकार व प्रशासनिक तंत्र की तंद्रा भंग कर सकें. स्थानीय भाजपा विधायक सुनील कुमार पिंटू भी राज्य सरकार में एक किसी ओहदे पद पर रहते भी इस दिशा में कुछ भी नहीं कर पाए. ■

feedback@chauthiduniya.com

इंटरव्यू

जीरो पर आउट होंगे नीतीश: गोपाल नारायण सिंह

गोपाल नारायण सिंह

सरोज सिंह

जदयू के साथ मिलकर सरकार बनाने का अगर किसी एक शख्स ने पहले दिन से विरोध किया था, तो उसका नाम है गोपाल नारायण सिंह. बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके गोपाल नारायण सिंह कहते हैं कि जो बात मैं पहले दिन से कह रहा था, वह अंतत: सच हो ही गई, लेकिन फिर भी भाजपा में हर संकट से उबरने की ताक़त है. सारे कार्यकर्ता खुश हैं और आगामी लोकसभा चुनाव में जनता नीतीश कुमार को जीरो पर आउट कर देगी. प्रस्तुत है, उनसे बातचीत के कुछ ख़ास अंश.

जदयू के साथ गठबंधन टूटने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं. भाजपा के लिए यह कितना सही फैसला है?

- सवाल मेरे महसूस करने का नहीं है, बल्कि सवाल भरोसे का है. अगर दोस्ती में भरोसा ही नहीं रहेगा, तो फिर ऐसी दोस्ती किस काम की! मैंने गठबंधन के समय ही छह बातों पर नीतीश कुमार की रजामंदी मांगी थी, पर ऐसा नहीं हो पाया. मैंने दिल्ली के नेताओं को भी उस समय बता दिया था कि बिना उन छह बातों पर रजामंदी लिए गठबंधन करना ठीक नहीं रहेगा, पर उस समय मेरी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया. हालांकि आज रिजल्ट सबके सामने है. इस विश्वासघात को पार्टी कार्यकर्ता कैसे भूल सकते हैं. भले ही कुछ नेता इस घटना से उदास हैं, पर पूरी पार्टी और बिहार के कार्यकर्ता बेहद खुश और उत्साह में हैं. संघर्ष का प्रोगाम तैयार हो गया है. आने वाले दिनों में नीतीश सरकार के खिलाफ निर्णायक संघर्ष शुरू हो जाएगा.

क्या आप यह महसूस करते हैं कि गठबंधन के टूटने से भाजपा भी नुकसान में रहेगी और चुनाव परिणाम प्रभावित होंगे?

-आपलोग गलत सोच रहे हैं. यह तय है कि गठबंधन टूटने से जदयू रसातल में जाएगी, पर भाजपा को नुकसान होगा, यह कहना गलत होगा. ऐसा इसलिए कि भाजपा संगठन वाली पार्टी है. बूथ के स्तर पर भाजपा के कार्यकर्ता अपना काम बखूबी करते हैं. दूसरे दल भले ही कोई दावा करें, पर हक़ीक़त में संगठन के स्तर पर वे बेहद कमजोर हैं. भाजपा पूरे सूबे में फैले अपने कर्मठ और पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं के बल पर लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करेगी और नरेंद्र मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत के निर्माण के सपने को भी पूरा करेगी.

आप हमेशा आरोप लगाते रहे हैं कि राजनीतिक साजिश के तहत उन पर केस-मुकदमे लादे जा रहे हैं. भाजपा अब सरकार में नहीं है. ऐसे में इस तरह की क्या कार्रवाई हो सकती है?

-मैं किसी से नहीं डरता नहीं, क्योंकि मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं है. राजनीति और व्यवसाय दोनों ही क्षेत्रों में मैंने हमेशा सही रास्ते को ही चुना है. कुछ लोग ईर्ष्यावश इसमें बुराइयां खोजने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आखिरकार ऐसे लोगों को निराशा ही हाथ लगेगी. सरकार में रहने या नहीं रहने से कुछ अंतर नहीं पड़ता है. किसी में हिम्मत है, तो मुझे छेड़ कर देखे.

भाजपा के अंदर भी बहुत सारी दिक्कतें हैं. कुछ नेता सार्वजनिक तौर पर मतभेदों के बारे में बता भी चुके हैं. ऐसे में नीतीश सरकार के खिलाफ लड़ाई आप कैसे लड़ेंगे?

-देखिए, भाजपा एक बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, इसलिए कुछ मसलों पर अलग-अलग राय होना स्वाभाविक है. पार्टी में सभी की बातें सुनी जाती हैं और एक बार किसी बात पर फैसला हो गया, तो सारे लोग पुरानी बात भूलकर लिए गए फैसले के साथ हो जाते हैं. अभी पार्टी का एक मात्र मकसद है बिहार के लोगों के मान-सम्मान की रक्षा व सूबे का वास्तविक विकास. नीतीश कुमार ने जनादेश के साथ जो धोखा किया है, उसका जवाब जनता जरूर देगी. भाजपा जनता को नीतीश कुमार का असली चेहरा बताएगी.

नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए क्या भाजपा बिहार में दूसरे दलों का भी साथ लेगी?

-भाजपा के सारे कार्यकर्ता पूरे जोश में हैं और इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि विश्वासघातियों को इस बार चुनाव में मजा चखा देना है. इस रास्ते में अगर कोई साथ आता है, तो उनका स्वागत है. राजनीति में हर तरह के विकल्प खुले रहते हैं, लेकिन भाजपा कुर्सी के लिए कभी अपनी नीति और कार्यक्रमों से समझौता नहीं करेगी. पहले कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाएगा इसके बाद ही दूसरे के बारे में सोचा जाएगा.

नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाए जाने से बिहार में भाजपा को क्या फायदा मिलने वाला है?

-नरेंद्र मोदी में लोग दरअसल, अटल बिहारी वाजपेयी की छवि देख रहे हैं. खासकर बिहार की जनता में नरेंद्र मोदी को लेकर गजब का क्रेज है. हर जात-समुदाय व धर्म के लोग नरेंद्र भाई को आशा की नजर से देख रहे हैं. उनको लग रहा है कि भारत का गौरव व सम्मान अगर कोई शख्स वापस ला सकता है, तो उसका नाम नरेंद्र मोदी ही है. नरेंद्र भाई की यही लोकप्रियता कुछ नेता पचा नहीं पा रहे हैं और इसीलिए उनके बारे में अनाप-शनाप बोलते रहते हैं, लेकिन मेरा दावा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में जनता नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो रहे दुष्प्रचार का मुंहतोड़ जबाव देगी. केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनेगी.■

feedback@chauthiduniya.com